राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 5 अंक 44

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शनिवार, 24 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



दुनिया को दिखी जापान की धमक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : जब रात घिर आई थी तब टोक्यो का ओलिंपिक स्टेडियम दमक रहा था। वहां उठी धमक पूरे विश्व में सुनाई दे रही थी । टोक्यो के प्रतीक को प्रदर्शित करने के लिए 20 सेकेंड तक नीली और सफेद रंग की आतिशबाजी हुई, जिसे जापानी संस्कृति में शुभ माना जाता है। कोरोना महामारी के कारण एक साल देरी से शुक्रवार को 32वें ओलिंपिक का आगाज हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों के संघर्षों की कहानियों पर प्रस्तुतियां दी गईं। हालांकि इस दौरान स्टेडियम के बाहर प्रदर्शनकारी ओलिंपिक आयोजन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

ओलिंपिक मार्च पास्ट की शुरुआत हमेशा की तरह पहले ओलिंपिक खेल आयोजित करने वाले ग्रीस से हुई। भारतीय दल जापानी वर्णमाला के अनुसार 21वें नंबर पर आया। हाकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मेरी कोम के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। भारत के अन्य खिलाड़ियों और छह अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान और जोश दिखाई दे रहा था।

ये रहे मौजूद : भारत के 127 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यीय दल ओलिंपिक में भाग ले रहा है, लेकिन 20 खिलाड़ियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इसमें टेबल टेनिस से सुतीर्था मुखर्जी और जी साथियान, नौकायन से केसी गणपति, वरुण अशोक, विष्णु सरवन और नेत्रा कुमानन, जिम्नास्ट प्रणति नायक, तैराक साजन प्रकाश, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, मुक्केबाजी से सिमरनजीत कौर, लवलीना, पूजा रानी, अमित पंघाल, मनीष कौशिक, आशीष और सतीश कुमार शामिल रहे।

यूनुस को ओलिंपिक लारेल पुरस्कार : समारोह के दौरान बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को ओलिंपिक लारेल पुरस्कार से नवाजा गया।



टोक्यो नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में भाग लेता भारतीय दल ● एएनआइ

ध्वजवाहक मेरी कोम और मनप्रीत ने थामा तिरंगा

- जापानी शुभ रंगों के अनुसार हुई आतिशबाजी के साथ टोक्यो में 32वें ओलिंपिक खेलों का शुभारंभ
- भारत 25वीं बार ओलिंपिक में हिस्सा ले रहा है, कोरोना के कारण जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि
- अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहीं। ब्राजील के दल में नजर आए दो खिलाड़ी
- किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान का दल बिना मास्क के नजर आया। पाकिस्तान के दो ध्वजवाहकों ने भी मास्क नहीं पहने थे
- 12 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी हेंड जाजा सीरिया की ध्वजवाहक बनीं। वह इतिहास की सबसे युवा ध्वजवाहक हैं

संबंधित खबरें » पेज 12

मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को दी बधाई



नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टोक्यो ओलिंपिक के सफल आयोजन की कामना करते हुए जापान और वहां के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा को बधाई दी और उम्मीद जताई कि 'इस प्रतियोगिता में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अतुलनीय प्रदर्शन करेंगे।' मोदी ने प्रधानमंत्री सुगा और जापान को टोक्यो ओलिंपिक और पैरालिंपिक की बहुत शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, 'विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के अतुलनीय प्रदर्शन की हम सत्र में आशा करते हैं।' इसके बाद मोदी ने एक फोटो भी पोस्ट की, जिसमें वह टेलीविजन पर उद्घाटन समारोह देखते हुए भारतीय दल के लिए जयकार करते नजर आ रहे हैं।

हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड की अवमानना याचिका खारिज

यमुना जल विवाद ▸ सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत, हरियाणा के साथ बातचीत से सुलझाएं मामला

दिल्ली की ओर से बार-बार याचिका दाखिल करने पर जताई नाराजगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के खिलाफ बार-बार दाखिल होने वाली दिल्ली जल बोर्ड की अवमानना याचिका को नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह हरियाणा के साथ विचार-विमर्श से मामले को सुलझाए। दिल्ली ने हरियाणा के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर पर्याप्त पानी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव, एएस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष दिल्ली की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश को पढ़ा। इस पर पीठ ने कहा, बताइए 26 साल बाद इसमें क्या अवमानना हुई है? सिंह ने कहा, उस आदेश के मुताबिक हरियाणा को वजीराबाद जलाशय पूरा भरा रखना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि उनके द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा आदेश के अनुसार पानी दे रहा है। कोर्ट ने दिल्ली की ओर से बार-बार याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताते हुए विकास सिंह से कहा, वह अपने मुवक्किल को सलाह दें कि वह बार-बार अर्जी न दाखिल करे।

हरियाणा ने कहा-जरूरत से ज्यादा दे रहे पानी : हरियाणा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कोर्ट से अवमानना याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि याचिका आधारहीन और प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हरियाणा जरूरत से ज्यादा पानी दे रहा है। यमुना रिवर एलोकेशन बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा 1,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी दे रहा है। दीवान ने कहा, कोर्ट के उस आदेश के बाद काफी इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है। अब ये दिल्ली को देखना है कि वह प्लांट में कितना पानी रखेगी। उस आदेश के बाद दो मुख्य पाइप लाइन व कैरियर लाइन चैनल का निर्माण हुआ है। ट्रांसमिशन यमुना से नहीं है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर से केस का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। पीठ ने दीवान से कहा कि वह अवमानना याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब दें। दीवान ने कहा कि न्यूनतम जरूरत की आपूर्ति की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त यमुना नदी को चैनल मानते हुए आदेश दिया था। अब स्थिति बदल चुकी है। 1996 में मूल वाटर प्लांट वजीराबाद जलाशय था, लेकिन अब नई तकनीक आ गई है। स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिल्ली का अधिकार है, वह चाहे तो वजीराबाद जलाशय को पूरा भरा रख सकती है।

दीवान ने कहा कि दिल्ली सरकार बार-बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रही है, जबकि उच्च स्तर पर वार्ता हुई है। दिल्ली की ओर से जवाब देते हुए विकास सिंह ने कहा कि उस आदेश का आशय था कि दिल्ली को जितनी जरूरत हो उतना पानी मिले। दिल्ली इस पानी का उपयोग कृषि में नहीं करती। कोर्ट का आशय था कि दिल्ली की घरेलू जरूरत के लिए पर्याप्त पानी मिले। इस पर कोर्ट ने दिल्ली से कहा कि वह इस बारे में हरियाणा के साथ बातचीत कर मामला सुलझाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली की अवमानना याचिका खारिज कर दी। विकास सिंह कहते रहे कि बातचीत से काम नहीं हो रहा है, कोर्ट याचिका खारिज न करे, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

कहा, कोर्ट गठित कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा आदेश के अनुसार दे रहा पानी



हमें बताइए कि अवमानना कहां है। अगर एक बार फिर सारे रिकार्ड्स देखें तो एक कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें आपकी भी गलती पाई गई है। - सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं क्योंकि हरियाणा खुद प्यासा रहकर दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति झूठ पर टिकी है। झूठ बोलकर पहले वह आक्सीजन का कोटा बढ़वाना चाहते थे। उसी तरह पानी कम मिलने का झूठ बोलकर पानी का कोटा बढ़वाने की उनकी मंशा थी, लेकिन दोनों झूठ सुप्रीम कोर्ट ने सिरे नहीं चढ़ने दिए।
- अनिल विज (गृह, शहरी निकाय और स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा)

महाराष्ट्र में बारिश का कहर, सौ से ज्यादा की मौत

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र में मूसलधार बारिश राज्य के लोगों पर कहर बनकर टूटी है। बारिश के बाद भूस्खलन व मकानों के गिरने की विभिन्न घटनाओं में पिछले दो दिनों में सौ से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। रायगढ़ जिले के तलई गांव में 38, पोलादपुर में 11 लोगों की भूस्खलन से मौत की खबर है। सतारा जिले के मिरगांव में 12 लोगों के मारे जाने एवं आंबेघर में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने की सूचना है। रत्नागिरी के खेड तालुका स्थित धामणंद बौद्धवाड़ी में भी 17 लोग मारे गए हैं। इन सभी स्थानों पर बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई लोग अब भी मलबे में दबे हैं। वहीं, मुंबई के गोवंडी क्षेत्र में एक दोमंजिला घर गिर जाने से चार लोग मारे गए। ज्ञात हो, कोंकण एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में तीन दिनों से मूसलधार बारिश हो रही है। प्रसिद्ध पर्यटनस्थल महाबलेश्वर में गत तीन दिनों में 1500 मिमी. बारिश रिकार्ड की गई है।

भारी बारिश से रत्नागिरी जिले के चिपलूण शहर का बड़ा हिस्सा गुरुवार को जलमग्न हो गया था। शुक्रवार को जलस्तर घटा तो नुकसान का पता चला। गुरुवार को बाढ़ में डूबे रहे चिपलूण के एक कोरोना सेंटर में आक्सीजन न मिलने से आठ लोगों की जान जाने की भी खबर है।

- कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में तीन दिनों से जारी बरसात से बिगड़े हालात
- कई लोगों के अब भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका
- महाबलेश्वर में तीन दिनों में रिकार्ड की गई 1500 मिमी. बारिश



महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक गांव में भूस्खलन से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। प्रेट्र

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने शोक जताया

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोगों की मौत पर शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि बारिश के चलते लोगों के मारे जाने की घटनाएं दुखद हैं। पीएम ने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ठाकरे से बात कर मदद का आश्वासन दिया है।

कई नदियां उफान पर : कोल्हापुर की पंचगंगा नदी के बाद सांगली और सतारा की नदियां भी उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से शहरों में भी कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। पुणे-बेंगलुरु हाइवे पानी से डूबा दिखाई दे रहा है।

तेज हवा, बारिश से बचाव अभियान में कठिनाई : महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री विजय वडेट्टीवार का कहना है कि इस समय कोंकण एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में चलाया जा रहा बचाव अभियान अपने आप में जटिल है। तेज हवा, भारी बरसात के बीच यहां बचाव दल का पहुंचना मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ के डीजी सत्य प्रधान ने भी एक ट्वीट में कहा है कि उनकी टीमें लगातार बचाव कार्य में लगी हैं।

नौसेना व वायुसेना ने संभाला मोर्चा पेज»5
केंद्र व राज्य ने मदद का किया एलान पेज»5

जागरण विशेष

हवाओं का रुख तय करता है मौसम का मिजाज



विदिशा : आधुनिक दौर में मौसम का मिजाज जानने के लिए उपग्रह से लेकर तमाम उपकरणों का सहारा लिया जाता है लेकिन, मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में किसान आज भी भारत की पुरातन संस्कृति पर भरोसा करते हैं। (पेज-10)

अंदर की खबरें

विश्वनाथ कारिडोर के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जमीन की अदला-बदली

जागरण संवाददाता, वाराणसी

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कारिडोर के लिए मंदिर प्रशासन व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच जमीन की अदला-बदली हुई है। जमीन की कीमत के आधार पर हुई अदला-बदली में विश्वनाथ धाम कारिडोर को 1700 वर्ग फीट जमीन मिली है। बदले में मंदिर प्रशासन ने करीब 200 मीटर दूर बांस फाटक क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट जमीन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद (संस्था का नाम) को दी है। कई दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्ष इस निर्णय पर पहुंचे। ज्ञानवापी मस्जिद के सामने स्थित विश्वनाथ धाम कारिडोर को मिली जमीन पर बने पुलिस कंट्रोल रूम को गिराने का काम शुक्रवार को शुरू भी हो गया।

आर्टिकल-31 में निहित एक्सचेंज आफ प्रापर्टी के तहत दो चरणों में संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ। इसके लिए नौ लाख 29 हजार रुपये की ई-स्टांप ड्यूटी अदा की गई। मंदिर प्रशासन ने आठ जुलाई तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने 10 जुलाई को रजिस्ट्री की। यह विनिमय पत्र राज्यपाल की स्वीकृति पर बना। सरकार का प्रतिनिधित्व नोडल अधिकारी व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर सुनील कुमार वर्मा ने किया। वहीं, दूसरे पक्ष से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, वाराणसी के सचिव अब्दुल बातिन नोमानी ने हस्ताक्षर किए।

ऐतिहासिक कदम

- ज्ञानवापी मस्जिद के सामने स्थित 1700 वर्ग फीट हस्तांतरित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू
- सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्ष 1993 में प्रशासन को दे दी थी जमीन, इस पर चल रहा था पुलिस कंट्रोल रूम
- मंदिर प्रशासन ने 1000 वर्ग फीट जमीन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को दी

इस जमीन का ज्ञानवापी मस्जिद से ताल्लुक नहीं है। यह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन थी, जिसे वर्ष 1993 में प्रशासन को सौंपा था। इसके बदले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को बांसफाटक के पास 1000 वर्ग फीट जमीन मिली है।
-एसएम यासीन, संयुक्त सचिव-अंजुमन इंतजामिया मसाजिद

1000 फीट जमीन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को दी गई है। बदले में 1000 फीट जमीन श्रीकाशी विश्वनाथ कारिडोर को मिली है। इसके लिए सहमति बन चुकी थी। विधिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
-दीपक अग्रवाल, कमिश्नर (वाराणसी)

राज्यसभा से तृणमूल के शांतनु सेन पूरे सत्र के लिए निलंबित



नई दिल्ली : राज्यसभा में मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिससे सदन को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सभापति एम. वेंकैया नायडू ने बृहस्पतिवार को हुई घटना को अशोभनीय और संसदीय लोकतंत्र पर हमला बताया। सरकार की तरफ से निलंबन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सभापति ने शांतनु सेन के निलंबन की घोषणा करते हुए उन्हें सदन छोड़ने को कहा। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। (पेज-3)

जम्मू को दहलाने आया पाकिस्तानी ड्रोन, पुलिस ने मार गिराया

- सरहद से आठ किलोमीटर भीतर कानाचक्क सेक्टर में आ चुके ड्रोन में बंधी थी पांच किलो आईईडी
- राष्ट्रपति के दौरे से दो दिन पहले हुई घटना, सेना मुख्यालय से महज डेढ़ किलोमीटर दूर गोली मार कर गिराया
- जैश ने रची थी साजिश, ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोलर और जीपीएस भी लगा हुआ था



जम्मू के अखनूर सेक्टर में पुलिस द्वारा मार गिराया गया पाकिस्तानी ड्रोन। प्रेट्र

जागरण न्यूज नेटवर्क, जम्मू

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 15 अगस्त से पहले जम्मू में बड़ी वारदात को अंजाम देने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम कर दी। गुरुवार देर रात अखनूर के कानाचक्क सेक्टर में आठ किलोमीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में आ चुके पाकिस्तानी ड्रोन को पुलिस ने मार गिराया। फ्लाइट कंट्रोलर व जीपीएस से लैस इस ड्रोन में पांच किलो आईईडी बंधी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। ज्ञात हो, जिस जगह इस ड्रोन को गिराया गया, वहां से सेना की अखनूर डिवीजन का मुख्यालय डेढ़ किलोमीटर दूर था। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के दौरे से दो दिन पहले हुई इस घटना के बाद सेना, सुरक्षाबलों को पुलिस को अधिक सर्तकता बरतने की हिदायत दी गई है।

जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि जैश-ए-मुहम्मद सीमा पार से अखनूर सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराने वाला है। इसके बाद पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। गुरुवार रात करीब एक बजे कानाचक्क के गुड़ा पट्टन क्षेत्र में पुलिस ने ड्रोन को देखा। वह थोड़ा नीचे हुआ तो पुलिस ने फायर कर उसे गिरा दिया। ड्रोन के साथ पांच किलो की आईईडी को बड़े तरीके से बांधा गया था। इसे धागे की मदद से नीचे गिराया जाना था। आईईडी विस्फोट के लिए तैयार थी। सिर्फ तार को जोड़ा जाना बाकी था।

आईईडी लेने आने वाले की तलाश जारी : पुलिस ने ड्रोन जब्त करने के बाद उस व्यक्ति के आने का इंतजार किया, जिसे आईईडी लेने आना था, मगर शायद उसे ड्रोन को गिराए जाने की सूचना मिल गई होगी। फिलहाल उसकी तलाश जारी है।

जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ रहे तार: ड्रोन से जिस पेलोड यानी आईईडी को गिराया जाना था, उसे धागे से बांधा गया था। इस प्रकार के धागे 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके के बाद भी मिल थे। इससे साफ है कि एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया था।

चीन, ताइवान और हांगकांग के पार्ट्स को असेंबल कर बना है ड्रोन : प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह ड्रोन एक हेक्साकाप्टर है, जिसके छह पंखे हैं। यह ड्रोन असेंबल है, जिसमें कुछ पार्ट चाइना, कुछ ताइवान और हांगकांग के हैं।

कठुआ में गिराए ड्रोन से मात्र एक सीरियल नंबर का अंतर : ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोलर पर जो सीरियल नंबर लिखा है, वह बीते वर्ष कठुआ में हथियार लेकर आए ड्रोन से मिलता है। दोनों के सीरियल नंबर में मात्र एक ही अंक का अंतर है। यह ड्रोन पेलोड लेकर 10 किलोमीटर तक ही चल पाता है।

बंगाल में नौसेना के प्रतिष्ठानों के तीन किमी दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी पेज»5

रुतबा

शांति वार्ता में अफगानिस्तान के दूत अब्दुल्ला अचानक भारत पहुंचे, जयशंकर के साथ की लंबी बातचीत, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन अगले हफ्ते आएंगे, बुधवार को जयशंकर और डोभाल से होगी वार्ता

अफगानिस्तान पर नई दिल्ली में कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अफगानिस्तान में हालात किस करवट बैठेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं, परंतु दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर कूटनीतिक सक्रियता काफी बढ़ गई है। अफगानिस्तान को लेकर दुनिया भर में चल रही शांति वार्ताओं में वहां की सरकार के प्रतिनिधि डा. अब्दुल्ला अब्दुल्ला शुक्रवार को अचानक दिल्ली पहुंचे और विदेश मंत्री एस जयशंकर से लंबी बातचीत की। इस वार्ता को इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भारत पहुंच रहे हैं। 28 जुलाई को उनकी जयशंकर के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से बातचीत होनी है। वह पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भारत व अमेरिकी विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक होगी।



नई दिल्ली में शुक्रवार को अफगानिस्तान के शांति वार्ताकार डा. अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

जयशंकर और अब्दुल्ला के बीच बातचीत को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। परंतु, अब्दुल्ला की यात्रा के बाद जल्द ही अफगानिस्तान के सेना प्रमुख के भारत आने की सूचना है। तालिबान के अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों में बढ़ते हमले को देखते हुए सेना प्रमुख की इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अफगानिस्तान ना सिर्फ भारत से अतिरिक्त सैन्य साजो समान की अपेक्षा रखता है बल्कि युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों के उपचार में भी मदद मांग रहा है।

अमेरिकी विदेश मंत्री की आगामी यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह 27 और 28 जुलाई को भारत में होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। 28 जुलाई को वह जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ब्लिंकन प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। यहां से ब्लिंकन कुवैत जाएंगे।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्लिंकन की यात्रा से दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों में और मजबूती आएगी। उनकी भारतीय मंत्रियों के साथ कोविड महामारी, हिंद प्रशांत क्षेत्र और अफगान मुद्दे समेत आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि ब्लिंकन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर भावी सहयोग की ठोस रूप रेखा बन सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री के भी भारत आने की संभावना है।

स्पिन बोल्डक में तालिबान ने की सौ लोगों की निर्मम हत्या

वाशिंगटन : तालिबान ने अफगानिस्तान में हावी होने के बाद बकरीद पर पाकिस्तान सीमा से लगे शहर स्पिन बोल्डक में सौ नागरिकों की हत्या कर खूनी खेल शुरू कर दिया है। नरसंहार के दौरान निर्दोष नागरिकों के साथ लूटपाट और घृणित कार्य किए गए। अफगान सरकार ने कहा है कि तालिबान ने अपने आका पाकिस्तान के इशारे पर यह जघन्य कांड किया है। (पेज-11)

4.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा शुक्रवार को दिल्ली का। यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 24 जुलाई, 2021

वन भूमि से हर तरह का अवैध निर्माण हटाया जाए : कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

फरीदाबाद खोरी गांव की वन भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फरीदाबाद नगर निगम से कहा कि वन भूमि पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। वन भूमि से सभी तरह के अवैध निर्माण हटाए जाएं, इसमें किसी तरह का अपवाद और छूट नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम को चार सप्ताह का समय और दे दिया है। नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 150 एकड़ में से करीब 74 एकड़ वन भूमि अवैध कब्जेदारों से खाली करा ली गई है। निगम ने पूरा क्षेत्र खाली कराने के लिए कोर्ट से कुछ और समय मांगा था।

जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश महेश्वरी की पीठ ने शुक्रवार को ये आदेश खोरी गांव में वन भूमि पर अवैध निर्माण हटाए जाने पर रोक और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को आदेश दिया था कि वह वन भूमि से सभी अवैध कब्जे हटाकर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे। नगर निगम की ओर से पेश वकील अरुण भारद्वाज ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि आदेश के मुताबिक नियोजित ढंग से अभियान चलाकर वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि 150 एकड़ वन भूमि में से 74 एकड़ भूमि से अवैध कब्जा हटा दिया गया है और जमीन अपने कब्जे में ले ली गई है। काम पूरा होने में अभी कुछ और वक्त लगेगा इसके लिए कोर्ट तीन सप्ताह का समय और दे दे। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करके और काम को देखते हुए नगर निगम को चार सप्ताह का वक्त और दे दिया।

पुनर्वास के लिए नगर निगम को ज्ञापन दें : सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण हटाए जाने के पीड़ित लोगों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाल्विस ने कहा कि निर्माण हटाने से लोग सड़क पर आ गए हैं। उनके पुनर्वास का इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने हरियाणा की नई पुनर्वास नीति का भी मुद्दा उठाया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि नई नीति का अभी सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ है। कोर्ट ने गोंसाल्विस से कहा कि वह इस बारे में फरीदाबाद नगर निगम को ज्ञापन दें। निगम उस पर विचार करेगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई नीति 31 जुलाई तक अधिसूचित हो जानी चाहिए। अगर नई नीति पर याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति है तो कानून के मुताबिक उन्हें अर्जी देने की छूट होगी।

खोरी गांव का मामला

- फरीदाबाद नगर निगम ने बताया, 150 एकड़ में से 74 एकड़ से अवैध निर्माण हटाया
- बाकी के अवैध निर्माण हटाने के लिए शीर्ष अदालत ने दिया चार और सप्ताह का समय


फाइल फोटो

चाहे फार्महाउस हो या कुछ और, एक भी अवैध कब्जा नहीं रहेगा

गोंसाल्विस ने एक आइएएस द्वारा आरटीआइ अर्जी से मिली सूचना का हवाला देते हुए कहा कि वन भूमि पर अवैध कब्जेदारों की लंबी सूची है। इसमें फार्महाउस और होटल भी शामिल हैं। उनकी इस दलील पर पीठ ने कहा कि आप आश्वस्त रहें, वन भूमि पर एक भी अवैध कब्जा नहीं रहेगा चाहे वह फार्महाउस हो या कुछ और। कोर्ट ने कहा कि वन भूमि से सारे अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई अपवाद या छूट नहीं होगी। यह काम दिए गए चार सप्ताह में पूरा किया जाएगा। जिनके पास अनुमति नहीं है, उन्हें हटाया जाए। मामले पर कोर्ट तीन अगस्त को फिर सुनवाई करेगा।

'टीकाकरण के बाद ही खोले जाएं स्कूल'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को खोलने के बारे में कहा कि आदर्श स्थिति तो यही है कि टीकाकरण के बाद ही स्कूल खोले जाएं। उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे पास यही मैसेज आ रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक बहुत चिंतित हैं। वैक्सीन की कमी के बारे में सीएम ने कहा कि वैक्सीन है ही नहीं। केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जाए।

सीएम तिमारपुर में भारत में आइएसओ से प्रमाणित विधायक कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। आइएसओ-9001 का यह प्रमाण पत्र, आम आदमी पार्टी के तिमारपुर विधानसभा से विधायक दिलीप पांडेय के कार्यालय को मिला है। केजरीवाल ने कहा कि विधायक कार्यालय में सभी व्यवस्थाएं शानदार हैं। कार्यालय में आने वाली विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में संभवतः यह पहला विधायक कार्यालय है, जिसको आइएसओ सर्टिफिकेट मिला है। अगर यह व्यवस्था यहां सफल होती है, तो फिर पूरी दिल्ली में सभी विधायकों के कार्यालय में इसको लागू करेंगे।

वहीं विधायक पांडेय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से प्रेरित सेवा भाव की राजनीति का एक नवीन आयाम यह प्रमाण पत्र है। कोई भी अपनी समस्या लेकर यहां आएगा तो उसके समाधान को लेकर प्रक्रिया क्या होगी, समस्या को कौन देखेगा और उसका समाधान कैसे कराया जाएगा, इन सबका एक व्यवस्थित तरीका कार्यालय में बनाया गया है।


तिमारपुर के विधायक दिलीप पांडे को आइएसओ-9001 का प्रमाण पत्र सौंपते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (दाएं)। सौ. दिल्ली सरकार

न्यूज गैलरी

मास्टर प्लान की अधिसूचना पर डीडीए से मांगा जवाब

नई दिल्ली : पंजाबी और उर्दू में दिल्ली मास्टर प्लान-2041 को प्रकाशित नहीं करने और दिल्लीवासियों को आपत्तियां व सुझाव देने के लिए मात्र 45 दिन देने संबंधी अधिसूचना को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। नेशनल हाकर फेडरेशन की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त तक होगी। अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि मास्टर प्लान-2021 को सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है, जबकि पंजाबी और उर्दू को छोड़ दिया गया है। इसके अलावा याचिका में मास्टर प्लान पर सुझाव व आपत्तियों के लिए न्यूनतम 90 दिन का समय देने का निर्देश देने की मांग की गई है। हालांकि, डीडीए ने गुरुवार को समाप्त हो रही समयसीमा को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। (जासं)

सीआइएससीई आज जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे

नई दिल्ली : काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (सीआइएससीई) शनिवार को अपराह्न तीन बजे के बाद 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा करेगा। इसे www.cisce.org वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। सीआइएससीई के मुताबिक प्रधानाचार्यों को दी गई आइडी और पासवर्ड के जरिये पोर्टल पर भी स्कूल छात्रों का परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर वे ciscehelpdesk@orioninc.com या 18002671760 पर संपर्क कर सकते हैं। छात्र विशिष्ट आइडी नंबर के जरिये भी परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल से ICSE/ISC <सात अंकों का विशिष्ट आइडी> टाइप करके 09248082883 पर भेजना होगा। (जासं)

पंजाब के समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा दे दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि स्वजन से परेशान होकर पंजाब से आए समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा व सुरक्षित स्थान मुहैया कराए। दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन स्वजन को स्वीकार नहीं होने के कारण उन्हें धमकी मिल रही है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने मयूर विहार फेज-1 के एसएचओ को निर्देश दिया कि गैर सरकारी संगठन धनक आफ ह्यूमैनिटी के कार्यालय के में रह रहे जोड़े को किंग्सवे स्थित सेवा कुटीर परिसर में शिफ्ट किया जाए, साथ ही वहां पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। (जासं)

छह जवानों के परिवारों को मिलेंगे एक-एक करोड़

कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग की तरफ से रखे गए प्रस्ताव को मिली मंजूरी

दिल्ली पुलिस के दो, एयर फोर्स के तीन और सिविल डिफेंस के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान गंवाई थी जान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दिल्ली के छह जांबाजों के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देगी। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इस बैठक में राजस्व विभाग ने सम्मान राशि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर मंजूरी दे दी गई।

जिन जांबाजों के परिवारों को यह सम्मान राशि दी जाएगी, उनमें से दो जवान दिल्ली पुलिस में तैनात थे और तीन एयरफोर्स में थे, जबकि एक जवान की सिविल डिफेंस में तैनाती थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के जिन लोगों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सरकार की तरफ से दी जाने वाली सम्मान राशि से परिवार को थोड़ी मदद हो जाएगी।

इन जवानों के परिवार को दी जाएगी अनुग्रह राशि

संकेत कौशिक (एसीपी-दिल्ली पुलिस) : संकेत कौशिक दिल्ली पुलिस में एसीपी पद पर कार्यरत थे। वह वसंत विहार में रह रहे थे। उनकी तैनाती दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली में यातायात पुलिस में थी। वह 25 जुलाई, 2020 को उमराव होटल के पास सर्विस लेन पर वाहनों की जांच कर रहे थे। रात करीब आठ बजे गुरुग्राम की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे मिनी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था। अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।

विकास कुमार-हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस : हरियाणा के झज्जर जिला निवासी विकास कुमार दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे। उनकी तैनाती नई दिल्ली स्थित वसंत विहार थाने में थी। वह 15 सितंबर, 2016 को आउटर रिंग रोड के पास जिया सराय से नेहरू प्लेस तक पिकेट ड्यूटी कर थे। मुनरिका की तरफ से एक तेज रफ्तार आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इससे उनका निधन हो गया था।

प्रवेश कुमार-सिविल डिफेंस : दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के वीपीओ खैरा निवासी प्रवेश कुमार सिविल डिफेंस में कार्यरत थे। 19 सितंबर 2020 की देर रात वह टीम के साथ मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। तेज रफ्तार आए एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उनका निधन हो गया था।

सुनित मोहंती-लेफ्टिनेंट एयरफोर्स : द्वारका निवासी सुनित मोहंती एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट थे। 24 जून, 2016 से वह 43 स्क्वाड्रन एयर फोर्स में तैनात थे। उन्हें अरुणाचल के मेहकुका एयरफील्ड के लिए हवाई रखरखाव मिशन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। विमान ने तीन जून, 2019 को जोरहाट एयर बेस से दोपहर करीब साढ़े बारह बजे उड़ान भरी थी। करीब आधे घंटे बाद विमान लापता हो गया। विमान का मलबा 12 जून को परी हिल्स, सियांग, अरुणाचल के रास्ते मेंचूका में मिला था। विमान में एयरफोर्स में कार्यरत सफदरजंग एन्क्लेव निवासी राजेश कुमार भी थे। हादसे में विमान में सवार सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई थी।

मीत कुमार-स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स : अशोक विहार निवासी मीत कुमार एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर कार्यरत थे। उनका विमान मिग-21 कांगड़ा हिल्स (एचपी) में 18 जुलाई 2018 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें उनकी मृत्यु हो गई।

मुख्यमंत्री को अपने ट्वीट का सम्मान करना होगा : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- अनुग्रह राशि की मांग को लेकर सिपाही अमित कुमार की पत्नी की याचिका पर हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट कर कोरोना योद्धाओं को एक करोड़ की अनुग्रह राशि देने का वादा करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया। कोरोना के चलते जान गंवाने वाले सिपाही अमित कुमार की पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने वादे का सम्मान करना होगा। गरीबों के किराये भुगतान करने के मामले में गुरुवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री यूं ही किसी भी कारण से वादे नहीं कर सकते हैं।

पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने और समय देने की मांग की। पीठ ने जवाब दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई चार अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। त्रिपाठी ने कहा कि सिपाही अमित इस अनुग्रह राशि को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वह दिल्ली सरकार की तरफ से कोविड ड्यूटी पर तैनात नहीं किए गए थे।

वहीं अधिवक्ता संदीप सहगल व अधिवक्ता आनंद प्रकाश शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर अमित की पत्नी पूजा ने दलील दी कि वह अनुग्रह राशि के लिए एक आफिस से दूसरे आफिस चक्कर काट रही हैं, लेकिन एक साल बाद भी उन्हें राशि नहीं दी गई। उन्होंने अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ट्वीट का हवाला दिया। इस पर पीठ ने कहा कि मेरे सामने मुख्यमंत्री द्वारा किया गया ट्वीट है और अगर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। याचिका के अनुसार अमित उत्तर-पश्चिम जिले के भारत नगर थाने में तैनात थे और महामारी के दौरान अग्रिम योद्धा के तौर पर सेवा दे रहे थे। पांच मई, 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक करोड़ की अनुग्रह राशि देने को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक अनुग्रह राशि नहीं मिली।

लाल किले में फ्लावर स्टैंड के लिए तैयार नहीं एएसआइ

- रक्षा मंत्रालय लाहौरी गेट की प्राचीर के सामने बनाना चाहता है फ्लावर स्टैंड
- एएसआइ ने कहा- यहां किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता

वीके शुक्ला, नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किला पर 15 अगस्त को होने वाले समारोह के लिए इस बार एक बड़ा फ्लावर स्टैंड बनाने की योजना पर रक्षा मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) एकमत नहीं हैं। एएसआइ का कहना है कि लाल किला विश्व धरोहर में शामिल है, जिसके चलते वहां किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह नियमों का उल्लंघन होगा। ऐसे में लाल किला को मिला विश्व धरोहर का तमगा यूनेस्को वापस ले सकता है।

मालूम हो कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला में होने वाले समारोह की तैयारियां रक्षा मंत्रालय करता है। हर साल लाल किला में लाहौरी गेट पर प्राचीर से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसी प्राचीर के सामने वाले भाग को रक्षा मंत्रालय सुंदर बनाना चाहता है, जिसमें सुंदर फूलों वाले गमले रखे जाएंगे। इसके लिए प्राचीर के सामने दो सौ फीट लंबा और आठ मीटर ऊंचा फ्लावर स्टैंड बनाया जाना है।

एएसआइ के एक अधिकारी ने कहा कि स्टैंड के लिए रक्षा मंत्रालय कंक्रीट के पिलर बनाना चाहता है। स्मारक में किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। ऐसे में इसे बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर स्टैंड को अस्थायी तौर पर बनाने का कोई और उपाय निकल सकता है तो इस पर विचार किया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस विवाद का जल्द ही कोई समाधान निकाल लिया जाएगा।

एक साल बाद भी नहीं हटाया गया हेलीपैड

स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के लिए हर साल लाल किला में हेलीपैड बनाया बनाया जाता है। पिछले साल इसे दीवान-ए-खास के सामने बनाया गया था। नियम के अनुसार इसे हर साल आयोजन के दो या तीन दिन बाद हटाया जाता रहा है। मगर पिछले साल नहीं हटाया गया, जबकि एएसआइ इस बारे में पत्र व्यवहार भी कर चुका है।

ताहिर हुसैन की याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

दिल्ली दंगा

जासं, नई दिल्ली

दिल्ली दंगा मामले में मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी से निलंबित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दंगा मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले को ताहिर ने चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने ताहिर की याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ताहिर हुसैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने दलील दी कि बिना पर्याप्त कारण के ताहिर के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिका में हुसैन के खिलाफ पेश आरोपपत्र में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 के तहत दर्ज मामले को रद करने मांग की गई है। इसके अलावा यूएपीए प्रविधानों के तहत अभियोजन को समीक्षा समिति द्वारा दी गई मंजूरी को भी रद करने की मांग की गई है।

इशरत जहां का दावा, नहीं है किसी धर्म की विरोधी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके अधिवक्ता प्रदीप तेवतिया ने कई धार्मिक आयोजनों की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि इशरत किसी धर्म की विरोधी नहीं है। वह वकील और युवा नेता रही है। दंगे की साजिश में शामिल बताकर उसे 'कट्टर' दिखाया गया। जांच एजेंसी उसकी गलत छवि पेश कर रही है। इशरत की तरफ से अधिवक्ता ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस के पास उसके खिलाफ एक भी साक्ष्य नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी। अधिवक्ता प्रदीप तेवतिया ने अपने सहयोगी अधिवक्ता गौरव दलाल के साथ इशरत के कई वर्षों के वित्तीय लेनदेन के दस्तावेज पेश किए।

त्रिलोकपुरी-मयूर विहार पाकेट कारिडोर शुरू करने की मिली अनुमति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी-मयूर विहार पाकेट एक के बीच नवनिर्मित कारिडोर पर मेट्रो परिचालन शुरू करने की अनुमति मिल गई है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) जेके गर्ग ने शुक्रवार को नवनिर्मित कारिडोर पर सुरक्षा मानकों की जांच की।

सीएमआरएस से स्वीकृति मिलने पर पिंक लाइन के इस कारिडोर के साथ ही ग्रे लाइन के नजफगढ़-ढांसा बस स्टैंड के बीच अगले सप्ताह तक मेट्रो का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर इस समय दो हिस्से में मजलिस पार्क से मयूर विहार पाकेट एक और त्रिलोकपुरी से शिव विहार के बीच मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इन दोनों कारिडोर के बीच 290 मीटर का हिस्सा पहले नहीं बन पाया था। इस वजह से पूरे पिंक लाइन पर मेट्रो का परिचालन नहीं हो रहा था। अब त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पाकेट एक को जोड़ने वाला कारिडोर तैयार हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से इस पर ट्रायल भी चल रहा है। इस कारिडोर पर परिचालन शुरू होने से पिंक लाइन के पूरे हिस्से पर मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी और यात्री शिव विहार से मजलिस पार्क तक आसानी से सफर कर सकेंगे।

अब जल्द रूप नहीं बदलेगा कोराना वायरस : गुलेरिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डा. रणदीप गुलेरिया ने अनुमान जताया कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस नाटकीय अंदाज में म्यूटेट नहीं होगा। दोहराया कि तीसरी लहर इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं। कोविड अनुकूल व्यवहार से तीसरी लहर को टाला जा सकता है और उसकी गंभीरता भी कम की जा सकती है।

डा. गुलेरिया ने शुक्रवार को कहा कि हाल ही में आए सीरो सर्वे के मुताबिक दो तिहाई आबादी में समुचित मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसके बावजूद जब तक ज्यादातर लोगों का टीकाकरण नहीं होता, भीड़ में जाने और गैर-जरूरी यात्रा से बचना चाहिए। उन्होंने उन राज्यों को आगाह किया है, जहां अब भी ज्यादा मामले आ रहे हैं। कहा कि ज्यादा मामले वाले राज्य उन राज्यों को जोखिम में डाल सकते हैं, जहां संक्रमण को प्रभावी तरीके से काबू किया गया है।

कोरोना के 58 नए मरीज, एक की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी में शुक्रवार को कोरोना के 58 नए मरीज मिले। एक मरीज की मौत हो गई। 69 मरीज ठीक हुए। मरीजों के ठीक होने की दर 98.21 फीसद है। पिछले 24 घंटों में 67 हजार 817 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 0.09 फीसद सैंपल पाजिटिव मिले। मृत्यु दर 1.74 फीसद पर स्थिर रही। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 14 लाख 35 हजार 778 हो गई है, जबकि 14 लाख दस हजार 164 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 25 हजार 41 हो गया है।

सक्रिय मरीजों की संख्या 573 है। फिलहाल 167 मरीज आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि अस्पतालों में 339 मरीज भर्ती हैं। कोविड केयर सेंटर में नौ मरीजों का इलाज चल रहा है। कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 322 रह गई है।

होगी सुविधा

डीयू रविवार को लांच करेगा नई वेबसाइट, इस पर कालेज, पाठ्यक्रम, शुल्क आदि का पूरा विवरण होगा मौजूद

एक क्लिक पर मिलेगी डीयू दाखिले से जुड़ी हर जानकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोरोना काल में लगातार दूसरे साल दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन होगी। सोमवार से दाखिले की दौड़ शुरू हो जाएगी। पीएचडी, एमफिल समेत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्र पंजीकरण कर सकेंगे। दाखिला प्रक्रिया को सुचारु से संपन्न कराने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय रविवार को नई वेबसाइट लांच करेगा। इस पर बस एक क्लिक में दाखिले से जुड़ी हर जानकारी छात्रों को मिलेगी।

मोबाइल फ्रेंडली : डीयू में कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रो. संजीव सिंह ने बताया कि वेबसाइट पूरी तरह मोबाइल फ्रेंडली होगी। दरअसल, विभाग ने डीयू की वेबसाइट उपयोगकर्ताओं पर एक शोध किया है। इसमें पता चला कि 80 फीसद उपयोगकर्ता मोबाइलधारक हैं। इसलिए वेबसाइट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मोबाइल पर न केवल आसानी से खुल जाए, बल्कि प्रत्येक सेक्शन दिखाई दे।

बड़े काम की वेबसाइट : वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर पंजीकरण के लिए लिंक, पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। डीयू प्रशासन की मानें तो स्नातक, स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही विज्ञान, कला वर्ग, विधि, संगीत, सामाजिक विज्ञान का पेज खुलेगा। इस पर छात्रों को यह भी पता चल सकेगा कि किस कालेज में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं छात्र को पाठ्यक्रम के तहत सीट, शुल्क की भी पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी।

चैटबाक्स में पूछें सवाल : डीयू हर साल ईमेल जारी करता था। छात्र अपने सवाल ईमेल के जरिये पूछते थे। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत बोझिल थी। अब नई वेबसाइट में चैटबाक्स की सुविधा होगी। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर किया गया है। छात्र दाखिले से संबंधित सवाल पूछेंगे और जवाब तुरंत मिलेगा। यही नहीं छात्र जैसे ही कोई शब्द टाइप करेंगे, उससे मिलते-जुलते सवाल उन्हे दिखने लगेगा।


कुछ इस तरह दिखेगी दिल्ली विवि की नई वेबसाइट। सौ. वीडियोग्रैब

आवदेन से संबंधित जानकारी

पाठ्यक्रम	आवेदन प्रारंभ होंगे	आखिरी तिथि
स्नातकोत्तर	26 जुलाई	21 अगस्त
एमफिल-पीएचडी	26 जुलाई	21 अगस्त
स्नातक पाठ्यक्रम	2 अगस्त	31 अगस्त

सीटों की स्थिति

स्नातक की सीटें	65 हजार
स्नातकोत्तर	20 हजार

2020 दाखिले से संबंधित आंकड़े

कुल कालेज	91
स्नातक में दाखिले के लिए पंजीकरण	563670
आवेदक जिन्होंने शुल्क जमा किया	354005

एनआइओएस ने जारी किया 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम

जागरण संवाददाता, नोएडा

- दसवीं में 90.64 फीसद और 12वीं में 79.21 फीसद परीक्षार्थी हुए पास

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग (एनआइओएस) ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। यह पहला मौका है कि जब एनआइओएस ने सीबीएसई से पहले 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। दसवीं में 90.64 फीसद और 12वीं में 79.21 फीसद छात्र पास हुए हैं। छात्र अपने परीक्षा परिणाम एनआइओएस की वेबसाइट nios.ac.in या results.nios.ac.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा छात्र अपने परिणाम www.digilocker.gov.in पर भी देख सकते हैं। छात्र यहां से परीक्षा परिणाम का प्रिंट भी ले सकते हैं।

एनआइओएस के निदेशक की तरफ से जारी किए गए परीक्षा परिणाम के अनुसार 10वीं कक्षा में एक लाख 18 हजार 869 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 75 हजार 637 छात्र और 42 हजार 217 छात्राओं के साथ 15 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। एक लाख सात हजार 745 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इनमें 68 हजार 416 छात्र और 39 हजार 314 छात्राएं पास हुए हैं। सभी 15 ट्रांसजेंडर भी सफल रहे हैं। 12वीं कक्षा में एक लाख 69 हजार 748 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें एक लाख 15 हजार 737 छात्र, 53 हजार 983 छात्राएं और 28 ट्रांसजेंडर शामिल थे। 12वीं कक्षा में एक लाख 34 हजार 466 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इनमें 93 हजार 258 छात्र, 41 हजार 184 छात्राएं और 24 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। एनआइओएस के अधिकारियों ने बताया कि सफल परीक्षार्थियों की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट रीजनल सेंटर से होकर स्टडी सेंटर पर पहुंचेंगे।

15 सितंबर तक बोलियां आ सकती हैं एयर इंडिया की बोली लगाने में रुचि रखने वाली इकाइयों की तरफ से। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में दी है।

रास से तृणमूल के शांतनु पूरे सत्र के लिए निलंबित

कार्रवाई ▸ सदन में आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ा था

राज्यसभा के सभापति ने गुरुवार को हुई घटना को अशोभनीय और संसदीय लोकतंत्र पर हमला बताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिससे सदन को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सभापति एम. वेंकैया नायडू ने गुरुवार को हुई घटना को अशोभनीय और संसदीय लोकतंत्र पर हमला बताया। सरकार की तरफ से निलंबन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सभापति ने शांतनु सेन के निलंबन की घोषणा करते हुए उन्हें सदन छोड़ने को कहा। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया।

पेगासस जासूसी मामले में गुरुवार को राज्यसभा में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब दे रहे थे और विपक्ष नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहा था। उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद शांतनु सेन ने मंत्री वैष्णव के हाथ से कागज छीना और उसे फाड़कर आसन की ओर उड़ा दिया। दोनों ओर से मामला गरम होने पर सदन स्थगित कर दिया गया।


नई दिल्ली में शुक्रवार को एक प्रेसवार्ता के दौरान तृणमूल कांग्रेस सदस्य शांतनु सेन। एएनआइ

संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने टीएमसी सदस्य शांतनु सेन के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सभापति नायडू ने उन्हें सत्र के बाकी अवधि के लिए निलंबित करने की घोषणा की। इसके विरोध में टीएमसी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। गुरुवार की हुई इस घटना के बाद राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी और संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने सभापति नायडू से मुलाकात कर इस घटना का पूरा ब्योरा दिया था।

निलंबन प्रक्रिया पर टीएमसी नेता ने एतराज जताया

टीएमसी सदस्यों के विरोध व हंगामे के बीच टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रे ने निलंबन की प्रक्रिया पर एतराज जताते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सदन के बिजनेस सूची में दर्ज नहीं था। बिजनेस सूची में प्रस्ताव के न होने की वजह से उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। टीएमसी के एक अन्य सदस्य ने आरोप लगाया कि सेन को एक मंत्री ने चेतावनी दी थी, लेकिन तभी सभापति ने कहा कि सदन के स्थगित होने के बाद यह घटना हुई थी। टीएमसी सदस्य ने बताया कि सदन स्थगित होने के बाद मंत्री हरदीप पुरी ने उन्हें मौखिक रूप से चेतावनी देने के अंदाज में अनाप शनाप बोला था।

पुराना है माननीयों के निलंबन का इतिहास

राज्यसभा में आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के निलंबित होने का इतिहास नया नहीं है। सदन के भीतर अशोभनीय आचरण के लिए अब से पहले भी कई बार सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है।

यह है प्रक्रिया

राज्यसभा की रूल बुक के नियम 255 के तहत सभापति को अधिकार है कि वह आचरण उपयुक्त नहीं पाए जाने पर किसी सदस्य को तत्काल सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। हालांकि सभापति के पास सदस्य को निलंबित करने का अधिकार नहीं होता। सदन अलग से प्रस्ताव लाकर किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है। निलंबन की अधिकतम समयसीमा उस समय चल रहे सत्र तक होती है। समयसीमा से पहले निलंबन खत्म करने की भी यही प्रक्रिया है।

राज्यसभा से निलंबन के कुछ मामले

3 सितंबर, 1962 : राज्यसभा सदस्य गोडे मुराहरी को निलंबित किया गया। उन्हें मार्शल की मदद से सदन से बाहर निकाला गया।

25 जुलाई, 1966 : राज नारायण और गोडे मुराहरी को निलंबित किया गया।

15 नवंबर, 1976 : सुब्रमणियन स्वामी को निलंबित किया गया।

15 मार्च, 1989 : पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में गठित ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सदन में रखे जाने से पहले ही मीडिया में लीक होने के कारण हंगामा हुआ। हंगामे के कारण 63 सदस्यों को हफ्तेभर के लिए निलंबित कर दिया गया।

21 मार्च, 2006 : साक्षी महाराज को प्रस्ताव लाकर निलंबित किया गया।

23 सितंबर, 2020 : सदन में हंगामे के बाद आठ सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित हुआ।

– जागरण रिसर्च

राहुल ने पेगासस जासूसी को देशद्रोह बताया


नई दिल्ली में शुक्रवार को विजय चौक पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से रुबरू हुए। एएनआइ

- विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया
- सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच कराने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सदन के अंदर संग्राम कर रहे विपक्षी दलों ने शुक्रवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए राजनेताओं-पत्रकारों समेत कई प्रमुख हस्तियों के फोन की जासूसी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने पोस्टर-बैनरों के साथ जासूसी को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए इसे देशद्रोह तक करार दिया।

राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल देश के लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं के खिलाफ किया है। उनकी जासूसी किए जाने का सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि उनके हर फोन की टैपिंग और दिनचर्या की जासूसी की जाती है। जासूसी प्रकरण को लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास करार देते हुए राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उठाई।

पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा कि जासूसी केवल उनकी निजता का मामला नहीं है। विपक्ष के एक नेता के रूप में वे जनता की आवाज उठाते हैं और जासूसी जनता की उस आवाज पर हमला है। राहुल ने कहा कि पेगासस का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और राफेल की जांच रोकने के लिए भी इसे हथियार बनाया गया। राफेल मामले में एफआइआर से ठीक पहले सीबीआइ के निदेशक की फोन टैपिंग की गई और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इस कृत्य के लिए उनके पास एक ही शब्द है-देशद्रोह।

अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। राहुल ने कहा, सरकार इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही कि उसने पेगासस खरीदा है या नहीं, क्योंकि इसे तो केवल सरकारों को ही बेचा जा सकता है।

मैं खुली किताब हूं

राहुल ने कहा कि कई बार तो उनके मित्रों को बोला जाता है कि राहुल गांधी को बता दीजिए कि उनकी फोन की टैपिंग हो रही है। इतना ही नहीं उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी बताते हैं कि उन्हें अपने वरिष्ठों को यह बताना पड़ता है कि राहुल गांधी ने क्या-क्या कहा। ऐसी जासूसी से भयभीत होने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, 'मैं खुली किताब हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य सी बात है। भारत की राजनीति को आप समझना चाहते हैं। अगर आप भ्रष्ट हैं, चोर हैं तो आपको डर लगेगा और भ्रष्ट या चोर नहीं हैं तो मोदी जी से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, हंसी आएगी।'

12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मिले नए कुलपति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश के दर्जन भर केंद्रीय विवि को नए कुलपति मिल गए हैं। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की मंजूरी के बाद शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार देर रात इनके आदेश जारी कर दिए। फिलहाल जिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नए कुलपति मिले है, उनमें हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं।

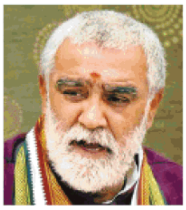
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के खाली पदों को जल्द भरने के संकेत दिए थे। पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है। फिलहाल विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्त की जो प्रक्रिया है, उनमें कार्यकारी परिषद या कोर्ट से मंजूरी लेना, सर्च कमेटी का गठन, विज्ञापन जारी करना, आवेदनों की जांच करना, चयनित अभ्यर्थियों के साथ इंटरेक्शन करना, सतर्कता क्लीयरेंस हासिल करना और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना शामिल है। मौजूदा समय में 22 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद खाली पड़े थे। इस आदेश के बाद अभी भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति होनी बाकी है। जिसमें जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। मंत्रालय ने इन बाकी बचे विश्वविद्यालयों में भी जल्द ही कुलपति की नियुक्ति के संकेत दिए है। इन दौरान जिन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की गई है, उनमें नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय शामिल हैं। सूत्रों की मानें तो शिक्षा मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने की तैयारी में है।

आइसक्रीम और कैंडी में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक पर लगेगी रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार बच्चों के उपभोग वाली वस्तुओं में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने जा रही है। ऐसा उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते हो रहा है। एक जनवरी, 2022 से आइसक्रीम, कैंडी और गुब्बारों में प्लास्टिक स्टिक के इस्तेमाल पर रोक होगी। पर्यावरण मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर आगामी एक जनवरी से रोक लग जाएगी। उनके उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक होगी।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 22 वृक्ष स्थानांतरित हुए : राजधानी दिल्ली के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 22 विरासती प्राचीन वृक्षों को बदरपुर इको पार्क में स्थानांतरित किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के नजदीक कार्य चल रहा है। इसके तहत त्रिकोणीय संसद भवन, उससे लगा केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास और उप राष्ट्रपति के आवास बनाए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में वृक्षों को स्थानांतरित करने की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में दी।

दिसंबर तक भूकंप की सूचना देने वाले 35 और सेंटर : जमीन के भीतर होने वाली हलचल पर नजर रखने के लिए नेशनल सेंटर फार सिस्मोलाजी (एनसीएस) दिसंबर तक 35 नए सेंटर स्थापित कर देगा। इससे देश को धरती के भीतर होने वाली गतिविधियों और भूकंप की पूर्व सूचना देने वाले सेंटरों की संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी। यह जानकारी भू विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को दी है। उन्होंने बताया कि इस तरह के अत्याधुनिक केंद्रों की संख्या मार्च 2026 तक बढ़ाकर 250 कर दी जाएगी।


अश्विनी चौबे। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

जल्द मिलेगी मित्रा को सरकार की स्वीकृति

देश में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (मित्रा) की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेने की प्रक्रिया तेज है, जल्द ही इसमें सफलता मिल जाएगी। 2021-22 के केंद्रीय बजट में इन पार्कों की स्थापना का प्रविधान है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने यह जानकारी लोकसभा को दी है। उन्होंने बताया कि आगामी तीन वर्षों में देश में सात ऐसे पार्कों की स्थापना की जानी है। इन पार्कों से बुनकरों और कपड़ा कारोबार को भारी लाभ होगा।

न्यूज गैलरी

अमित शाह की पूर्वोत्तर के सभी सीएम के साथ बैठक आज

शिलांग : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे। मेघालय में उमियम में नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एनईएसएसी) के मुख्यालय में आयोजित बैठक में पूर्वोत्तर के राज्यों में कानून व्यवस्था व कोरोना समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। (आइएएनएस)

नौसेना प्रमुख कल रूस जाएंगे

नई दिल्ली : नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह रविवार को रूस जाएंगे और सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 325वें रूसी नौसेना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय युद्धपोत आइएनएस तबार गुरुवार को ही सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया है। (प्रेट्र)

मणिपुर के पत्रकार रिहा

इंफाल : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) में गिरफ्तार पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को मणिपुर की साजवा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। इंटरनेट मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। (एएनआइ)

'बूथ कैप्चरिंग व फर्जी वोटिंग की कोशिशों से कड़ाई से निपटा जाए'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग की किसी भी कोशिश से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि इससे कानून का शासन और लोकतंत्र प्रभावित होता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने झारखंड में पोलिंग बूथ पर दंगा करने के एक दोषी की अपील खारिज कर दी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वोटिंग की आजादी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। पीठ ने कहा, 'निर्वाचन प्रणाली का सार मतदाताओं की आजादी सुनिश्चित करना होना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र होकर अपनी पसंद के मुताबिक मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।'

शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में गोपनीयता जरूरी है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में गोपनीयता बरकरार रखना अनिवार्य है। लोकतंत्र में जहां प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, वहां यह सुनिश्चित करना अहम है कि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सके। अगर उसका वोट उजागर होगा तो उसे प्रताड़ित किया जाएगा। पीठ ने कहा, लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। चुनाव ऐसी व्यवस्था है जो अंततः लोगों की इच्छा को दर्शाती है। लिहाजा किसी को भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के अधिकार में कटौती करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।


सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने लक्ष्मण सिंह की याचिका खारिज कर दी जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 147 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि सिंह को सुनाई गई छह महीने की सजा के खिलाफ राज्य ने अपील करने में रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए यह मामला वहीं का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा के एक सदस्य द्वारा भी ताकत का इस्तेमाल दंगे के तौर पर स्थापित होता है।

91 के आर्थिक संकट बाद आगे की राह और भी चुनौतीपूर्ण : मनमोहन

उदारीकरण के 30 साल

- कहा-भारतीयों के सम्मानजनक जीवन के लिए वरीयताओं को नए सिरे से जांचें

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि 1991 के आर्थिक संकट के मुकाबले आगे की राह और भी चुनौतीपूर्ण है। सभी भारतीयों के सम्मानजनक जीवन के लिए हमें वरीयताओं को नए सिरे से जांचना होगा।

आर्थिक उदारीकरण के 30 साल पूरे होने पर मनमोहन सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की विभीषिका से वह बेहद आहत हैं। लाखों भारतीयों और उनकी आजीविकाओं की क्षति हुई है।

बतौर वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने बजट भाषण में विक्टर ह्यूगो के हवाले से कहा था, 'जिस विचार का समय आ गया है उसे धरती पर कोई ताकत नहीं रोक सकती है।' उन्होंने कहा कि 30 साल बाद एक देश के तौर पर हमें राबर्ट फ्रास्ट की कविता को याद करना चाहिए, 'मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं, और आराम करने से पहले मीलों का फासला तय करना है।' सिंह ने कहा कि उदारीकरण के शुरू होने के बाद से अब आगे की राह और भी चुनौतीपूर्ण है। अभी खुशी मनाने या आराम करने का वक्त नहीं है, बल्कि आत्मदर्शन और विचार करने का वक्त है। हमें एक देश के तौर पर अपनी वरीयताओं को फिर से जांचना होगा, चूंकि प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य और सम्मानित जीवन को सुनिश्चित करना है।


रखी बात : मनमोहन सिंह फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 30 साल पहले 1991 में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम सुधारों की राह चुनी थी और देश की आर्थिक नीति को उससे नई राह मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों से विभिन्न सरकारों ने इसी राह पर चलकर तीन अरब डालर की अर्थव्यवस्था का सपना देखा है और अपना देश दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 30 करोड़ भारतीयों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सका है। हजारों-लाखों नई नौकरियां सृजित हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अपने कई साथियों के साथ सुधार की प्रक्रिया में भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला।

बांबे हाई कोर्ट ने स्टेन स्वामी की तारीफ में की गई टिप्पणी वापस ली

जेएनएन, नई दिल्ली : बांबे हाई कोर्ट की जस्टिस एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एल्गार परिषद मामले में आरोपित फादर स्टेन स्वामी की तारीफ में की गई मौखिक टिप्पणी वापस ले ली है। स्टेन स्वामी का हाल ही में गंभीर बीमारी से निधन हो गया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की ओर से हाई कोर्ट में पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को स्टेन स्वामी को याद करते हुए कहा था कि कानूनी मामलों से इतर समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए वह उनकी प्रशंसा करता है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनका निधन हो जाएगा।

एनआइए के खिलाफ बनाई जा रही है नकारात्मक छवि : शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सिंह ने कहा कि एनआइए के खिलाफ नकारात्मक छवि बनाई जा रही है और इससे जांचकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जस्टिस शिंदे ने खुली अदालत में यह टिप्पणी की और मीडिया में व्यापक रूप से इसकी रिपोर्टिंग हुई।

जल संचय

तालाबों व जलाशयों की पांचवीं देशव्यापी गणना में स्थिति उजागर, गांवों में सिंचाई लायक नहीं 53 हजार से अधिक तालाब

गांव के तालाबों में भारी अतिक्रमण, राज्यों को हटाने के निर्देश

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

देश के तालाबों और जलाशयों की पांचवीं गणना के आंकड़ों से इस बात का पता चला है कि देश में 53 हजार से अधिक तालाब व जलाशय सिंचाई के काबिल नहीं हैं। उनमें गाद भरी होने, पानी के अभाव और पानी खारा होने की वजह से उनका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं हो पा रहा है। कई राज्यों में ग्राम समाज की जमीनों पर बने तालाबों पर कब्जा होने की वजह से भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा गया है। इन तालाबों के पुनरुद्धार के लिए केंद्र ने दो हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

देश में परंपरागत पुराने तालाबों व जलाशयों के पानी से खेती में सिंचाई होती है, लेकिन देखरेख और रखरखाव के अभाव में इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने इन जलाशयों व तालाबों की हालिया गणना कराई, जिसके तहत पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5,16,303 तालाब व जलाशय हैं। लोकसभा में पूछे एक लिखित सवाल के जवाब में मंत्रालय ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि 53 हजार से अधिक जलाशयों की हालत बुरी है। ज्यादातर की सफाई न होने से उनमें गाद भरी हुई है, जिसमें या तो पानी नहीं है और है तो बहुत कम। ये सिंचाई के काम नहीं आ पा रहे हैं।

- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल पांच लाख से अधिक तालाब व जलाशय
- इन तालाबों के पुनरुद्धार के लिए केंद्र ने दो हजार करोड़ रुपये किए हैं मंजूर


देश में परंपरागत पुराने तालाबों व जलाशयों के पानी से खेती में सिंचाई होती है। फाइल

राज्य का विषय होने के नाते इसके लिए राज्य सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। केंद्र सरकार भी इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय मदद देती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों व जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए रिपेयर, रिनोवेशन और रेस्टोरेशन (आरआरआर) स्कीम शुरू की है। यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी देने के लिए शुरू की गई है। मौजूदा तालाबों से सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा सकता है। इस मंत्रालय के अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय इस दिशा में विशेष योजनाएं चला रहा है। मनरेगा के मार्फत भी पुराने तालाबों की साफ-सफाई और जलाशयों के तटबंध बनाए जा रहे हैं। गर्मी के महीनों में तालाबों के सूख जाने से पर उनकी गाद भी निकाली जा रही है। तालाबों में पानी भरने के नाले व नालियां भी साफ की जाती है। मनरेगा के मार्फत जल संरक्षण की दिशा में सर्वाधिक कार्य कराए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के 2,228 तालाबों की सफाई और तटबंध बनाने के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए। तालाबों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए भी राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों पर हुए नाजायज कब्जे को हटाना भी सरकार की प्राथमिकता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी



1 अगस्त से राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते अप्रैल के मध्य से ही आम लोगों के लिए इसे बंद कर दिया गया था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 24 जुलाई, 2021

सिद्धू ने संभाली कुर्सी, लौट कर 'बेअदबी' पर आए

दिखाए तेवर ▶ नए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने मंच से 10 बार लिया अपना नाम, किसी अन्य का जिक्र नहीं

सिद्धू के व्यवहार से हैरान व असहज नजर आए मंत्री, कैप्टन से बनाए रखी दूरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़


चंडीगढ़ में शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस भवन में कार्यक्रम के दौरान बातचीत करते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। संजय चिल्डियाल

पिछले साल मोगा में हुई ट्रैक्टर रैली के बाद पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल लिया। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने पहली बार मंच से पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंच का नजारा जरूर कुछ बदला हुआ था, लेकिन सिद्धू नहीं बदले।

बरगाड़ी बेअदबी के पुराने मुद्दे के साथ-साथ उन्होंने महंगी बिजली व शिक्षकों-डाक्टरों के धरने पर अपनी ही सरकार को घेरा और फिर अकालियों को भी आंखें दिखाईं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से दूरी बना कर चल रहे सिद्धू ने मंच से भाषण के दौरान भी उनका नाम लेने से परहेज किया। उन्होंने अमरिंदर समेत किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं लिया, जबकि अपना नाम दस बार लिया। 18 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने एक बार 'सीएम साहब' जरूर कहा। वहीं, कैप्टन ने अपने भाषण में तीन बार सिद्धू का नाम लिया। वहां बैठे मंत्री व अन्य नेता सिद्धू के इस व्यवहार से हैरान और असहज नजर आए। सिद्धू के साथ चार कार्यकारी अध्यक्षों कुलजीत नागरा, सुखमिंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और संगत सिंह गिलजियां ने भी जिम्मेदारी संभाली। सिद्धू ने कहा, 'मसला प्रधानगी का नहीं है। मसला यह है कि किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं। मसला यह है कि ईटीटी शिक्षक, डाक्टर, बस ड्राइवर, कंडक्टर धरना दे रहे हैं। मसला यह है कि मेरे गुरु की बेअदबी हुई है। जिस दिन मेरे गुरु का इंसाफ होगा, उस दिन समझूंगा पंजाब का कार्यकर्ता जिंदा है।'

सिद्धू ने 2017 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रचार अभियान के नारे 'चाहता है पंजाब' पर तंज कसते हुए कहा-'पूछता है पंजाब- नशे के मगरमच्छ कहां है। बिजली समझौते का सच क्यों नहीं सामने लाया जाए।' भाषण के अंत में सिद्धू ने कहा, 'दिल्ली माडल के परखच्चे उड़ा देंगे। अब केवल पंजाब का माडल चलेगा। मुझे ज्यादा तो नहीं बोलना था, लेकिन जो बोलना था, वह विस्फोटक बोलना था। कहा कि 15 अगस्त से उनका बिस्तर कांग्रेस भवन में ही लगेगा।' उन्होंने मंत्रियों से अपील की कि वे भी तीन घंटे कांग्रेस भवन में बैठा करें।

कैप्टन ने तीन बार लिया सिद्धू का नाम, बोले- सियासत में साथ चलेंगे : कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 'सियासत में मैं और नवजोत सिंह सिद्धू साथ चलेंगे। मैंने सिद्धू के पिता भगवंत सिंह से सियासत सीखी है। उस समय सिद्धू छह साल के थे और उछलते-कूदते फिरते थे। सोनिया गांधी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह सिद्धू को प्रधान बना रही हैं। मैंने बाहर आकर कह दिया था कि पार्टी जो फैसला करेगी, वह उसका सम्मान करेंगे। कहा, कार्यकर्ता नए अध्यक्ष का पूरा समर्थन करें। शिअद पर मुझे भरोसा नहीं है और आम आदमी पार्टी तो पाकिस्तान के साथ भी गठजोड़ करती रहती है।

कैप्टन को नमस्कार बोल निकले सिद्धू, प्रियंका के कहने पर पांच मिनट बाद वापस आए

नाश्ते की टेबल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ फोटो में बैठे नजर आ रहे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर यह दिखाने का प्रयास जरूर किया गया कि दोनों के बीच मतभेद खत्म हो गए हैं, लेकिन इस मेज पर सिद्धू को लाने में एक बार फिर से हाई कमान के पसीने छूट गए। चाय का कप रिश्तों के बीच जमी बर्फ को पिघला नहीं सका। पदभार ग्रहण करने से पहले मुख्यमंत्री की ओर से पंजाब भवन में रखी चाय पार्टी में सिद्धू पहले ही पहुंच गए थे। 10 बजकर 22 मिनट पर कैप्टन पहुंचे। इसके 13 मिनट बाद चाय पार्टी शुरू होने से पहले ही सिद्धू उन्हें नमस्कार कह कर चले गए। वह विधायकों के साथ बात करने लगे। मुख्यमंत्री ने उनके बारे में पूछा तो बताया गया कि सिद्धू वापस चले गए हैं। कैप्टन के सहयोगियों ने पंजाब प्रभारी हरीश रावत से पूछा तो उन्होंने बताया कि सिद्धू नीचे समारोह में हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सिद्धू लौट गए हैं तो रावत खासे नाराज दिखे। उन्होंने तुरंत सिद्धू को फोन किया और लौटने को कहा। पता चला कि सिद्धू ने इस बारे में ना नुकर की। रावत ने तुरंत प्रियंका गांधी को फोन कर सारी बात बताई और उनसे कहा कि वह सिद्धू से बात करें। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी के कहने पर ही सिद्धू दस मिनट बाद फिर से लौट आए। सिद्धू के चेहरे पर अलग ही हंसी थी। लौटते ही उन्होंने कैप्टन को फिर से नमस्कार किया और कहा कि उनके आने की उन्हें खुशी है। कैप्टन ने कहा कि दिखाई नहीं दे रहे थे तो सिद्धू ने कहा कि अरदास करने गए थे। वह कैप्टन के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठने लगे तभी खेल मंत्री राणा सोढी ने कैप्टन के साथ वाली कुर्सी पर बैठने की सलाह दी। वह तुरंत ही कैप्टन के साथ वाली कुर्सी पर लौट आए।

उत्तराखंड कांग्रेस में असंतोष, नवप्रभात और किशोर रूठे

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड कांग्रेस में हालिया बदलाव से पार्टी के भीतर असंतोष सतह पर भी दिखने लगा है। खासतौर पर पांच अध्यक्षों के फार्मूले को लेकर उनमें रोष है। धारचूला विधायक हरीश धामी के बीते रोज नाराजगी जताने के बाद शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवप्रभात ने मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को दूरभाष पर इसकी जानकारी भी दी। नवप्रभात संगठन में हालिया बदलाव से नाखुश हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी बदलाव के इस फार्मूले से सहमत नहीं दिख रहे हैं। इस मामले में उन्होंने नई दिल्ली में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से मुलाकात भी की।

कांग्रेस हाईकमान ने बीते रोज प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी सौंपी। नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। पार्टी ने साथ में 10 कमेटी भी गठित की हैं। बदलाव के जरिये सबको साथ लेने की पार्टी की कोशिशों को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नवप्रभात पांच अध्यक्षों बनाने के पार्टी के कदम से खफा हैं।

खिंचे-खिंचे से हैं किशोर : पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी पांच अध्यक्ष बनाने के फार्मूले से सहज नहीं हैं। दिल्ली में मौजूद किशोर ने शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से मुलाकात कर इस फार्मूले से पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में उन्हें जानकारी दी। बीते रोज कार्यकारी अध्यक्ष पद पर कुछ नाम और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफे की चेतावनी देने वाले धारचूला विधायक हरीश धामी का रुख शुक्रवार को बदला नजर आया।

जिसके नेतृत्व में चुनाव, वही तय करे मेनिफेस्टो

पार्टी में हुई इस कवायद को चुनाव से पहले खींचतान का नया अध्याय शुरू होने के तौर पर देख रहे नवप्रभात ने बड़ा कदम उठाया। बीते रोज सौंपी गई प्रदेश कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से ही उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने जा रही है, मेनिफेस्टो तय करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। लिहाजा उन्हें ही कमेटी तय करने देनी चाहिए। संपर्क करने पर उन्होंने पद छोड़ने और प्रभारी से दूरभाष पर बात करने की पुष्टि की। नवप्रभात को कोर कमेटी समेत अन्य दो कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

बसपा के मंच से भगवान श्रीराम और ब्राह्मणों का हुआ यशोगान

जागरण संवाददाता, अयोध्या


अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीशचंद्र मिश्र। प्रेट्र

स्थापित सत्य है कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं और इसी सत्य के आधार पर शुक्रवार को रामनगरी में एक और सियासी बदलाव का सूत्रपात होता दिखा। अपने राजनीतिक पूर्वजों की रीति-नीति से इतर बहुजन समाज पार्टी की नई छवि के निर्माण का प्रयास साफ दिखा। बसपा ने भले ही मिशन 2022 का शंखनाद किया हो, लेकिन जिस तरह मंच पर श्रीराम का जयघोष और ब्राह्मणों का यशोगान हुआ, उसमें नए सियासी समीकरणों को साधने का संकल्प दिखा।

प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की विषयक विचार गोष्ठी को संबोधित करने रामनगरी पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद सतीशचंद्र मिश्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बसपा का गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है और इसी के सहारे पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। उनके निशाने पर भाजपा रही। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर वर्षों से चंदा मांगने वालों ने कभी हिसाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए डेढ़ साल से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी तक मंदिर की नींव भूमि के ऊपर नहीं आ सकी है। ब्राह्मणों की एकजुटता और सर्वसमाज के सहयोग से 2022 में बसपा की सरकार बनने के बाद ही राममंदिर निर्माण गति पकड़ेगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने रामलला को राजनीति के चश्मे से देखा। रामलला का दर्शन करने से पहले क्या भाजपा से अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज की स्थिति ठीक नहीं है। सत्ता की चाबी लेने के लिए ब्राह्मणों को एकजुट होने के साथ भाईचारा मजबूत करना होगा, क्योंकि ब्राह्मण सबके लिए कार्य करने वाला होता है। पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ब्राह्मणों के साथ सर्वसमाज के उत्थान का कार्य किया है। राजनीति के साथ-साथ शासन और प्रशासन के उच्च पदों पर ब्राह्मणों की उपस्थिति दर्ज करवाई है। 2005 में ब्राह्मण समाज के अभिनंदन से प्रसन्न होकर बहनजी ने ही नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। आज मुठभेड़ के नाम पर ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। संबोधन का समापन उन्होंने जय श्रीराम-जय परशुराम के नारे से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकथा मर्मज्ञ पं. राधेश्याम शास्त्री ने की तथा संचालन पूर्व मंत्री नकुल दुबे व कार्यक्रम संयोजक करुणाकर पांडेय ने किया। कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व सतीशचंद्र मिश्र ने रामलला, हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन के साथ सरयू आरती और नदी का दुग्धाभिषेक किया।

भाजपा से दुश्मनी का कोई इरादा नहीं : चिराग

जागरण टीम, बेतिया/मोतिहारी : चाचा पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने के बाद भी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का भाजपा से मोहभंग नहीं हुआ है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के बाद उनके स्वजनों से मिलने जा रहे चिराग पासवान मोतिहारी में थोड़ी देर के लिए रुके। उन्होंने कहा कि उनका भाजपा से दुश्मनी का कोई इरादा नहीं है। जब चाचा ने धोखा दे दिया तो भाजपा पर क्या टिप्पणी करें। संगठन को और अधिक मजबूत बनाना है। चिराग ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राज्य में जिस सुशासन का दावा किया जाता है, मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा कर उसकी हकीकत जान लें। शराबबंदी के बाद से राज्य में इसकी तस्करी बढ़ गई है। जहरीली शराब बनने और इसके सेवन से लोग लगातार मर रहे हैं।

पश्चिम चंपारण के लौरिया और रामनगर प्रखंड में जहरीली शराब से मृत लोगों के स्वजनों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार की विफलता के कारण जहरीली शराब से मौतें हुईं। शराबबंदी है तो शराब कैसे पहुंची?

बसपा के घर में सेंध लगाएंगे रामदास आठवले

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

जनाधार का विस्तार

- **26** सितंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में निकालेंगे बहुजन कल्याण यात्रा, सभी मंडल मुख्यालयों पर करेंगे सभा
- **26** नवंबर को लखनऊ में होगी विशाल रैली, नड्डा और योगी को भी किया जाएगा आमंत्रित


रामदास आठवले। फाइल/इंटरनेट मीडिया

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुणा-भाग तेज हो गया है। बसपा फिर से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटी है तो भाजपा के सहयोगी के रूप में आरपीआइ प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले उत्तर प्रदेश के हर जिले में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को राजग की ओर मोड़ने में जुटेंगे। पार्टी ने प्रदेशभर में बहुजन कल्याण यात्रा निकालने का फैसला लिया है, जो 26 सितंबर से गाजियाबाद से शुरू होगी और 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन लखनऊ में समाप्त होगी।

केंद्रीय मंत्री आठवले ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उनके हित में लिए गए फैसलों से अवगत कराना है। साथ ही समाज के लोगों को ऐसे दलों से सतर्क भी करना है, जो राजनीति तो उनके नाम पर करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके हित में कोई काम नहीं करते है। आरपीआइ का दावा है कि उत्तर प्रदेश में उसका पहले से ही बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय पार्टी के 17 विधायक होते थे।

आरपीआइ के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता के मुताबिक बहुजन कल्याण यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी। इस दौरान प्रत्येक मंडल में एक रैली की जाएगी, जिसे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले संबोधित करेंगे। यात्रा का समापन संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को होगा। इस दौरान लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन होगा। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया जाएगा। पार्टी ने इस बीच प्रदेश में यात्रा को लेकर पहले दौर की अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी ने इस बीच अपने सदस्यता अभियान को भी गति दी है।

सहमति बनी तो कुछ सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी आरपीआइ

आरपीआइ की तैयारी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की भी है। पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा के साथ सहमति बनने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। राजग का सहयोगी दल होने के चलते भाजपा के शीर्ष स्तर को इस इच्छा से अवगत कराया गया है, जिस पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इसके बाद से ही उत्साहित है। बहुजन कल्याण यात्रा की योजना को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

तृणमूल संसदीय दल की चेयरपर्सन चुनी गईं ममता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

रणनीति

- केंद्रीय राजनीति में एक बार फिर पांव जमाने की कोशिश में हैं बंगाल की मुख्यमंत्री
- टीएमसी सुप्रीमो को दोनों सदनों के सांसदीय दल का अध्यक्ष बना तृणमूल ने चली चाल

बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है। शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मीडिया में इसकी घोषणा की।

डेरेक ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सर्वसम्मति से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। बता दें कि ममता सात बार सांसद रह चुकी हैं और लगातार तीन बार बंगाल की सीएम बनी हैं। बताया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा में तृणमूल संसदीय दल की प्रमुख ममता होंगी। इसे राष्ट्रीय राजनीति में पैठ बनाने की तृणमूल की रणनीति का है अहम हिस्सा माना जा रहा है।

डेरेक ने कहा कि पार्टी प्रमुख के अनुभव को देखते हुए रणनीतिक रूप से उनके अनुभव को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें संसदीय दल का नेता बनाने का निर्णय लिया है।

शांतनु सेन को निलंबित किए जाने पर केंद्र सरकार पर बोला हमला : इसके साथ ही डेरेक ने आज राज्यसभा के पार्टी सदस्य शांतनु सेन को निलंबित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर टीएमसी के दो सांसदों, कांग्रेस के तीन सांसदों और वामपंथी पार्टियों के दो सांसदों को सदन से निलंबित किया जा चुका है, लेकिन इस तरह से भाजपा उन लोगों का मुंह बंद नहीं करवा पाएगी। वे लोग भाजपा के जनता के हित के खिलाफ लिए गए फैसले को लेकर आवाज उठाते रहेंगे।

ममता की यात्रा से पहले दिल्ली पहुंचे सुवेंदु, शाह के साथ की बैठक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- नेता प्रतिपक्ष ने कहा, चुनाव बाद शुरू हुई हिंसा अब भी जारी
- दिल्ली में है भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल


नई दिल्ली में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एएनआइ

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पहले शुक्रवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंच गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। राज्य के भाजपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ है। सूत्रों के मुताबिक, सुवेंदु ने चुनाव बाद हिंसा को लेकर शाह को पूरी जानकारी दी है। बैठक के संबंध में सुवेंदु ने अधिक कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, यह जरूर कहा कि बंगाल में चुनाव बाद शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है और स्थिति बहुत चिंताजनक है। उन्होंने गृह मंत्री को हालात से अवगत कराया है। वह इस मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा बंगाल के बारे में और भी चर्चा हुई है, लेकिन वे उस संबंध में मीडिया को कुछ नहीं कह सकते हैं।

राज्य के भाजपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भी सुवेंदु के साथ दिल्ली में है। वे बंगाल की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुनाव बाद जारी हिंसा की शिकायत करने की योजना है। संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए, बंगाल के सभी भाजपा सांसद दिल्ली में हैं।

हाई कोर्ट में सुवेंदु ने दाखिल की याचिका : बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ सभी मामलों की सीबीआइ से जांच कराने का आग्रह किया है।

भाजपा ने उठाया सवाल, क्या 'जिन्ना' की राह पर चल रही हैं ममता : ममता बनर्जी द्वारा 16 अगस्त को 'खेला होबे' दिवस मनाने की घोषणा के बाद भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने सवाल किया है कि क्या ममता जिन्ना की हार पर चल रही हैं? बता दें कि 16 अगस्त 1946 को ही पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम देश की मांग पर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी। इसी दिन को ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। उस समय हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया था। इसी पर तंज कसते हुए भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस असल में तृणमूल लीग हो चुकी है।

भाजपा ने छात्रा के परिचय में धर्म बताए जाने पर उठाया सवाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

विवाद

- अमित मालवीय ने कहा- ममता की तुष्टीकरण की राजनीति नई ऊंचाई पर पहुंची
- बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुस्लिम छात्रा का सर्वोच्च अंक पाना कोई अविरल घटना

भाजपा ने उच्च माध्यमिक परीक्षा (बंगाल बोर्ड की 12वीं की परीक्षा) में सर्वोच्च अंक पाने वाली छात्रा के परिचय के तौर पर उसके धर्म का उल्लेख किए जाने पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्ष महुआ दास ने गुरुवार को उच्च माध्यमिक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा था कि इस बार सबसे ज्यादा अंक (500 में 499) जिसे प्राप्त हुए हैं, वह मुर्शीदाबाद की एक मुस्लिम छात्रा है। महुआ दास ने हालांकि उसके और उसके स्कूल के नाम का उल्लेख नहीं किया था। बाद में पता चला कि उस छात्रा का नाम रुमाना सुल्ताना है और वह मुर्शीदाबाद जिले के कांदी राजा मनिंद्र चंद्र गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है।

भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख और बंगाल में पार्टी के सह-पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति उस वक्त नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जब उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्ष ने सर्वोच्च अंक पाने वाली छात्रा के परिचय के तौर पर उसके धर्म का उल्लेख किया। छात्र-छात्राओं को और कितने दिनों तक यह सब सहन करना पड़ेगा?

वहीं, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुस्लिम छात्रा का सर्वोच्च अंक पाना कोई अविरल घटना नहीं है। जो लोग बार-बार यह कह रहे हैं कि मुस्लिम छात्रा प्रथम आई है, वे इसे लेकर इतने आश्चर्यचकित क्यों है? छात्रा किस धर्म से ताल्लुक रखती है, शिक्षा परिषद यह बताने की जिम्मेदारी न ले तो ज्यादा खुशी होगी। बहुत से लोगों का कहना है कि मुस्लिम छात्र- छात्राएं पहले भी बंगाल में अव्वल हुए हैं, लेकिन तब धर्म से उनका परिचय नहीं दिया जाता था। वे इसे राजनीति से ही जोड़कर देख रहे हैं।

बंगाल की सियासत

वाममोर्चा तथा कांग्रेस के गठबंधन में दरार पड़ने की आशंका, ममता 2011 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही सत्ता में आई थीं

टीएमसी व कांग्रेस में गठबंधन की संभावना बढ़ी

इंद्रजीत सिंह, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस की ओर से 21 जुलाई को आयोजित शहीद दिवस पर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के संदेश के बाद बंगाल में टीएमसी-कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। दूसरी तरफ सूबे में मौजूदा वाममोर्चा और कांग्रेस के रिश्ते में दरार पड़ने की आशंका है। बताते चलें कि वर्चुअल रैली में ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के मकसद से कांग्रेस के साथ वृहद गठबंधन का आह्वान किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोविड नियंत्रण में रहता है तो वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर्दियों में कोलकाता में होने वाली आम सभा में आमंत्रित करेंगी।

गत दिनों ममता की वर्चुअल रैली में पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से शामिल हुए थे। इसके बाद बंगाल कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि राज्य में फिर से तृणमूल के साथ उसके गठबंधन की संभावना प्रबल हो गई है। गौरतलब है कि ममता राज्य में 2011 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही सत्ता में आई थीं।

हाईकमान के निर्देश पर ही गठबंधन पर होगा फैसला : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बंगाल कांग्रेस तो कांग्रेस की एक शाखा है। लिहाजा हाईकमान के निर्देश पर ही गठबंधन के मुद्दे पर फैसला होगा। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी के साथ वृहद गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। मगर बंगाल में तृणमूल के साथ गठबंधन में कांग्रेस को क्या फायदा होगा, इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। इस स्थिति में वामपंथियों के साथ गठबंधन क्या होगा?

वामो-कांग्रेस गठबंधन में टूट की आशंका : दूसरी ओर कांग्रेस के साथ माकपा के गठबंधन के टूटने के आसार दिख रहे हैं। लिहाजा माकपा को भी एक वैकल्पिक रास्ते के बारे में विचार करना पड़ रहा है। वाममोर्चा के चेयरमैन बिमान बोस का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस हम लोगों के साथ तालमेल नहीं रखना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं। यह उनका फैसला होगा।

कांग्रेस के पास सौदेबाजी की कोई जगह नहीं

कांग्रेस के पास लोकसभा में राज्य से दो सीटें हैं, जबकि वामपंथी शून्य हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन होने पर भी कांग्रेस के पास इन दो सीटों के बाहर सौदेबाजी की कोई जगह नहीं है। पार्टी के एक धड़े का सवाल है कि गठबंधन तभी बनेगा जब लोकसभा और राज्यसभा में कुछ प्रमुख लोगों की सीटें सुरक्षित होंगी।

गुजरात कांग्रेस के कार्यक्रम से नदारद रहे हार्दिक पटेल

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

महंगाई व पेगासस जासूसी मामले में गुजरात कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजभवन ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल नदारद थे। इन दिनों हार्दिक कांग्रेस से अधिक पाटीदार आंदोलन के साथियों के साथ कार्यक्रम में व्यस्त हैं।

गुजरात प्रदेश कांग्रेस पिछले कई दिनों से प्रदेश में महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है, लेकिन हार्दिक पटेल कभी-कभार ही इनमें नजर आते हैं। हाल ही में सूरत जेल से रिहा हुए पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया की रिहाई के मौके पर हार्दिक अपने पुराने साथी पाटीदार नेताओं के साथ सूरत पहुंचे थे। आजकल वे पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेताओं के साथ अधिक नजर आ रहे हैं। इसका पहला कारण है कांग्रेस में उनकी उपेक्षा। युवक कांग्रेस से अलग हुए निखिल सवाणी ने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हार्दिक पटेल का राजनीतिक करियर खत्म करने का भी आरोप लगाया है।

नखिल अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को हार्दिक गांधीनगर से महज 60 किमी दूर हिम्मतनगर में एक कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन गांधीनगर में पेगासस जासूसी मामले में राज्यपाल आचार्य देवव्रत को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के साथ नजर नहीं आए। जब उनसे इस संबंध में पूछा गया तो उनका इतना ही जवाब मिला कि हिम्मतनगर में एक कार्यक्रम में थे।

आम के स्वाद को लेकर योगी का राहुल गांधी पर तंज

राब्यू, लखनऊ : आम के स्वाद को लेकर उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज किया है। योगी ने ट्वीट कर राहुल पर निशाना साधा। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो को टैग किया है जिसमें राहुल यह कह रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के नहीं, आंध्र प्रदेश के आम पसंद हैं। राहुल के इस कथन पर प्रतिक्रिया जताते हुए योगी ने लिखा कि 'आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है।'

30 फीसद की कमी आई है जम्मू-कश्मीर में होने वाली आतंकी हिंसा में। सक्रिय आतंकियों की संख्या 300 से घटकर 200 के करीब रह गई है। इनमें भी 60-70 विदेशी हैं।

न्यूज गैलरी

कश्मीर के प्रतिबंधित ब्लाग की जांच में जनसहयोग की अपील

श्रीनगर : इंटरनेट मीडिया पर आतंकी संगठनों के लिए कश्मीर में सक्रिय मुख्यधारा के लोगों की हिट लिस्ट जारी करने वाले ब्लाग के पकड़े गए कथित संचालकों की जांच में पुलिस ने शुक्रवार को जनसहयोग की अपील की है। पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) कश्मीर रेंज ने कहा कि पकड़े गए आरोपितों के साथ लेनदेन रहा है। (राब्यू)

पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत स्थिर

लखनऊ : लखनऊ के एसजीपीजीआइ में भर्ती उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है। शुक्रवार शाम को संस्थान के निदेशक प्रो.आरके धीमन ने बताया कि उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। वह खुद से आक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह से उनके फेफड़ों और खून में पर्याप्त आक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। (जासं)

आकाश मिसाइल का दोबारा किया सफल परीक्षण

बालेश्वर : भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर तट पर शुक्रवार को दोबारा आकाश मिसाइल की नई पीढ़ी एमपीएटीजीएम (फायर एंड फारगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल) का सफल परीक्षण किया। तीन दिनों के भीतर इस मिसाइल का लगातार दूसरी बार सफल परीक्षण किया गया है। (जासं)

लैंको इंफ्राटेक फ्राड अकाउंट घोषित किया

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने लैंको इंफ्राटेक और बसुंधरा ग्रीन पावर को फ्राड अकाउंट घोषित किया है। दोनों पर 589 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। बैंक ने सेबी को यह जानकारी दी है। लैंको पर कर्ज लिए गए धन को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आरोप है। (प्रेट्र)

परमबीर सिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज

मुंबई : मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है। उन पर ठाणे में एक बिल्डर के रिश्तेदार से वसूली करने और मोटी रकम के लिए अगवा करने का आरोप है। इसमें एक डीसीपी रैंक के अफसर और तीन के नाम शामिल हैं। (राब्यू)

सोपोर में 10 लाख के इनामी फैयाज समेत दो आतंकी ढेर

दुश्मनों को जवाब ▶ 12 घंटे चली मुठभेड़, दो असाल्ट राइफलें भी बरामद, लश्कर को दिया बड़ा आघात

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर में बारामुला जिले के सोपोर में गुरुवार की शाम को शुरू हुई मुठभेड़ सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी ढेर कर दिए। मुठभेड़ करीब 12 घंटे चली। मारे गए आतंकियों में 10 लाख का इनामी फैयाज अहमद वार उर्फ रुकना और शाहीन अहमद मीर उर्फ शाहीन मौलवी शामिल हैं। इस दौरान आतंकी ठिकाना बना मकान भी तबाह हो गया। मुठभेड़ स्थल से दो असाल्ट राइफलें व अन्य सामान मिला है। फैयाज की मौत सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है। वहीं, आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। वह सोपोर में जिंदा बचा लश्कर का एक स्थानीय आतंकी था।

गुरुवार की शाम पौने पांच बजे पुलिस ने सेना की 22 आरआर व सीआरपीएफ के जवानों के साथ तलाशी अभियान चलाया था। आतंकियों ने अपने ठिकाने के बाहर जवानों को घेराबंदी करते देखा मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षाबलों ने आसपास के मकानों से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आइजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों को कई बार आत्मसमर्पण का मौका दिया, लेकिन वह नहीं मानें। ऐसे में शुक्रवार सुबह आठ बजे दोनों आतंकियों के मारे जाने के साथ मुठभेड़ समाप्त हो गई।

रिसाइकल्ड आतंकी था फैयाज : फैयाज अहमद वार एक रिसाइकल्ड आतंकी था। वह 14 साल पहले 2008 में पहली बार हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बना था। सुरक्षाबलों का दबाव बढ़ने पर उसने हथियारों के साथ सरेंडर किया था और कुछ समय जेल में रहा। रिहा होने के बाद वह हिजबुल के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम करने लगा। पुलिस ने एक बार फिर उसे हथियारों संग पकड़ा और उसे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। जेल से रिहा होने के बाद वह कुछ समय तक पूरी तरह शांत बैठा, लेकिन मार्च, 2020 में वह फिर से लश्कर का हिस्सा बन गया।

एक दर्जन से अधिक हमले किए फैयाज ने : मार्च, 2020 में आतंकी बनने के बाद फैयाज अहमद ने लश्कर और ओवरग्राउंड वर्करों का नया नेटवर्क तैयार किया। इसके साथ ही सोपोर और उसके साथ सटे इलाकों में बीते एक साल के दौरान सुरक्षाबलों पर हुए अधिकांश हमलों में वह खुद शामिल रहा। उसने चार मार्च, 2020 को वारपोरा में पुलिसदल पर हमल किया था। इसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक समेत दो लोग मारे गए थे। इसके बाद बाद 18 अप्रैल, 2020 को उसने अहद बब चौराहे पर सीआरपीएफ के जवानों पर अपने साथियों संग घात लगाई। इस हमले में तीन सीआरपीएफ कर्मी और ईदीपोरा सोपोर का रहने वाला दानिश मंजूर मारे गए थे। माडल टाउन सोपोर में पहली जुलाई 2020 को हुए आतंकी हमले में भी वह शामिल था। इस हमले में एक सीआरपीएफ कर्मी और श्रीनगर के एचएमटी इलाके का रहने वाला बशीर अहमद खान मार गए थे। इसी साल 12 जून को उसने सोपोर म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्यों पर हमला किया था। इसमें दो काउंसलर और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी।



जम्मू-कश्मीर के बारामुला में सोपोर में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बल। प्रेट्र

एचएमटी हमले शामिल था शाहीन मौलवी

शाहीन अहमद मीर उर्फ शाहीन मौलवी श्रीनगर, लावेपोरा और नारबल के पास बीते एक साल के दौरान सुरक्षाबलों पर हमले की विभिन्न वारदात में शामिल रहा है। उसने ही बीते साल 26 नवंबर को खुशीपोरा, एचएमटी में सुरक्षाबलों एक दस्ते पर अपने साथियों संग घात लगाकार हमला किया था। इस हमले में दो सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। हमले के बाद वह कथित तौर पर एक सैन्यकर्मी की राइफल लेकर भाग गया था।

आजम या खैरी पोस्ट से किया जा रहा था संचालन

राज्य ब्यूरो, जम्मू

अखनूर के कानाचक्क सेक्टर में गुरुवार रात मार गिराए गए ड्रोन की साजिश व रूट का पता लगाने में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। सूत्रों की मानें तो यह ड्रोन अखनूर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गढ़खाल के रास्ते आया था। इसके ठीक सामने पाकिस्तान की आजम पोस्ट और साथ लगती खैरी पोस्ट है। माना जा रहा है कि यह ड्रोन इन्हीं दो पोस्टों में से एक से संचालित किया गया था। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना इस साजिश को अंजाम देना संभव नहीं हैं।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) व राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीमों ने जम्मू में ही डेरा डाल रखा है। एनएसजी की टीमें जहां पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, वहीं एनआइए हमले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

क्या है हेक्साकाप्टर?

हेक्साकाप्टर ऐसा ड्रोन होता है, जिसके रोटर की संख्या छह होती है। रोटर ड्रोन के ब्लेड की तरह काम करते हैं और हर रोटर पर पंखे होते हैं। चार रोटर वाले ड्रोन के मुकाबले छह रोटर वाले ड्रोन हवा में ज्यादा ऊपर जाते हैं और ज्यादा समय तक स्थिर रह सकते हैं। इनकी वजन उठाने की क्षमता भी अधिक होती है। ब्लेड की संख्या ज्यादा होने के कारण तेज हवा चलने पर भी इन्हें नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। कोई रोटर खराब होने पर भी यह हवा में स्थिर बना रह सकता है।

पाक वायुसेना दे रही ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण

गगन कोहली, राजौरी

पाकिस्तान सरहद पर संघर्ष विराम समझौते की आड़ में गुलाम कश्मीर में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों में भारत के खिलाफ ड्रोन फोर्स तैयार करने में जुटा है। इसके लिए बकायदा पाकिस्तानी वायु सेना के अधिकारी और विशेषज्ञ आतंकियों को ड्रोन उड़ाने से लेकर उससे हमले करने तक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। चीन में बने यह ड्रोन आतंकियों के लिए नया हथियार बन चुके हैं। यही वजह है कि बिना सरहद लांघे जम्मू-कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए सीमा पार से हथियार व विस्फोटक लदे ड्रोन लगातार भारतीय क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पार पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी वायु सेना के अधिकारियों और जवानों ने अपनी गतिविधियों को काफी तेज कर रखा है। ये अधिकारी सुबह से शाम तक शिविरों में जाकर आतंकियों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण में आतंकियों को बताया जा रहा है कि ड्रोन को कितनी ऊंचाई में उड़ाना है, ताकि वह पकड़ में न आ सके और किस ड्रोन के साथ कितना विस्फोट, हथियार और ड्रग्स को बांधकर भेजना है।

चीन में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे आतंकी : चीन सेना जिन ड्रोन का प्रयोग करती है, वही ड्रोन अब पाकिस्तान में आतंकी इस्तेमाल कर रहे है। आतंकियों तक यह ड्रोन पाकिस्तानी सेना, वायु सेना व उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ पहुंचा रही है। सूत्रों के अनुसार, यह ड्रोन काफी आधुनिक होने के साथ इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि यह बड़ी आसानी से 10 से 15 किलोमीटर उड़ान भर सकते हैं।

ठिकाने तक सामान पहुंचाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल : सूत्रों के अनुसार, सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के आका भारतीय क्षेत्र में मौजूद आतंकियों के मददगारों से पहले संपर्क करते हैं। मददगार जो जगह हथियार, ड्रग व विस्फोट गिराने के लिए तय करते है, उस लोकेशन को सीमा पार भेज दिया जाता है और फिर तय समय पर इस सामान को भेजा दिया जाता है। आतंकियों के मददगार इसे आतंकियों तक पहुंचाने में सक्रिय रहते हैं।

बंगाल में नौसेना के प्रतिष्ठानों के तीन किमी दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : भारतीय नौसेना ने कोलकाता समेत पूरे बंगाल में अपने प्रतिष्ठानों के तीन किलोमीटर के दायरे में कोई भी अधिकृत ड्रोन या मानवरहित विमान (यूएवी) उड़ाने पर शुक्रवार को पाबंदी लगा दी। नौसेना ने एक बयान में कहा, नौसेना इन इलाकों में बगैर अनुमति के उड़ाए जाने वाले यूएवी को जब्त करने या नष्ट करने का अधिकार रखती है। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जैश और लश्कर ड्रोन से भेज रहे हथियार

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) मुकेश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये जम्मू-कश्मीर में हथियार भेज रहे हैं। ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट और कई अन्य संवेदनशील इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए है। उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर पहले ही रणनीति बना ली गई है।

डेढ़ साल में ड्रोन से 30 बार गिराए गए हथियार : एडीजी मुकेश सिंह ने बताया कि डेढ़ साल में ड्रोन से 25 से 30 बार हथियार व अन्य सामान गिराया गया है, जिसे बरामद किया गया है। इसमें 16 एके-47, तीन यूबीजीएल (अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर), 34 पिस्तौल, 15 ग्रेनेड और 18 आइईडी (तीन बड़े और 15 छोटे) शामिल हैं। इसके अलावा चार लाख रुपये की करंसी भी बरामद हुई है। इससे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को पाकिस्तानी ड्रोन से दो बम गिराए गए थे। इन धमाकों में वायुसेना के दो कर्मी घायल हो गए थे।

किश्तवाड़ में आतंकी सरूरी के घर पर दबिश

जासं, किश्तवाड़ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुक्रवार को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मुहम्मद अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सरूरी के घर में दबिश दी। जांच एजेंसी ने यहां जांच पड़ताल की और उसके परिवार के लोगों से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि एनआइए ने गुरुवार को भी किश्तवाड़ के सरूर इलाके में जहांगीर के घर में जाकर जांच पड़ताल की थी। इसके बाद शुक्रवार को जहांगीर के शिमना इलाके वाले मकान में भी जाकर जहांगीर के परिवार लोगों से पूछताछ की। सुबह से ही एनआइए की टीम जहांगीर के मकान में पहुंच गई थी। मकान को चारों तरफ से सीआरपीएफ व पुलिस ने घेर रखा था। एनआइए ने क्या पूछताछ की है, इस संबंध कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्थानीय पुलिस अधिकारी भी इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। अलबत्ता, सूत्रों का कहना है कि किश्तवाड़ के और भी कई ठिकानों पर एनआइए की दबिश पड़ेगी। गौरतलब है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने पहली नवंबर 2018 को परिहार बंधुओं को मौत के घाट उतारा था। आतंकी जहांगीर सरूरी ही है।

23 बोडो उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण

गुवाहाटी, आइएएनएस : असम में नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ बोडोलैंड (एनएलएफबी) के 23 उग्रवादियों ने गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें संगठन का सरगना और शीर्ष कमांडर शामिल हैं। पश्चिमी असम के लालपानी में आयोजित एक कार्यक्रम में एनएलएफबी के स्वघोषित प्रमुख एम बाथा के नेतृत्व में 23 उग्रवादियों ने राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पिजुष हजारिका के सामने हथियार डाल दिए। हजारिका ने उग्रवादियों के मुख्यधारा में लौटने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के अनुरोध पर एनएलएफबी के सदस्य घर लौट आए हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक ट्वीट कर कहा कि आत्मसमर्पण एक स्वागत योग्य कदम है।

सिग्नल हुआ लाल तो खुद जाम होंगे ट्रेन के पहिये

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

नवाचार

- सहारनपुर-लखनऊ रेल मार्ग पर लगाई जाएगी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली
- देशभर में 37 हजार किलोमीटर रेल मार्ग पर यह सिस्टम लगाने की है योजना

तेज रफ्तार ट्रेन कई बार चालक की गलती या उसे झपकी आ जाने के कारण सिग्नल शूट कर जाती है लेकिन अब सेंसर आधारित नई स्वदेशी तकनीक इस पर विराम लगा देगी। अगर सिग्नल लाल हुआ और चालक ने ब्रेक नहीं लगाया तो भी ट्रेन के पहिये स्वत: ही जाम हो जाएंगे। ऐसे में हादसे की आशंका भी नहीं होगी। रेलवे की देशभर में 37 हजार किलोमीटर रेल मार्ग पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लगाने की योजना है। मुरादाबाद रेल मंडल में सहारनपुर से लखनऊ तक यह सिस्टम लगाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। विश्व के विकसित देशों में ट्रेनों का संचालन आधुनिक तकनीक से किया जाता है। इसमें चालकों को सिग्नल देखने की आवश्यकता नहीं होती है, इंजन में लगे सिस्टम पर सिग्नल की जानकारी मिलती है। कई देशों में घने कोहरे में भी ट्रेनों का संचालन निर्धारित गति से किया जाता है। आधुनिक तकनीक के जरिये ट्रेन दुर्घटना की आशंका को न्यूनतम किया जा सकता है।

इंटरनेट और सेंसर आधारित है स्वदेशी तकनीक: आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की कई कंपनियों ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के उपकरण बनाए हैं। रेलवे की जांच में यह सिस्टम खरे उतरे हैं। सिस्टम को आप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से प्रस्तावित मार्ग के सभी स्टेशनों के सिग्नल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जो इंटरनेट व मोबाइल नेटवर्क द्वारा संचालित होगा। सेंसर आधारित यह सिस्टम ट्रेन के इंजन में लगाया जाएगा, जो ब्रेक सिस्टम से जुड़ा होगा।

एक स्टेशन पहले ही मिलेगी जानकारी: स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लग जाने के बाद ट्रेन के चालक को अगले स्टेशन के सिग्नल की स्थिति पहले ही पता चल जाएगी। इससे सुपर फास्ट ट्रेन चालकों को ट्रेन चलाने में आसानी होगी।

मुरादाबाद में 550 किमी रेल मार्ग पर लगेगा सिस्टम

भारतीय रेलवे ने प्रथम चरण में 37 हजार किलोमीटर के प्रमुख रेल मार्ग पर यह सिस्टम लगाने की योजना तैयार की है। इस पर 30 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जम्मूतवी हावड़ा रेल मार्ग मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर सहारनपुर से लखनऊ तक साढ़े पांच सौ किलो मीटर रेल मार्ग पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लगाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। इस योजना को पूरा होने में पांच साल का समय लगेगा।

दो वर्षों से प्राकृतिक आपदाएं झेल रहा है कोंकण

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

प्राकृतिक सुंदरता का खजाना समेटे महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र पिछले दो वर्षों से प्राकृतिक आपदाएं झेलता आ रहा है। चार दिनों से हो रही मूसलधार बारिश ने इस क्षेत्र के भरते घावों को एक बार फिर कुरेद दिया है। कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में आई इस बाढ़ को इन्हीं क्षेत्रों में 2005 एवं 1967 में आई बाढ़ से भयावह बताया जा रहा है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को प्रमुख पर्यटन राज्य गोवा से जोड़ने वाली करीब 500 किमी. की सागरतटीय पट्टी कोंकण क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। मुंबई से गोवा की ओर सड़क मार्ग से जाते हुए बाईं ओर हरी-भरी पहाड़ियों के बीच महाड, पेण, खेण, चिपलूण जैसे शहर एवं छोटे-छोटे गांव साथ चलते हैं तो दाहिनी ओर कुछ दूर जाने पर समुद्र साथ-साथ चलता है। मुंबई से करीब पौने दो सौ किमी. का सफर तय करने के बाद बाईं ओर ही पोलादपुर के पहाड़ी रास्तों से महाराष्ट्र के हिल स्टेशन महाबलेश्वर पर जाया जा सकता है। समुद्र तल से 1,439 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस हिल स्टेशन से पांच नदियां कृष्णा, कोयना, वेरना, सावित्री एवं गायत्री निकलती हैं। इनमें कृष्णा देश की चौथी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश होते हुए 1400 किमी. का सफर तय कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अन्य चार नदियां भी महाराष्ट्र के बड़े हिस्से से गुजरती हैं। इसी महाबलेश्वर ने पिछले तीन दिनों में 1534.4 मिमी. बारिश रिकार्ड की है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। इसका असर यहां से निकलनेवाली नदियों एवं उन नदियों के मार्ग में पड़नेवाले कोंकण एवं पश्चिम महाराष्ट्र के नगरों-कस्बों में पड़ना स्वाभाविक है। सांगली में कृष्णा की बाढ़ ही कहर बरपा रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र का विशाल जल क्षमता वाला कोयना बांध भी इसी क्षेत्र में स्थित है। कोयना बांध से भी पिछले कुछ ही दिनों में 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है।

मुंबई सहित महाराष्ट्र के ज्यादातर बड़े शहर पेयजल के लिए कोयना जैसे बड़े बांधों में बरसात के दिनों में संचित जल पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए इन बांधों के क्षेत्र में पर्याप्त बारिश होना भी जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन क्षेत्रों में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होना विपदा का कारण बन गया है। मुसीबत का कारण सिर्फ पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात ही नहीं है। सागरतटीय क्षेत्र होने के कारण पिछले दो वर्ष में कोकण पट्टी ने दो बड़े तूफान भी सहे हैं। पिछले वर्ष आए निसर्ग तूफान से हुई बर्बादी से कोंकण उबर भी नहीं पाया था कि कुछ माह पहले आए टाक्टे तूफान ने भी इसी क्षेत्र को अपना निशाना बनाया। लोग अभी तक इन तूफानों में उजड़ चुके अपने घर भी नहीं दुरुस्त कर पाए हैं। यही क्षेत्र अपने स्वादिष्ट हापुस आमों एवं काजू के लिए जाना जाता है। देश को 80 फीसद स्ट्राबेरी महाबलेश्वर देता है। टाक्टे ने इन सारी फसलों को तबाह कर किसानों को नुकसान पहुंचाया था। इनका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर कोरोना के असर से भी कोंकण एवं पश्चिम महाराष्ट्र के जिले अभी बाहर नहीं आ सके हैं।



महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मूसलधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके बीच स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं और मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ा है। शुक्रवार को बरसात के बीच मरीज (व्हीलचेयर पर) की सहायता में जुटे लोग। एपी

नौसेना और वायुसेना ने संभाला मोर्चा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नौसेना एवं वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वायुसेना के चार हेलीकाप्टर चिपलूण एवं खेड में बचाव कार्य में लगे हैं। नौसेना का मुंबई स्थित पश्चिमी कमान अपनी सात बाढ़ राहत टीमों (एफआरटी) को राज्य प्रशासन की मदद के लिए उतार चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने मारे गए लोगों के स्वजन को दो लाख रुपये और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी पांच लाख रुपये मदद देने की घोषणा की है।

छह जिलों के लिए रेड अलर्ट: मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए बचाव के उपाय करने की सिफारिश की है। उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की।

बारिश की वजह से त्रिवेंद्रम राजधानी सहित कई ट्रेनें रद

राब्यू, नई दिल्ली : महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है। दक्षिण दिशा से दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनें रद करनी पड़ी हैं। इस वजह से वापसी दिशा में भी इन ट्रेनों को रद करने की घोषणा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैकों की नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे किसी तरह की परेशानी न हो।

ज्ञानवापी मामले में 27 को होगी निगरानी याचिका पर सुनवाई

जासं, वाराणसी : 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ, पंडित शोभनाथ व्यास, डा.रामरंग शर्मा तथा अन्य पक्षकारों ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने आदि को लेकर मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत में चल रही है। मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने विवादित स्थल की धार्मिक स्थिति के निर्धारण के लिए 10 दिसंबर, 2019 को अयोध्या रामजन्म भूमि की भांति पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा रडार तकनीक से भौतिक व पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील की। वादी तथा प्रतिवादी पक्ष की कई बार हुई बहस को सुनने और नजीर के अवलोकन के बाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) आशुतोष तिवारी की अदालत ने बीती आठ अप्रैल को वाद मित्र की अपील मंजूर कर ली। केंद्र व राज्य सरकार को पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) को आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

मतांतरण

खूंटी, रांची सिमडेगा समेत राज्य के कई हिस्सों में अवैध तरीके से बनाए गए हैं चर्च, कई जगह चल रहा है विवाद, बहला-फुसलाकर ग्रामीणों के घरों को बना दिया मतांतरण का केंद्र

गरीबों के लिए बने पीएम आवास को बना दिया चर्च

संजय कुमार, रांची

- कहीं स्कूल तो कहीं गोदाम के नाम पर जमीन हासिल कर बना दिए चर्च

झारखंड में ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर मतांतरण कराने का काम तो जारी है ही, जगह-जगह चर्च भी अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं। सरकारी जमीन से लेकर विवादित जमीन तक पर गांवों में चर्च बनाए गए हैं। इतना ही नहीं कई जगह सीधे-सादे ग्रामीणों को बरगला कर मतांतरण कराने वालों ने इंदिरा आवास और पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को उपलब्ध कराए गए आवासों को भी प्रार्थना घर और चर्च में तब्दील कर दिया है। हाल के दिनों में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कई घरों को बाहर से देखकर तो बताना भी मुश्किल है कि यह चर्च या उपासना स्थल है। बाहरी ढांचे में कोई परिवर्तन करने की बजाय इन घरों के भीतर यीशु की मूर्ति या क्रूस को रखा गया है। यहां नियमित अंतराल पर लोग जुटते हैं और प्रार्थना सभा के बहाने मतांतरण की गतिविधियां चलाई जाती हैं।

खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड के पंढरिया गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित एक ग्रामीण के घर को हेब्रोन प्रार्थना भवन में तबदील कर दिया गया है। इसी प्रखंड के एक अन्य गांव रायसिमला के पाहन टोली में बुधराम मुंडा के घर को भी विश्ववाणी चर्च में बदल दिया गया है, जिसका विरोध भी सरना समाज के लोगों ने किया है। इसी तरह रायसिमला गांव के पाहन टोली में आकृति धान नाम के ग्रामीण से गोदाम के नाम पर जमीन लेकर वहां चर्च बना दिया गया। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने चर्च में ताला लगा दिया है। दोनों पक्षों की ओर से इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया मुंडा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास मे चल रहे चर्च को खाली कराने के लिए जल्द ही जिला प्रशासन को आवेदन दूंगी। गलत तरीके से जमीन लेकर जहां भी चर्च बना है उसका विरोध होगा।

सीधे-सादे गांववालों को बनाया जाता है बेवकूफ: रांची की समाजसेवी प्रिया मुंडा का कहना है कि यहां भोले भाले व गरीब आदिवासियों की जमीन लेकर चर्च बनाए जा रहे हैं। सीएनटी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियां आदिवासियों की जमीन खरीद नहीं सकती हैं। इसलिए दान में देने की बात कागज पर लिखवाई जा रही है। ग्रामीणों से जमीन लेने के समय उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि बच्चों को पढा देंगे और कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन जमीन लेने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। प्रिया का कहना है कि जांच हो तो सैकड़ों चर्च अवैध निकलेंगे। विश्ववाणी और विलिवर चर्च तो ज्यादातर स्थानों पर गलत तरीके से ही बनाए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के खूंटपानी में तो स्कूल के नाम पर जमीन लेकर चर्च बना दिया गया।



खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के पड़ारिया गांव में अवैध तरीके से बनाया गया प्रार्थना केंद्र। जागरण

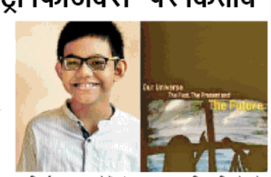
रांची में भी बने हैं अवैध चर्च

ईसाई मिशनरियां अब गांवों के साथ साथ शहरों में भी अवैध चर्च बनाकर लोगों को मतांतरित कराने में लगी हैं। एकल अभियान के राष्ट्रीय सह अभियान प्रमुख ललन शर्मा का कहना है कि पादरियों का गांवों में विरोध शुरू होने पर अब वे शहर की मलिन बस्तियों को निशाना बनाने लगे हैं। इन बस्तियों में कई जगहों पर अवैध रूप से तैयार चर्च दिख जाएंगे। रांची के ही एचईसी चेकपोस्ट के पास रेलवे की जमीन पर एक घर को चर्च बना दिया गया है। शहर की व्यस्त सड़क होने के बाद भी अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि यहां चर्च है। इस तरह के कई चर्च जगह-जगह बनाए जा रहे हैं।

कोलकाता के 10 साल के बच्चे ने लिखी 'एस्ट्रो फिजिक्स' पर किताब

बाल प्रतिभा

- रेयांश को पांच साल की उम्र से ही होने लगी थी अंतरिक्ष में रुचि
- पाइथागोरस प्रमेय से लेकर ब्लैक होल सिद्धांत तक का उसका ज्ञान परिवार के लिए भी अविश्वसनीय



द यूनिवर्स : द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नामक किताब लिखने वाले 10 साल के रेयांश। सौ. इंटरनेट मीडिया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

10 साल के रेयांश ने 'एस्ट्रो फिजिक्स' जैसे कठिन विषय पर किताब लिखकर सबको चकित कर दिया है। किताब का नाम 'द यूनिवर्स : द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर' है। रेयांश ने बताया कि जब मैं पांच साल का था, तब से मुझे अंतरिक्ष में रुचि होने लगी थी। मैं रात के आकाश को देखता और अपने आप से पूछता था कि प्रकाश के वे बिंदु क्या हैं? वे कैसे बने? और मैं यहां क्यों हूं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मैंने अलग-अलग खगोलीय किताबें पढ़नी शुरू कीं और कई अंतरिक्ष वीडियो देखे। 2019 में जब मैं सात साल का था तो किताबों और वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुए ज्ञान के साथ एक पुस्तक लिखने का फैसला किया था।

घरेलू वैक्सीन उत्पादकों से करार में देरी नहीं

सदन में जवाब ▸ सरकार ने लोकसभा को बताया, वैक्सीन की आपूर्ति के आर्डर के साथ अग्रिम भुगतान भी किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी से निपटने और टीकाकरण समेत उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार ने शुक्रवार को विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। सरकार ने बताया कि घरेलू वैक्सीन उत्पादकों के साथ करार करने में किसी भी तरह की देरी नहीं हुई और वैक्सीन की आपूर्ति का आर्डर देने के साथ ही कंपनियों को अग्रिम भुगतान भी किया गया।



लोकसभा में गरमाया संक्रमण का मामला। फाइल

लोकसभा में कांग्रेस के राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस की माला राय के लिखित सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 135 करोड़ डोज उपलब्ध होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण को पूरा करने का कोई निश्चित समय तय नहीं किया जा सकता, लेकिन इस साल दिसंबर इसके पूरा होने जाने की उम्मीद है।

एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार अब तक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9725.15 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इसमें टीके की खरीद के साथ ही उसे लगाने जैसी सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी शामिल है।

देश में उपलब्ध वैक्सीन का भंडारण सामान्य रेफ्रिजरेटर में: स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने बताया कि देश में अभी तक जितनी भी कोरोना रोधी वैक्सीन उपलब्ध है उसे रखने के लिए किसी खास तरह के रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। इनके लिए दो से आठ डिग्री तापमान वाला सामान्य रेफ्रिजरेटर ही पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि देश में अभी 296 वाक-इन-कूलर और 57,640 आइस-लाइंड रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हैं। वाक-इन-कूलर और आइस-लाइंड रेफ्रिजरेटर एक विशेष प्रकार के रेफ्रिजरेटर होते हैं, जिन्हें वैक्सीन, दवा, ब्लड सैंपल इत्यादि रखने के लिए डिजाइन किया जाता है।

67.6 फीसद लोगों में एंटीबाडी मिली

स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने कहा कि चौथे सीरो सर्वे में छह साल से अधिक उम्र के 67.6 फीसद व्यक्तियों में कोरोना एंटीबाडी पाई गई है। यह सीरो सर्वे 14 जून से छह जुलाई के बीच देश के 20 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 70 जिलों में कराया गया था। इसमें छह साल से ऊपर के कुल 36,227 शामिल थे।

कोरोना संक्रमितों में 11 फीसद 20 साल से कम उम्र के: भारती प्रवीण पवार ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों में 11 फीसद 20 साल से कम उम्र के थे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय दवा नियामक ने भारत बायोटेक को दो से 18 साल और कैडिला हेल्थकेयर को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है।

कोरोना से जटिलताओं का आकलन करना जल्दबाजी होगी: एक अन्य सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते फेफड़े में फाइब्रोसिस और थ्रोंबोटिक में वृद्धि जैसी जटिलताओं के बारे में राय बनाना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के ज्यादातर मामलों का संबंध कोरोना संक्रमण से पाया गया है।

राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन को बताया कि कुछ राज्यों ने कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए थे, लेकिन किसी में भी वैक्सीन की खरीद नहीं की जा सकी। बाद में राज्यों ने केंद्र को सूचना दी कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की सीधी खरीद में धन और लाजिस्टिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते एक मई से 20 जून तक टीकाकरण की गति धीमी पड़ी थी। इसकी गति को बढ़ाने के लिए ही केंद्र ने 21 जून से महाभियान चलाया।

कोरोना वैक्सीन पर राजनीति बंद हो: मांडविया ने विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं करें। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगें।

देश में 854 लोगों पर सिर्फ एक डाक्टर

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि देश में 854 लोगों पर एक एलोपैथिक डाक्टर और 559 लोगों पर एक नर्स उपलब्ध है। यह आंकड़ा पंजीकृत एलोपैथिक डाक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता पंजीकृत नर्सों की 70 प्रतिशत उपलब्धता मानकर निकाला गया है।

संसद के निचले सदन में एक लिखित जवाब में स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में पंजीकृत 12.68 लाख एलोपैथिक और 5.65 लाख आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने कहा कि अब तक की उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक देश में पंजीकृत नर्सिंग कर्मचारियों की संख्या कुल 32.63 लाख है, जिसमें 22.72 लाख पंजीकृत नर्स और 9.91 लाख पंजीकृत नर्स एसोसिएट्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डाक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें जिन जिलों में मेडिकल कालेज नहीं हैं, वहां केंद्रीय वित्तपोषण योजना के तहत जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज के रूप में अपग्रेड किया जाना शामिल है। इसके तहत तीन चरणों में 157 अस्पतालों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 47 मेडिकल कालेज संचालित हो गए हैं। **कोरोना से 4,18,987 मौतें हुईं:** स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने बताया कि देश भर में पिछले साल जनवरी से लेकर इस साल 22 जुलाई तक कोरोना वायरस से संक्रमण के चलते कुल 4,18,987 लोगों की मौत हुई है।

दूसरी लहर में आक्सीजन की मांग 9,000 टन तक पहुंची

भारती प्रवीण पवार ने सदन को बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में आक्सीजन की मांग 9,000 टन तक पहुंच गई थी। जबकि, महामारी की पहली लहर में एक दिन में सबसे अधिक 3,095 टन आक्सीजन की मांग हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल अगस्त में प्रतिदिन 5,700 टन आक्सीजन का उत्पादन हो रहा था, जो इस साल 13 मई को बढ़कर 9,690 टन प्रतिदिन तक पहुंच गया। 28 मई को केंद्र सरकार ने राज्यों को 10,250 टन आक्सीजन आवंटित किए थे।

आक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े केंद्र ने राज्य से नहीं मांगे : सिंहदेव

नईदुनिया, रायपुर : कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होने के केंद्र सरकार के जवाब पर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी आक्सीजन की कमी से मौत की जानकारी राज्य से नहीं मांगी। सिंहदेव ने संसद में जवाब के बाद ट्वीट किया-केंद्र सरकार एक दिन में मरने वालों की संख्या, कोमारबिडिटी (कोरोना के साथ अन्य बीमारी) के साथ मौत और उसके प्रकार जैसा डाटा मांगते हैं।

कोविड से रेलवे ने खोए अपने 2,903 कर्मी: कोविड की वजह से रेलवे ने 2,903 कर्मचारी-अधिकारी खोए हैं। इनमें से 2,782 दिवंगत कर्मियों के परिवारों को निर्धारित मुआवजा-सुविधाएं दी जा चुकी हैं। यह जानकारी शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि सेवाकाल में दिवंगत कर्मियों के स्थान पर उनके नजदीकी एक रिश्तेदार को नौकरी में लेने की नीति है।

24 घंटे में करीब चार कम हुए सक्रिय मामले

▸ कुल एक्टिव केस 4.05 लाख, इस दौरान सामने आए 35 हजार नए मामले

▸ पिछले 32 दिनों से दैनिक संक्रमण दर तीन फीसद से नीचे

जेएनएन, नई दिल्ली : कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पिछले एक दिन में सक्रिय मामलों में 3,881 की गिरावट आई है और कुल एक्टिव केस4,05,513 रह गए हैं, जो कुल मामलों का 1.3 फीसद है। इस दौरान 35,342 केस पाए गए हैं, जबकि एक दिन पहले 40 हजार से ज्यादा नए मामले मिले थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक दैनिक और साप्ताहिक संक्रमण दर पांच फीसद से नीचे बने हुए हैं। वास्तव में दैनिक संक्रमण दर तो पिछले 32 दिनों से तीन फीसद से नीचे है। मरीजों के उबरने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि, मृत्युदर में कमी नहीं आ रही है। पिछले कुछ दिनों से मृत्युदर 1.30 फीसद से ज्यादा बनी हुई है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 2.75 करोड़ डोज: मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी कोरोना वैक्सीन की 2.75 करोड़ डोज बची हुई हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक कुल 43.87 करोड़ डोज मुहैया कराई गई हैं। इन्हें जल्द ही 71.40 लाख डोज और उपलब्ध करा दी जाएंगी।

देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	35,342
कुल सक्रिय मामले	4,05,513
24 घंटे में टीकाकरण	54.76 लाख
कुल टीकाकरण	42.34 करोड़

बुधवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	35,342
कुल मामले	3,12,93,062
सक्रिय मामले	4,05,513
मौतें (24 घंटे में)	483
कुल मौतें	4,19,470
ठीक होने की दर	97.36 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.12 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.14 फीसद
जांचें (गुरुवार)	18,68,561
कुल जांचें	45.29 करोड़

गुजरात हाई कोर्ट ने तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

किया आगाह

▸ आरटी पीसीआर टेस्ट, मास्क तथा टीकाकरण पर सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत

▸ कोरोना से बच्चे प्रभावित न हों, इसके खास प्रबंध किए जाएं

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य सरकार को कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है। अदालत ने कहा कि आरटी पीसीआर टेस्ट, मास्क तथा टीकाकरण पर सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना से बच्चे प्रभावित न हों, इसके खास प्रबंध किए जाएं।

गुजरात उच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग को तलब किया था। पिछले काफी समय से अदालत में इस पर सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश विक्रम नाथ एवं जस्टिस भार्गव डी कारिया की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि तीसरी लहर से पहले टीकाकरण पर ध्यान ध्यान देना चाहिए। यह रोग वैसा नहीं है, जैसा हम समझते हैं। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनकी खास व्यवस्था की जानी चाहिए। डाक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स, दवा तथा वैक्सीन आदि की कमी लोगों को महसूस नहीं हो। अस्पतालों में पर्याप्त बेड की व्यवस्था कराएं। साथ ही आक्सीजन की कमी को भी शीघ्र दूर किया जाए। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर तथा कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में आवश्यक मेडिकल साधन उपलब्ध कराए जाएं। मास्क को लेकर राज्य सरकार को अभी और गंभीर होने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में लोग टीकाकरण को लेकर गंभीर नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं का ब्योरा तलब किया: हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वह प्रदेश में उपलब्ध तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण कोर्ट के समक्ष रखे। इस जानकारी में अलग से बाल रोगियों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को बताने के लिए भी कहा गया है।

वैक्सीन की तीसरी डोज भी लेना चाहते हैं डाक्टर, उठी मांग

संतोष शुक्ल, मेरठ

कोरोना की तीसरी लहर से पहले डाक्टरों में नई बेचैनी है। आइएमए हेल्थ वर्करों को नई लहर से पहले तीसरा डोज लगवाने की मांग उठा रहा है, जिससे वार्ड में ड्यूटी करते समय डाक्टरों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों के शरीर में पर्याप्त एंटीबाडी टाइटर रहे। आइएमए का कहना है कि फरवरी 2021 तक ज्यादातर डाक्टरों को दोनों डोज लग गई थी, लेकिन पांच माह बाद एंटीबाडी कम हो सकती है। ऐसे में पश्चिमी देशों की तरह यहां भी तीसरे डोज पर चर्चा उठी है। इस विषय पर आइसीएमआर ही गाइडलाइन जारी करेगा।

इंदौर ने प्रश्न उठाया, अब मेरठ में भी मांग: आइएमए इंदौर ने हेल्थ वर्करों को बूस्टर के रूप में तीसरी डोज लगाने की मांग उठाई है। मेरठ आइएमए चैप्टर भी दो बार चिकित्सकों के साथ बैठक कर चुका है। डाक्टरों ने बताया कि तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कभी उभर सकती है। वरिष्ठ फिजिशियन डा. तनुराज सिरोही के अनुसार फाइजर ने तीसरी डोज के लिए डब्ल्यूएचओ में आवेदन किया है। अंतरराष्ट्रीय शोध में पता चला है कि डेल्टा वायरस के प्रति टीके कम कारगर हैं। ऐसे में वैक्सीन की नई डोज देकर एंटीबाडी बढ़ाई जा सकती है।

पांच माह में घटने लगी एंटीबाडी

पांच माह बाद कई डाक्टरों में एंटीबाडी की मात्रा घटती मिली। कई डाक्टरों में अप्रैल के मुकाबले जुलाई में एंटीबाडी कम रह गई। ऐसे में बूस्टर डोज लेने से उनमें बड़ी मात्रा में एंटीबाडी टाइटर बनेंगे और संक्रमण से सुरक्षा मिलेगी लेकिन इसके लिए विशेषज्ञों की राय जरूरी है।

पति की मौत के बाद जताई मां बनने की इच्छा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▸ तीन माह पहले कोरोना से हो गई थी पति की मौत, डाक्टर ने महिला को दी सरोगेसी से संतान पाने की सलाह

पति की मौत के तीन माह बाद वडोदरा की एक महिला ने मां बनने की इच्छा जताई है। वे पहले से आइवीएफ तकनीक के जरिये गर्भधारण की कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन कुछ शारीरिक समस्या के चलते गर्भधारण नहीं हो सका। इसी बीच पति की कोरोना से मौत हो गई। डाक्टर ने अब उन्हें सरोगेसी से संतान पाने की सलाह दी है।

वडोदरा की 35 वर्षीय हैली अर्के का विवाह संजय नामक व्यक्ति के साथ 2014 में हुआ था। कुछ साल संतान नहीं होने पर उन्होंने आणंद के आकांक्षा अस्पताल में आइवीएफ तकनीक से गर्भधारण की सलाह ली। अस्पताल की चिकित्सा निदेशक डा. नयना पटेल ने आइवीएफ तकनीक से गर्भधारण कराने की कोशिश की। डा. नयना बताती हैं कि इस दंपती का पांच दिन का एंब्रायो निषेचित अंडाणु उनके लैब में संरक्षित है। लेकिन हैली के गर्भाशय में कुछ खराबी है। साथ ही उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है। इसलिए सरोगेसी की सलाह दी गई है। इसके तहत उनके एंब्रायो को किसी अन्य महिला के गर्भ में स्थापित कर संतान प्राप्त की जा सकती है।

स्पर्म लिए जाने के अगले दिन ही पति की मौत: उच्च न्यायालय के आदेश पर वडोदरा के अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के स्पर्म लेने के 30 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। भरूच के युवक व वडोदरा की युवती का नौ माह पहले ही कनाडा में प्रेम विवाह हुआ था। युवक पिता के बीमार होने के कारण भारत आया तो खुद कोरोना संक्रमित हो गया। इस युवा दंपती की प्रेम कहानी का गुरुवार को करुण अंत हो गया। युवक को कोरोना संक्रमण के बाद वडोदरा के स्टर्लिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मल्टीपल आर्गन फेल हो जाने के बाद चिकित्सकों ने उसके जीवित रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। पत्नी ने जब पति के स्पर्म से ही आइवीएफ तकनीक के जरिये गर्भधारण करने की इच्छा जताई तो चिकित्सकों ने उसके अचेत होने व गंभीर रूप से बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत से मंजूरी लेने की बात कही। महिला ने मंगलवार को ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पति के स्पर्म संरक्षित कराने की मांग रखी। न्यायालय ने इस पर अस्पताल प्रबंधन तथा राज्य सरकार को इसकी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। अदालत में स्पर्म से पत्नी के गर्भधारण करने का फैसला होना है। लेकिन इससे पहले ही स्पर्म संरक्षित करने के महज 30 घंटे बाद पति ने दम तोड़ दिया।

क्या है एंब्रायो

पुरुष के स्पर्म जब महिला के अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो ताकतवर स्पर्म ही अंडाणु को फर्टिलाइज कर पाता है। इसकी अवधि पांच दिन की होती है।

राष्ट्रीय फलक

विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के भविष्य पर सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ कोरोना के भय से विदेशी सरकारें संशकित, आश्वासन देने के बावजूद नहीं बदल रही जमीनी स्थिति

भारत में कोरोना महामारी की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, इसके बावजूद भारतीयों को लेकर कई देशों का रवैया नहीं बदला है। इस कारण आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, चीन और यूरोपीय देशों के दर्जनों विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले भारतीय विद्यार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकारी स्तर पर इजाजत नहीं मिलने और हवाई सेवा नहीं होने के कारण हजारों भारतीय विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र खराब होने का खतरा पैदा हो गया है। विदेश मंत्रालय के पास रोजाना ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों की तरफ से मदद की गुहार आ रही है। विदेश मंत्रालय लगातार कूटनीतिक स्तर पर यह मुद्दा उक्त देशों के समक्ष उठा रहा है, कुछ देशों की तरफ से मदद का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत बदलती हुई नहीं दिख रही।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में बताया, हम लगातार विदेशी सरकारों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कोरोना की स्थिति सुधर रही है। नई दिल्ली स्थित इन देशों के राजनयिकों को भी बताया जा रहा है और दूसरे देशों में स्थित हमारे राजदूत भी संबंधित प्रतिनिधियों से मिलकर बात कर रहे हैं। भारतीयों को आने-जाने में छूट मिलने पर ही भारतीय छात्रों को भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जारी रखने की छूट होगी। कुछ देशों की तरफ से सकारात्मक संकेत मिले हैं और जल्द ही उनकी तरफ से घोषणा हो सकती है।

उधर, राज्यसभा में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि अब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, जार्जिया जैसे देशों ने भारतीय छात्रों के लिए प्रवेश नियमों में ढिलाई देनी शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से ग्लोबल इंडियन स्टूडेंट्स पोर्टल भी बनाया जा रहा है जहां शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों का पंजीयन किया जाएगा ताकि उनकी मदद की जा सके। विदेश मंत्रालय की इस उम्मीद के बावजूद अन्य कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि हालात बहुत सकारात्मक नहीं दिख रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों के दबाव के बावजूद उनकी सरकार भारत के छात्रों को अनुमति देने से अभी हिचक रही है। कुछ देशों में प्रवेश की इजाजत मिलने के बावजूद सामान्य फ्लाइट नहीं होने की वजह से भी समस्या आ रही है।

लाइन क्लियर का सिग्नल देकर सो गया गेटमैन

जासं, फतेहपुर : फतेहपुर में हावड़ा-दिल्ली रेल रूट पर रमवां रेलवे क्रासिंग का फाटक बंद करने के बाद टार्च (इलेक्ट्रिकल लैंप) से हरी बत्ती जलाकर लाइन क्लियर का सिग्नल देकर गेटमैन कमरे में सो गया। इससे क्लियर लाइन देखकर पटरी पर ट्रेनें दौड़ती रहीं और मध्यरात्रि से भोर तक रेलवे फाटक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

रमवां गेट नंबर 47 पर गुरुवार रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक गेटमैन आरके शर्मा की ड्यूटी थी। बताया गया मध्यरात्रि के बाद उसने टार्च (इलेक्ट्रिक लैंप) जलाकर बाहर रख दिया और कमरे में सोने चला गया। हरा सिग्नल देखकर रात भर ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती रहीं। इधर वाहनों की लाइन देखकर पुलिस रिस्पांस वेहिकल ड्यूटी पर तैनात सिपाही जानकारी लेने पहुंचे और सोते हुए गेटमैन का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया। गेटमैन को निलंबित कर जांच बैठा दी। हालांकि, दैनिक जागरण वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

ताकि हवा रहे साफ

नई दिल्ली, एएनआइ : कोरोना महामारी के दौरान शहरों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, एनजीटी ने अपने आदेश में पहले ही इस मामले पर फैसला दे दिया है और आगे इस पर स्पष्टीकरण या विचार की जरूरत नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि अधिकारी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) की कैटेगरी के मुताबिक पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि पटाखों के उत्पादन की अनुमति दी गई थी और जो इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे एक्यूआइ की कैटेगरी के आधार पर अनुमति से ऐसा कर सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध उन स्थानों पर है जहां वायु की गुणवत्ता खराब है। पीठ ने कहा, 'जिस क्षण वायु की गुणवत्ता खराब होती है, सभी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए।'

पटाखों का दुष्प्रभाव समझने के लिए क्या आपको आइआइटी की जरूरत है?

सुनवाई के दौरान पटाखा विक्रेताओं की ओर से पेश अधिवक्ता साई दीपक जे. ने दलील दी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के प्रदूषण फैलाने वाले शीर्ष 15 कारणों में पटाखे शामिल नहीं थे। इस पर पीठ ने कहा कि लोगों की सेहत पर पटाखों के दुष्प्रभावों का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययनों की जरूरत नहीं है। पीठ ने सवाल किया, 'क्या आपको अपनी सेहत पर पटाखों का दुष्प्रभाव समझने के लिए आइआइटी की जरूरत है? दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि दिवाली के दौरान क्या होता है।' पीठ ने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित किए गए पटाखों की बिक्री न हो। उल्लंघन के मामलों में उन्हें हर्जाना वसूलने का अधिकार भी दिया गया था।

बनारसी साड़ी की डिजाइन में पहली बार क्यूआर कोड की बुनाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी

हथकरघा आधारित बनारसी साड़ियों की डिजाइन में अब क्यूआर कोड भी रहेगा। यानि स्टिकर और लेबल से मिलने वाली सारी जानकारियां धागे से बुनी गई डिजाइन में मिल जाएंगी। आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस (एआइ) आधारित इस तकनीक के सहारे ग्राहक साड़ी की गुणवत्ता, ब्रांड व अन्य विशेषताएं मोबाइल फोन से तुरंत जान सकेंगे। साड़ी पर बुने गए क्यूआर कोड को स्कैन करते ही साड़ी का पूरा विवरण एक पल में फोन के स्क्रीन पर होगा। साड़ी पावरलूम की है और दुकानदार हैंडलूम बताकर बेच रहा है तो एक क्लिक पर सच्चाई पता चल जाएगी।

आइआइटी-बीएचयू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोध छात्र एम.कृष्ण प्रसन्ना नाइक ने अपने गाइड प्रोफेसर प्रभाष भारद्वाज के मार्गदर्शन में बनारसी साड़ी पर क्यूआर कोड, लोगो, रेशम चिह्न और जीआइ टैग इनबिल्ट किया है। बनारस में अंगिका सहकारी समिति के अध्यक्ष अमरेश कुशवाहा और डिजाइनर व शोधार्थी अंगिका ने सबसे पहले अपनी कंपनी से इसकी शुरुआत की है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी बनारसी साड़ी की मांग: दो माह की कोशिश के बाद इस डिजाइन को तैयार किया गया। इस तकनीक की मदद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हैंडलूम वाली बनारसी साड़ियों की मांग बढ़ सकती है। प्रोफेसर भारद्वाज ने बताया कि क्यूआर कोड की बुनाई साड़ी के उस हिस्से पर की गई है, जो पहनने के बाद दिखाई नहीं देता।

सर्वे के दौरान आया विचार: कृष्णा की पीएचडी टेक्सटाइल पर ही केंद्रित है। एक सर्वे के दौरान उन्हें यह विचार आया। यह तकनीक आसानी से हथकरघा और पावरलूम साड़ी के बीच अंतर को स्पष्ट कर देगी। इससे डुप्लीकेसी बंद होगी। अमरेश कुशवाहा ने बताया कि साड़ी के सबसे अंतिम हिस्से में करीब सात इंच चौड़े पैच में क्यूआर कोड और अन्य तीन लोगो डिजाइन किए गए हैं। उनके पास 200 कुशल कारीगरों की टीम है, जो अब इस तकनीक पर भी काम करेगी। इससे बनारसी साड़ी के बाजार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक नई पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

अब सुधरेगी बुनकरों की स्थिति

राजस्थान की वनस्थली से टेक्सटाइल डिजाइन में शोध कर रहीं अंगिका कुशवाहा के मुताबिक विभिन्न सर्वे में पाया गया कि हैंडलूम की मांग अत्यधिक होने के बावजूद बुनकरों का हाल ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पावरलूम साड़ियों को ही बाजार में हैंडलूम बताकर बेच दिया जाता है। इससे हैंडलूम व्यवसाय का नुकसान होता है। अब इस इनबिल्ट क्यूआर कोड से ऐसा नहीं होगा और बुनकरों की स्थिति में सुधार आएगा।



बनारसी साड़ी में बनी क्यूआर कोड की डिजाइन। जागरण

भ्रष्टाचार के मामलों में अपील दायर करने में देरी से बचे सीबीआइ : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, आइएएनएस : भ्रष्टाचार के मामलों में अपील दायर करने में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआइ की आलोचना करते हुए संभावना जताई कि आरोपितों के साथ मिलीभगत से अधिकारी उन्हें बचाने के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने सीबीआइ के नए निदेशक को ऐसा तंत्र बनाने का सुझाव दिया जिससे भविष्य में अपील दायर करने में देरी न हो। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए जिससे अपील दायर करने और इससे जुड़े अन्य कदमों की एक आइसीटी प्लेटफार्म पर निगरानी की जा सके। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 26 जून, 2019 के फैसले के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई के दौरान की। इस फैसले में हाई कोर्ट ने विशेष सीबीआइ जज के नवंबर, 2012 के फैसले पलट दिया था जिन्होंने प्रतिवादियों को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट के फैसले से प्रतिवादी बरी हो गए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 647 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की गई। देरी के लिए माफीनामे में भी देरी का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। शीर्ष अदालत ने सीबीआइ की इस दलील को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि कोरोना महामारी की वजह से अपील दायर करने में देरी हुई।

ट्विटर इंडिया के एमडी को बड़ी राहत, नोटिस खारिज

बेंगलुरु, प्रेट्र : गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत दी और उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यक्तिगतरूप से पेशी के नोटिस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने नोटिस को दुर्भावनापूर्ण बताया। बता दें कि ट्विटर पर एक सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने माहेश्वरी को व्यक्तिगतरूप से पूछताछ के लिए गाजियाबाद के लोनी थाने में हाजिर होने को कहा था।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति जी नरेंदर की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस को सीआरपीसी की धारा 160 के रूप में लिया जाना चाहिए जिसके तहत गाजियाबाद पुलिस वर्चुअल मोड में माहेश्वरी से पूछताछ कर सकती है।

डीएचएफएल अधिग्रहण पर रोक की याचिका खारिज

नई दिल्ली: नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने पीरामल ग्रुप को राहत देते हुए 63 मून्स की याचिका ठुकरा दी है। एक याचिका के माध्यम से 63 मून्स ने पीरामल ग्रुप की कंपनी पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के अधिग्रहण प्रस्ताव को रोकने की गुहार लगाई थी। एनसीएलटी इस अधिग्रहण सौदे को पहले ही मंजूरी दे चुका है। (प्रेट्र)



कोरोना की अनिश्चितता अभी भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि त्योहारी सीजन के नजदीक आते-आते बाजार में बड़े सकारात्मक बदलाव दिखेंगे।
— संजय लालभाई,
चेयरमैन, अरविंद लिमिटेड

सेंसेक्स	52,975.80	▲	138.59
निफ्टी	15,856.05	▲	32
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 46,698	▲	₹256
चांदी प्रति किलोग्राम	₹66,111	▲	₹662
डॉलर	₹74.40	▼	₹0.06
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 73.78		

बढ़े खर्च से रिलायंस इंडस्ट्रीज का लाभ गिरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के लाभ में कमी आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में आरआइएल का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ सात फीसद गिरकर 12,273 करोड़ रह गया। हालांकि कंपनी के कई कारोबार ने बेहतर विकास दर दिखाई, लेकिन कई मदों में खर्च बढ़ने से सकल लाभ में कमी देखी गई। कंपनी ने बताया, समीक्षाधीन अवधि में उसका कुल खर्च 50% से अधिक बढ़कर 1.31 लाख करोड़ पर जा पहुंचा, जिसमें 3,464 करोड़ रुपये का टैक्स खर्च शामिल है।

आरआइएल के अनुसार परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन पर कोरोना की दूसरी लहर का असर नहीं के बराबर रहा है। पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग सेग्मेंट का कर-पूर्व लाभ 50% बढ़कर 12,231 करोड़ पर जा पहुंचा। समीक्षाधीन अवधि में कच्चे तेल को पेट्रोल-डीजल जैसे रिफाइंड उत्पाद में बदलने के कारोबार की कमाई सुधरी।

भारत में बढ़ी डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा



यूएनईएससीएपी ने दुनिया की 143 अर्थव्यवस्थाओं को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया था ● फाइल फोटो

- यूएन के सर्वे में भारत ने इस वर्ष 90.32 फीसद अंक हासिल किए, पिछले सर्वे में मिले थे 78.49 फीसद अंक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा में भारत ने पिछले दो वर्षों में अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। यह बात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा के ताजा वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कही गई है। इस सर्वेक्षण में भारत ने इस वर्ष 90.32 फीसद अंक हासिल किए। वर्ष 2019 में किए गए इस सर्वेक्षण में भारत को 78.49 फीसद अंक मिले थे। यूएनईएससीएपी ने दुनिया की 143 अर्थव्यवस्थाओं को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। इस सर्वे में मुख्य रूप से पांच चीजों को शामिल किया गया था। इनमें पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था व सहयोग, कागज-रहित व्यापार एवं सीमा पार कागज रहित व्यापार शामिल हैं।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि दक्षिण एवं दक्षिण- पश्चिम एशिया क्षेत्र और एशिया-प्रशांत क्षेत्र की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत का समग्र स्कोर भी फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नार्वे, फिनलैंड आदि कई देशों के मुकाबले अधिक पाया गया है और भारत का समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से अधिक है। भारत ने पारदर्शिता सूचकांक के लिए 100% और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी संबंधी मामले में 66% अंक हासिल किया।

पारदर्शिता के मामले में इस वर्ष भारत को 100 फीसद अंक दिए गए जबकि वर्ष 2019 में भारत ने पारदर्शिता के मामले में 93.33 फीसद अंक हासिल किए थे। इस वर्ष की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कारोबार से जुड़ी औपचारिकताओं के मामले में भारत को 95.83 फीसद अंक मिले, जबकि वर्ष 2019 में यह 87.5 फीसद था। संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग में इस वर्ष भारत ने 88.89 फीसद अंक प्राप्त किए जबकि 2019 में 66.67 फीसद अंक मिले थे। कागज रहित व्यापार में वर्ष 2021 में फीसद तो वर्ष 2019 में 81.48 फीसद अंक प्राप्त हुए थे। सीमा पार कागज रहित व्यापार में भारत को इस वर्ष 66.67 फीसद अंक मिले जबकि वर्ष 2019 में 55.56 फीसद अंक मिले थे।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों के मामले में किए गए सुधारों की वजह से भारत ने फेसलेस, पेपरलेस और कांटैक्टलेस व्यवस्था के तहत सीमा शुल्क में उल्लेखनीय सुधार किया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर यूएनईएससीएपी रैंकिंग में सुधार के संदर्भ में इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क ढांचे के तहत कोविड से संबंधित आयातों जैसे आक्सीजन से संबंधित उपकरण, जीवन रक्षक दवाएं, टीके आदि में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए गए। डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण हर दो वर्ष में यूएनईएससीएपी द्वारा आयोजित किया जाता है।

अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में मिलेगा नामिनी का विकल्प

नई दिल्ली, प्रेट्र : जो निवेशक इस वर्ष पहली अक्टूबर से नया ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलेंगे, उनके पास किसी को नामित करने या उसे हटाने का विकल्प होगा। यह जानकारी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को दी। इससे जुड़ा एक प्रारूप भी जारी किया गया है। इसके अलावा मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धारकों को 31 मार्च तक नामिनी की जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।

एजीएम के लिए मिला एक महीने का और वक्त: सेबी ने बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 100 कंपनियों को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है। मौजूदा नियमों के तहत ऐसी कंपनियों को वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख से पांच महीने के भीतर अपनी एजीएम आयोजित करनी होती है।

चालू वित्त वर्ष में निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

45 फीसद की बढ़ोतरी जुलाई के शुरुआती तीन सप्ताह में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष में निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जुलाई के शुरुआती तीन सप्ताह में वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 45.13 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2019 की समान अवधि के मुकाबले यह बढ़ोतरी 25.42 फीसद की है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में 95.39 अरब डालर का निर्यात किया गया जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 85 फीसद और वर्ष 2019 की समान अवधि के मुकाबले 17.90 फीसद अधिक है। पिछले वर्ष अप्रैल-जून में 51.32 अरब डालर का निर्यात किया गया, जो वर्ष 2019 के अप्रैल-जून में 80.91 अरब डालर का था। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल से वस्तुओं के निर्यात में दहाई अंकों की बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है।

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष जुलाई के शुरुआती तीन सप्ताह (21 जुलाई तक) में 22.48 अरब डालर का निर्यात किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 15.49 अरब डालर का था। वर्ष 2019 के जुलाई के शुरुआती तीन सप्ताह में 17.92 अरब डालर का निर्यात हुआ था। इस वर्ष समीक्षाधीन अवधि में आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 64.82 फीसद बढ़कर 31.77 अरब डालर पर पहुंच गया। वर्ष 2019 की समान अवधि में 25.77 अरब डालर का आयात किया गया था। वहीं, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का आयात पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले 108 फीसद बढ़कर 126.15 अरब डालर हो गया।

एजीआर मामले में टेलीकाम कंपनियों की याचिकाएं खारिज

एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू की गणना में त्रुटियों का लगाया था आरोप



सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वोडाफोन आइडिया को सबसे अधिक नुकसान होगा, भारती एयरटेल बेहतर स्थिति में

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में टेलीकाम कंपनियों को राहत देने से इन्कार किया है। कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत टेलीकाम कंपनियों की सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में टेलीकाम कंपनियों ने उन पर बकाया एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) की गणना में कथित त्रुटियों को ठीक करने की मांग की थी। कंपनियों का कहना था कि सरकार ने बकाया एजीआर की जो गणना की है, उनमें प्रविष्टियों (एंट्रीज) के दोहराव की गलतियां हैं।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष सितंबर में एजीआर से संबंधित 93,520 करोड़ रुपये के बकाये का सरकार को भुगतान करने के लिए टेलीकाम सेवा प्रदाताओं को 10 वर्षों का समय दिया था।

पीठ ने 19 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में जारी आदेश का हवाला दिया। उस आदेश में कहा गया था कि एजीआर से जुड़े बकायों का दोबारा आकलन नहीं किया जा सकता। एक टेलीकाम कंपनी की ओर से पेश अधिवक्ता का कहना था कि वे इसके लिए दूरसंचार विभाग को दोष नहीं दे रहे थे क्योंकि वे अंकगणितीय प्रविष्टियां हैं। वे सिर्फ उन प्रविष्टियों को विभाग के समक्ष रखना चाहते हैं ताकि वे उन पर पुनर्विचार कर सकें।

पिछले साल सितंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दूरसंचार विभाग की मांग के मुताबिक टेलीकाम आपरेटर्स कुल बकायों के 10 फीसद का भुगतान 31 मार्च, 2021 तक करेंगे और बाकी का भुगतान पहली अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2031 तक वार्षिक किस्तों में करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट के इस फैसले से वोडाफोन आइडिया को सबसे अधिक नुकसान होगा। सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार सेक्टर की अन्य कंपनियों के मुकाबले भारती एयरटेल बेहतर स्थिति में है।

अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ चलती रहेगी जांच

बेंगलुरु, रायटर : ई-कामर्स कंपनी अमेजन व फ्लिपकार्ट के खिलाफ एंटी-ट्रस्ट संबंधी जांच चलती रहेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में दोनों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की चल रही जांच को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और नटराज रंगास्वामी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तो उन्हें जांच से डरना नहीं चाहिए। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर जांच को रोका नहीं जा सकता है।

समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार दिल्ली व्यापार महासंघ द्वारा शिकायत के बाद सीसीआइ ने जनवरी, 2020 में जांच का आदेश दिया था। इस महासंघ में स्मार्टफोन विक्रेता या उसकी एसेसरीज बेचने वाले बहुत से व्यापारी हैं। इस आदेश को चुनौती देते हुए दोनों दिग्गज ई-कामर्स कंपनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पिछले महीने वाणिज्य मंत्री पीयूष

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, कुछ गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने शुरू की थी जांच

गोयल ने सीसीआइ जांच से भागने और कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर दोनों कंपनियों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कंपनियों ने कुछ छिपाया नहीं है तो वे सीसीआइ द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हैं।

समाचार एजेंसी रायटर के मुताबिक फ्लिटकार्ट ने कहा कि वह फैसले की समीक्षा करेगा। साथ ही उसने भारतीय कानूनों का हर हाल में पालन करने की बात दोहराई है। रायटर के मुताबिक अमेजन के दस्तावेज की जांच करने पर पता चलता है कि वह विक्रेताओं के एक छोटे से ग्रुप को लंबे अरसे से तरजीह देता रहा है। दोनों प्लेटफार्म पर मोबाइल फोन के एक्सक्लूसिव लांच और भारी-भरकम छूट का भी आरोप है। सूत्रों के अनुसार दोनों कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं।

जोमैटो की जबरदस्त लिस्टिंग, वैल्यू एक लाख करोड़ को छूकर लौटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर के शेयर बाजारों में कई स्टार्ट-अप कंपनियों ने लिस्टिंग के पहले ही दिन रिकार्ड बनाया है लेकिन भारत में शुक्रवार को पहली बार ऐसा देखने को मिला। आनलाइन फूड डिलिवरी स्टार्ट-अप कंपनी जोमैटो बीएसई में सूचीबद्ध होने के पहले ही दिन निवेशकों को 66 फीसद का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 76 रुपये के मूल्य पर आवंटित हुए थे। सूचीबद्धता के कुछ ही समय में 81.57 फीसद की वृद्धि के साथ ये 138 रुपये पर पहुंच गए। बाजार बंद होने के समय इसके एक शेयर की कीमत 65.59 फीसद की वृद्धि के साथ 125.85 रुपये पर पहुंच गई। एनएसई में इसके शेयर 116 रुपये पर खुले और 125.30 रुपये पर बंद हुए।

इसके साथ ही जोमैटो भारतीय बाजार की पहली स्टार्ट-अप कंपनी बन गई है जिसका बाजार पूंजीकरण शेयर कारोबार के पहले ही दिन ही एक लाख करोड़ रुपये को छू गया।

कारोबार



- लिस्टिंग के दिन ही शेयरों ने लगाई 66 फीसद की छलांग
- 76 रुपये आफर प्राइस के मुकाबले 125.85 रुपये पर पहुंचे

बाजार बंद होते समय बीएसई पर कंपनी का पूंजीकरण पूंजीकरण 98,731.59 करोड़ रुपये था। कई जानकार बता रहे हैं कि जोमैटो का यह प्रदर्शन शेयर बाजार पर काफी सकारात्मक असर डालेगा। कंपनी को मिली इस प्रतिक्रिया से अन्य स्टार्ट-अप के लिए भी बाजार का रास्ता आसान होगा। इससे विशेष रूप से स्टार्ट-अप्स में निवेश करने वाले निवेशकों का एक नया वर्ग भी तैयार होगा। अगले कुछ महीनों में कई स्टार्ट-अप कंपनियां आइपीओ के साथ बाजार में उतरने की तैयारी में है। जोमैटो ने जिस दिन से प्रारंभिक पब्लिक आफर (आइपीओ) लाने का एलान किया है उसी दिन से इसको लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्सुकता है। यही वजह है कि 9,375 करोड़ रुपये के इस आइपीओ को 38 गुना ज्यादा आवेदन आए।

कोटक महिंद्रा कैपिटल के एमडी व सीईओ एस. रमेश ने कहा है कि जोमैटो को शेयर बाजारों में मिली इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि निवेशकों का एक बड़ा वर्ग इन तकनीक आधारित कंपनियों में निवेश करने को तैयार है। यह भारतीय उद्यमशीलता को भी एक तरह से सलाम है। भारत 4जी से निकलकर 5जी टेक्नोलाजी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में डिजिटल आधारित इकोनामी का और विस्तार होगा। वर्ष 2008 में स्थापित जोमैटो वर्तमान में देश के 525 शहरों के अलावा दुनियाभर के 23 देशों में सर्विस दे रही है।

खेल जागरण

आखिरी मैच में श्रीलंका की सांत्वना जीत



शाट लगाते भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शा ● एपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अविष्का फर्नांडो (76) और भानुका राजपक्षे (65) के अर्धशतकों की मदद से श्रीलंका ने कोलंबो में शुक्रवार को खेले गए सीरीज के तीसरे व अंतिम वनडे मैच में भारत को तीन विकेट से हराकर सांत्वना जीत दर्ज की। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.1 ओवर में 225 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका को जीत के लिए 47 ओवर में 227 लक्ष्य मिला था। जवाब में श्रीलंका ने 39 ओवर में सात विकेट पर 227 रन बनाकर जीत दर्ज की। हालांकि, भारतीय टीम सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में सफल रही।

आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 35 रन पर मिनोद भानुका (7) को का विकेट गंवा दिया। उन्हें कृष्णप्पा गौतम ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट बनाया। इसके बाद राजपक्षे और अविष्का ने दूसरे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। सकारिया ने 23वें ओवर में राजपक्षे को आउट कर अपना पहला विकेट झटका। कुछ देर बाद सकारिया ने धनंजय डिसिल्वा (2) को अपने ही गेंद पर लपक लिया। चरित असलंका (24) को हार्दिक पांड्या ने चलता किया। स्पिनर राहुल चाहर ने आखिरी लम्हों में तीन विकेट लेकर मैच में रोमांच ला दिया, लेकिन यह भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था।

इससे पहले भारत ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जब उसने 23 ओवर के बाद तीन विकेट पर 123 रन बनाए थे तभी बारिश आ गई, जिसके कारण मैच को 47-47 ओवर का कर दिया गया। बारिश के बाद खेल शुरू होने पर भारत ने 38 रन के अंदर पांच विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शा (49), संजू सैमसन (46) और सूर्यकुमार यादव (40) ने प्रभावशाली शुरुआत की, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सका।

अंतिम वनडे में भारत को सात विकेट से हराया, भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की

संक्षिप्त स्कोर बोर्ड

भारत: 225 (43.3 ओवर)
पृथ्वी शा: 49 रन, 49 गेंद, 8 चौके
अकिला धनंजय : 10-0-44-3
श्रीलंका : 227/7 (39 ओवर)
फर्नांडो : 76 रन, 98 गेंद, 4 चौके, 1 छक्का, **राजपक्षे**: 65 रन, 56 गेंद, 12 चौके, **चाहर** : 10-0-54-3
मैन आफ द मैच : अविष्का फर्नांडो
मैन आफ द सीरीज : सूर्यकुमार

5 खिलाड़ियों ने इस मैच में भारत के लिए वनडे पदार्पण किया। इनमें नीतीश राणा, राहुल चाहर, चेतन सकारिया, कृष्णप्पा गौतम और संजू सैमसन शामिल हैं। भारत के वनडे इतिहास के पहले मैच को छोड़ दिया जाए तो यह दूसरा मौका है जब भारत के पांच खिलाड़ियों ने एक साथ वनडे पदार्पण किया। इससे पहले दिसंबर 1980 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में ऐसा हुआ था।

5 कैच छोड़े भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने इस मैच में। पूरी सीरीज में भारत की ओर से नौ कैच छोड़े गए

फिजियो को मान्यता नहीं मिलने पर विनेश का फूटा गुस्सा

बुडापेस्ट, आइएएनएस : एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) के उनकी फिजियो पूर्णिमा नगोमदिर को मान्यता नहीं देने पर गुस्सा जाहिर किया। विनेश ने ट्वीट कर लिखा, 'क्या चार महिला पहलवानों के लिए एक फिजियो की मांग करना अपराध है। एक एथलीट के कई कोच/स्टाफ होने के और भी उदाहरण हैं। संतुलन कहां है। हमने फिजियो की मांग काफी समय पहले की थी, ना कि अंतिम क्षणों में जैसा रिपोर्ट में कहा गया है।' विनेश टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार हैं।

एएफआइ खराब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ करेगा कार्रवाई : भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) ने लंबी कूद के खिलाड़ी एम श्रीशंकर और 20 किमी पैदल चाल के एथलीट केटी इरफान की फार्म में गिरावट के बावजूद उन्हें ओलिंपिक दल से बाहर नहीं करने के फैसला किया, लेकिन इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की चेतावनी दी। एएफआइ की चयन समिति ने एक आपात बैठक में दो एथलीटों को 26 सदस्यीय टीम से बाहर नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। बेंगलुरु में हाल ही में आयोजित ट्रायल में खराब प्रदर्शन के बाद कुछ सदस्यों का मत था कि इन दोनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जाए।

राष्ट्रीय फलक

राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी

पोर्नोग्राफी मामला

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति को 19 जुलाई की रात किया गया था गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई के एक कोर्ट ने पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें कुछ एप के जरिये प्रसारित करने से जुड़े मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कारोबारी राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत शुक्रवार को 27 जुलाई तक बढ़ा दी। कुंद्रा के अलावा, पुलिस ने दूसरे आरोपित रयान थोरपे को भी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसकी हिरासत भी 27 जुलाई तक बढ़ा दी।

बता दें कि पोर्नोग्राफी मामले में कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई की रात गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कुंद्रा की हिरासत अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच के लिए कुंद्रा की हिरासत बढ़ाने की अपील की। पुलिस ने इससे पहले कोर्ट को बताया कि 45 वर्षीय कारोबारी अश्लील फिल्मों के माध्यम से काफी पैसा कमा रहे थे। पुलिस ने कुंद्रा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसकी जांच जरूरी है। एएनआइ के मुताबिक पुलिस ने कुंद्रा के यस बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ अफ्रीका के खातों का उल्लेख किया और कहा कि उन खातों की भी जांच जरूरी है। कोर्ट को सूचित किया गया कि इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।



पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कारोबारी राज कुंद्रा को ले जाती मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। प्रेट्र

कुंद्रा ने बांबे हाई कोर्ट में अपील की : कारोबारी कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उसने कहा कि उसकी फिल्में उत्तेजक तो हो सकती हैं, लेकिन अश्लील नहीं कहा जा सकता।

यशिल्पा के बयान दर्ज : मिडडे के मुताबिक, कुंद्रा को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा के शुक्रवार को बयान दर्ज किए। वह पति की कंपनी में निदेशक थीं, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछताछ की। शिल्पा ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री ने पुलिस से कहा कि उनके पति का अश्लील फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है और पोर्न वीडियो के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

चुनौतियों के लिए तैयार : पुलिस पूछताछ से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट शेयर किया जो पति की गिरफ्तारी के बाद उनका पहला पोस्ट था। इसमें अभिनेत्री ने अपनी स्थितियों के बारे में बताया। शिल्पा ने पोर्नोग्राफी मामले में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पोस्ट से लगता है कि वह जीवन में चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। गुरुवार रात शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर किसी बुक का एक पेज शेयर किया है जिसकी शुरुआत में अमेरिकी लेखक जेम्स थर्बर का कथन है जिसमें कहा गया कि गुस्से में पीछे मुड़कर न देखें। डर में आगे न देखें। मैं गहरी सांस लेता हूं। यह जानकर खुशी होती कि मैं जिंदा हूं।

लव जिहाद में हरिद्वार के चार युवक अल्मोड़ा से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : उत्तराखंड के बग्वालीपोखर क्षेत्र में लव जिहाद के मसले पर शुक्रवार को बड़ा हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने चार युवकों को दबोच थाने पहुंचाया। इस बीच पुलिस मामले को दबाने में जुटी रही। मगर भाजपा विधायक महेश नेगी व हिंदूवादी संगठनों के मुखर होने पर पाक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, बग्वालीपोखर घाटी के एक गांव की नाबालिग को इंटरनेट मीडिया के जरिये कलियर (हरिद्वार) निवासी कासिफ ने जाल में फंसाया। शुक्रवार को वह अपने दोस्त अरमान, साने आलम व फरमान के साथ बग्वालीपोखर पहुंच गया। मोबाइल पर संपर्क साध उसने बच्ची को द्वाराहाट बाजार के एक होटल में बुलाया। धोखे में वह होटल पहुंच भी गई। मगर होटल मालिक को संदेह हुआ तो उसने थाने में सूचना दे दी।

किसान आंदोलन में पांच मामलों में 43 लोग हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पुलिस ने अभी तक पांच मामलों में 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह आंदोलन केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों को लेकर हो रहा है। इस दौरान हुई किसानों की मौतों के बारे में केंद्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस कार्रवाई की जानकारी शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब में दी।

तोमर ने कहा है कि नए बने कानूनों से भ्रमित होकर किसान आंदोलन कर रहे हैं जबकि इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी और गांवों में निवेश बढ़ेगा। इससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। केंद्र सरकार के बनाए तीन कानूनों का पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पिछले आठ महीनों से विरोध कर रहे हैं। वे दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इनमें से 200 जंतर मंतर पर भी धरना दे रहे हैं। तोमर ने आश्वस्त किया कि किसानों की जमीन, मिट्टी की गुणवत्ता और पैदावार से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी कंपनी को नहीं दी जा रही है।

कांग्रेस सांसदों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का निंदा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों ने दूसरे दिन भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और किसान संसद की कार्यवाही चलाई। कांग्रेस के कई सांसदों के संसद में जारी प्रदर्शन छोड़कर चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होने पर प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई। शुक्रवार को छह मंडलीय दल में हरदेव हर्षी, जगतार सिंह बाजवा, वी.वेंकटरमैया, मुकेश कुमार, जगवीर सिंह और हरपाल बिलारी को स्पीकर व डिप्टी स्पीकर बनाया गया। बाजवा ने कहा कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) कानून पर बहस दूसरे दिन भी जारी रही।

जापान के उगते सूरज के ध्वज से ओलिंपिक में विवाद

ओलिंपिक डायरी

सियोल, प्रेट्र : उगते सूरज के अपने ध्वज को जापान इतिहास का हिस्सा मानता है, लेकिन कोरिया, चीन और अन्य एशियाई देशों में कुछ का कहना है कि यह ध्वज युद्ध के दौरान जापानी अत्याचारों की याद दिलाता है और उन्होंने इसकी तुलना नाजी स्वास्तिक से की। इसी वजह से ओलिंपिक में जापान के ध्वज को लेकर नाराजगी है और मेजबान देश के कुछ पड़ोसी देशों ने इसे टोक्यो ओलिंपिक के दौरान प्रतिबंधित करने की मांग भी की है।

शनिवार को दक्षिण कोरिया ने तब ओलिंपिक गांव से अपने बैनर हटा दिए थे जब आइओसी ने उन्हें उकसाने वाला करार दिया था।

दक्षिण कोरिया ने कहा कि उसे आइओसी ने वादा किया था कि ओलिंपिक के अन्य स्थलों और स्टेडियमों में भी इस ध्वज को लगाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जापान की आयोजन समिति ने कहा कि ध्वज ओलिंपिक स्टेडियम के अंदर प्रतिबंधित नहीं है।

एक दिन टला नाओमी ओसाका का मैच : ओलिंपिक टेनिस टूर्नामेंट में नाओमी ओसाका के शुरुआती मैच को शनिवार से रविवार तक के लिए टाल दिया गया है। आयोजकों ने हालांकि इसका कारण नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि यह कदम टूर्नामेंट के रेफरी की ओर उठाया गया है।

ओसाका को मूल रूप से शनिवार सुबह सेंटर कोर्ट पर खेलों की पहली प्रतियोगिता में चीन की 52वीं रैंकिंग की खिलाड़ी झेंग साइसाई के खिलाफ अपने अभियान को शुरू करना था। फ्रेंच ओपन के पहले दौर के बाद टेनिस से विश्राम लेने वाली ओसाका लगभग दो महीने बाद प्रतिस्पर्धा में वापसी कर रही हैं।

ओलिंपिक रद करने को लेकर टोक्यो में प्रदर्शन

टोक्यो, प्रेट्र : करीब 50 प्रदर्शनकारियों ने ओलिंपिक रद करने की मांग को लेकर टोक्यो में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी टोक्यो मेट्रोपोलिटन प्रशासन की इमारत के बाहर नो टू ओलिंपिक्स और सेव पीपुल्स लाइव्स के नारे लगाते हुए एकत्र हुए। उन्होंने साइनबोर्ड ले रखे थे जिस पर कैंसल द ओलिंपिक्स लिखा था।

17.2 प्रतिशत रही भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। वहीं संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट बताती है कि 2010 से 2019 के बीच भारत की आबादी की वृद्धि दर 1.2 से बढ़कर 1.36 हो गई जो चीन के मुकाबले दोगुनी है।

आजकल

जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रारूप सामने आने के बाद से इस पर बहस छिड़ गई है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है जिसके नियंत्रण की सख्त जरूरत है। हालांकि इस मसले पर सभी पक्ष एकमत हैं, वैचारिक विरोध केवल इसके तरीकों पर है। राजनीतिक दल इस विषय पर अपने नफा-नुकसान के अनुकूल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया इस बात पर ज्यादा है कि यह नीति किन समूहों को प्रभावित करेगी। वैसे व्यावहारिक तौर पर यह मसला संसाधनों पर बढ़ते जनभार से ही जुड़ा होना चाहिए



अभिजीत
शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में प्रभावी कानून बनाए जाने के लिए पिछले कुछ समय से देशभर में चर्चा तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। हालांकि यह मसला अब सामाजिक समस्या से अधिक एक राजनीतिक समस्या के रूप में उभर चुका है, लेकिन हमारे सीमित संसाधनों पर पड़ने वाले इसके व्यावहारिक पक्ष को देखा जाना ज्यादा जरूरी है।

दरअसल 18वीं सदी में ही प्रख्यात अर्थशास्त्री माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को संसाधनों और उनकी उपलब्धता से जोड़कर देखते हुए इसे इंसान के लिए सर्वाधिक जरूरी खाद्य आपूर्ति के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि का पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया। माल्थस का मानना था कि अगर हमारी जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता के अनुपात में तेजी से बढ़ती है और यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उपलब्ध खाद्य आपूर्ति व जनसंख्या के बीच असंतुलन पैदा होगा जिससे खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

माल्थस का सिद्धांत कई दशकों तक प्रभावशाली रहा, लेकिन बाद में जब खाद्य उत्पादन को इंसान ने कई गुना बढ़ा लिया और पश्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति ने अन्य संसाधनों की उपलब्धता को भी कई गुना बढ़ा दिया, तब माल्थस की बात थोड़ी कमजोर दिखने लगी। एक अन्य अर्थशास्त्री रिकार्डो ने जनसंख्या और श्रम को लेकर अपना सिद्धांत दिया। उनके अनुसार जनसंख्या में तेज वृद्धि वेतन का स्तर कम कर देगी और इससे लाभ व पूंजी दोनों के ही संचय पर अंकुश लग जाएगा, जिसका प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ेगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चाएं दो बड़े कारणों से आगे बढ़ीं। पहला, दुनिया को माल्थस दोबारा याद आए जब तीसरी दुनिया के नए स्वतंत्र हुए गरीब और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से बढ़ी और हालात ऐसे हो गए कि ये देश अपनी खाद्यान्न जरूरतों के लिए विकसित देशों पर निर्भर होने लगे। शीत युद्ध के उस दौर में खाद्यान्न एक कूटनीतिक और प्रभाव बढ़ाने का साधन बन गया। दोनों ही पक्षों ने अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए नए स्वतंत्र देशों को खाद्यान्न आपूर्ति करना शुरू किया। अर्थशास्त्रियों ने इन परिस्थितियों को माल्थस के सिद्धांत से जोड़कर देखा और यह बात सामने आई कि अधिक जनसंख्या खाद्यान्नों की कमी का कारण बनेगी। इन बातों का प्रभाव यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए नीतियां भी बननी शुरू हो गईं। दूसरा, पूर्वी एशिया के देशों ने इसी दौर में यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे प्रजनन दर को कम करके बचत और निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि छोटा परिवार अपने बच्चों को बेहतर विकास के अवसर प्रदान करने में अधिक सक्षम हो सकता है।

हालांकि बाद के समय में कुछ अर्थशास्त्रियों ने पूर्वी एशिया के विकास को प्रजनन नियंत्रण से नहीं, बल्कि जनसांख्यिकीय लाभांश से जोड़ते हुए उस समय की युवा आबादी को आर्थिक विकास का कारण माना। जनसांख्यिकीय लाभांश उस आर्थिक विकास को कहते हैं जो किसी भी देश में काम करने वाले आयु वर्ग के लोगों और उन पर आश्रित लोगों का अनुपात अधिक होने पर मिलता है। उस समय भारत में भी स्थिति और सोच विश्व के अन्य हिस्सों के जैसी ही थी। भारत में भी खाद्यान्न संकट था और हम भी अपने भोजन के लिए विदेशी मदद पर निर्भर थे। पिछली सदी के सातवें और आठवें दशक में भारत में भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से यह मसला राजनीतिक व धार्मिक बन गया। वहीं लगभग इसी दौर में खेती के क्षेत्र में हुई हरित क्रांति ने देश में खाद्य सुरक्षा और खेती से होने वाले लाभ को बढ़ा दिया। खाद्य सुरक्षा ने आबादी को लेकर उपजी चिंता को दूर कर दिया और यह मसला चर्चा से बाहर हो गया।

यह सही है कि देश में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होने लगी थी। किसानों को तात्कालिक तौर पर कुछ लाभ भी हो रहा था, मगर वहीं दूसरी ओर बढ़ते परिवारों के कारण प्रति परिवार खेतों के क्षेत्रफल में लगातार कमी आती गई। बढ़ी हुई उत्पादकता के बावजूद जोत का आकार कम होते जाने से अधिकांश परिवारों के लिए खेती से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन कर गए।

यही सब कारण है कि आज शहरों और महानगरों में गांवों से बड़ी संख्या में लोग आकर बस चुके हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर जुटा पाना मुश्किल होता जा रहा है। भविष्य की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है, क्योंकि जहां एक ओर आगामी 30 वर्षों में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी तो वह देश भारत होगा। दूसरी तरफ पूरे विश्व में मशीनीकरण तेजी से हो रहा है जिससे रोजगार के अवसरों में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के तेजी से हो रहे विकास के कारण घटते रोजगार के अवसर और विनिर्माण का विकसित देशों की ओर लौटना भविष्य में रोजगार संकट उत्पन्न कर सकता है। यूरोप और अन्य विकसित देशों में घट रही जनसंख्या समेत कोरोना महामारी के कारण हुए अनेक बदलाव इस संकट को और गहरा कर सकते हैं।

जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत को भारत के बहुसंख्यक लोगों ने गंभीरता से समझा है। सराहनीय यह है कि अब इसको लेकर एक राजनीतिक इच्छाशक्ति और दूरदर्शी कदम उठाने को लेकर प्रतिबद्धता भी दिख रही है तथा समाज भी इसके लिए तैयार है। जरूरत है कि हम जनसंख्या को राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए भूलों को सुधारने में लगें तो यह देश के एक बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।



बुनियादी ढांचा विकसित करने के बावजूद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर बढ़ रहा जनसंख्या का दबाव। फाइल

बुनियादी सुविधाओं का हो सहज वितरण



शिवप्रकाश
राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, भाजपा

उत्तर प्रदेश सरकार नई जनसंख्या नीति (2021-2030) लेकर आई है। इसके उद्देश्यों को घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से संसाधनों की आपूर्ति, जनसंख्या विस्फोट में रोकथाम, मूलभूत सुविधाओं मसलन रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जन सामान्य तक सहज वितरण हो पाएगा।

वर्ष 1968 में पाल आर एहरिच ने अपने शोध पत्र 'द पापुलेशन बम' में जनसंख्या विस्फोट को अनियंत्रित कैंसर के समान बताया है। अधिक जनसंख्या गरीबी, पर्यावरण में क्षरण एवं राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है। साथ ही बेरोजगारी व अपराधों में वृद्धि का कारण भी बनती है। जनसंख्या नियंत्रण नीति सामने आने के साथ ही कुछ लोगों द्वारा विरोध का स्वर भी दिखाई देने लगा है। कुछ ने तो इसे विधि के विधान में व्यवधान बताया। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण जो मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है, वह भी विधि का विधान ही है। जल, जंगल और जमीन को नष्ट करने से मनुष्य भी नहीं बचेगा। बढ़ती जनसंख्या इन सभी को प्रभावित करती है। बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सरकारी सुविधाएं भी अपर्याप्त होती जा रही हैं। गत दिनों कोरोना संक्रमण के बेहद प्रभावी होने के दौर में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी अपर्याप्त ही थीं। ऐसा नहीं है कि यह चुनौती केवल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ही उभरी है। ये चुनौतियां शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बड़ी आबादी का कितना दबाव बढ़ गया है यह किसी से छिपा नहीं है। ये चुनौतियां तेजी से बढ़ती आबादी के मुकाबले बुनियादी ढांचे के विकास से भी जुड़ी हैं।

ऐसा नहीं है कि ज्यादा जनसंख्या से केवल उन्हीं चीजों पर बोझ बढ़ रहा है जो सरकार की तरफ से दी जानी हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो भोजन, पानी, ईंधन आदि की चुनौती भी देश के सामने बड़ी होती जा रही है। सामाजिक असमानता का दायरा भी देश में बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करते समय रोजगार देने का वायदा करती है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाती। कारण रोजगार सृजन सीमित है। लिहाजा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि के कारण इनका समन्वय ही नहीं हो पाता।

भारत में जनसंख्या विस्फोट की विकराल समस्या को समझने के लिए आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 17.2 फीसद रही है। इसे वार्षिक आधार पर इस प्रकार समझा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2010 से लेकर 2019 के बीच भारत की आबादी की वृद्धि दर 1.2 से बढ़कर 1.36 हो गई है जो चीन के मुकाबले दोगुनी है। इस आंकड़े के मुताबिक 2020 में भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ हो चुकी है।

जनसंख्या नियंत्रण नीति को अनेक लोग आस्थाओं के साथ भी जोड़ कर देखते हैं और समर्थन या विरोध इसी आधार पर करते हैं। बढ़ती जनसंख्या का धार्मिक असुंतलन एक वर्ग के लोगों के मन में आशंका भी उत्पन्न करता है। घटनाओं पर संगठित प्रतिक्रिया एवं चुनाव में सामूहिक मतदान इस आशंका को और भी पुष्ट करते हैं। हमें जनसंख्या नीति का समर्थन या विरोध लिंग, भाषा, क्षेत्र अथवा आस्था के आधार पर करने के या समाज हित व भविष्य की चुनौतियों को आधार मानकर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति में सहायक तत्वों को प्रोत्साहन एवं इसका अनुपालन न करने वालों को हतोत्साहित करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के साथ साथ समाज में जनजागरण का प्रयास भी करना होगा। जागरूक व्यक्तियों और संस्थाओं को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

खरी-खरी

घुमक्कड़ और लहरों के संगणक

निर्मल गुप्त

मुल्क आधिकारिक तौर पर लगभग अनलाक हो लिया है। संसद का पावस सत्र शुरू हो चुका है। चारों तरफ पेगासस-पेगासस मची है। यायावर स्वभाव के बेपरवाह लोगों ने अब इसे बाइडिफाल्ट चौपट खुला मान लिया है। ये वे हैं जिन्होंने मान लिया है कि मास्क बांधना भक्तों का काम है, हम तो सेमी-लिबरल हैं, घूमेंगे-फिरेंगे और बात-बात पर सरकार को कोसेंगे। वे बयान बहादुर जो कल तक मास्क को ठोड़ी पर टिकाए घूमते थे, अब उसे पहचान पत्र की तरह गले में लटकाए रमणीय स्थलों की ओर कूच कर गए हैं। उन्होंने ठान लिया है कि वे तीसरी लहर को साथ लाकर ही मानेंगे।

उन्हें लगता है कि पेगासस जैसे स्पाइवेयर के जरिये वे लोग यदि हमारे पहाड़, झील, झरने और ठंडक हैक कर ले गए तो क्या होगा? वे हमारे ढाबों की रेसिपी इस स्पाइवेयर के जरिये चुरा ले गए और अपने यहां ले जाकर उनका कापीराइट ले लिया तो हम अपनी सुरम्य वादियों को अगली बार जाकर क्या मुंह दिखाएंगे?

वे संक्रमण की आशंकाओं को परे धकेलते शीतल वादियों में मजे से गर्मागर्म इमरती और ठंडी आइसक्रीम का लुत्फ ले रहे हैं। सब जानते हैं कि जेब में जब दाम लबालब हों तो बंदे को किस्म-किस्म की मसखरी, प्रयोगधर्मिता और अघाई सूझती है। तिस पर गोल्डन क्रेडिट कार्ड और कोरोना की नकली निगेटिव रिपोर्ट भी खीसे में मौजूद रहे तो जीवन के जंगल में मौज-मस्ती के स्वर्ण मृग खुद-ब-खुद कुलांचे भरने लगते हैं।

कुछेक बिंदास घूमने-फिरने निकल लिए हैं, लेकिन जो आर्थिक-पारिवारिक वजह अथवा शंकालु स्वभाव के चलते घर में ही रह गए, वे या तो पछता रहे हैं या किसी मुहावरे वाले जलाशय के किनारे खड़े चुपचाप लहरें गिन रहे हैं।

घुमक्कड़ दनादन सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। लहरों के कुशल संगणक उनके कमेंट बाक्स में बता और चेता रहे हैं कि तीसरी लहर अज्ञात स्थल से अपने चिरपरिचित लक्ष्य की तरफ चल निकली है। मानसून भले रास्ता भूल जाए, जानलेवा लहर भुलक्कड़ नहीं है। वैसे भी विपदा और त्रासदी आम आदमी की जिंदगी का रास्ता कमोबेश कभी नहीं भूलती।

ट्वीट-ट्वीट

किसान संसद में एक पत्रकार का सिर फोड़ने की कोशिश हुई। महिला पत्रकारों को भद्दी-भद्दी अश्लील गालियां दी गईं। जिन लोगों ने ये किया, उनके गले में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी आइकार्ड था। मीडिया की आजादी का झंडा उठाने वालों में दम है तो मीडिया पर इस हमले के खिलाफ आवाज उठाएं।
अशोक श्रीवास्तव@AshokShrivasta6

उत्तर प्रदेश में माफिया की 1,574 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वान यू की तरह उभर रहे हैं, जिन्होंने अपने देश का कायाकल्प कर दिया था।
प्रकाश सिंह@singh_prakash



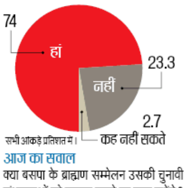
क्या अब किसी के मन में यह संदेह रह गया है कि बाढ़, भीषण गर्म हवाएं, दावानल, अतिवृष्टि और सूखे आदि के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार नहीं है।
शेखर कपूर@shekharkapur

सुरेश रैना कश्मीरी ब्राह्मण या कहिए कश्मीरी पंडित हैं। मैं भी कश्मीरी पंडित या कश्मीरी ब्राह्मण हूं। तथ्यों को स्वीकारने में कुछ भी गलत नहीं। रैना ने किसी अन्य जाति या समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्हें निशाना बनाने वालों को कश्मीरी पंडितों के बारे में और पढ़ना चाहिए।
आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

जिंदगी वर्षों में नहीं जी जाती, लम्हों में जी जाती है। आप लम्हों का आनंद उठाइए। छोटे-छोटे लम्हों को पूरी तरह से जिएं। वही असल जिंदगी है।
मनीष मूंदड़ा@ManMundra

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या मंत्री के हाथ से कागज छीनने वाले सांसद को संसद के शेष सत्र से निलंबित किया जाना चाहिए?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन उसकी चुनावी संभावनाओं को मजबूत बनाने का काम करेंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अबकी तो गुरु पूर्णिमा मना रहा पंजाब,
चेला गुरु बन देखता सीएम पद का ख्वाब।
सीएम पद का ख्वाब हवा जो बहती ताजी,
है चेले के हाथ जा रही दिखती बाजी।
कहें 'गुरुघंटाल' चमकती किस्मत सबकी,
सीएम तो श्रीमान बनेंगे सिद्धू अबकी!
– ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

उत्तराधिकारी पर निर्भर नफा-नुकसान



आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

जातिगत जनगणना को लेकर भले ही राजनीतिक दलों के मत अलग-अलग हों, लेकिन वर्तमान में जातिगत राजनीति का ही बोलबाला है। सत्ता प्राप्ति के लिए जातिगत समीकरणों पर ही ज्यादा भरोसा किया जाता है। इसलिए जातिगत राजनीति से उपजे नेताओं और उनके द्वारा गठित राजनीतिक दलों में उत्तराधिकारी अधिकतर परिवार से उपजते हैं। जहां ऐसा नहीं होता वहां उत्तराधिकार का संकट हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि नेतृत्व के नीचे कोई बेल पनपने ही नहीं पाती। बिहार में जदयू (जनता दल यूनाइटेड) फिलहाल ऐसी ही दुविधा से ग्रस्त है, जिसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर माथापच्ची जारी है।

जदयू में सर्वेसर्वा बनकर स्थापित हो चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संगठन में अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपवाद हैं कि उन्होंने कभी भी अपने स्वजनों को न तो राजनीति में सक्रिय किया और न ही चुनाव या पिछले दरवाजे से सदन में भेजा। उनके साथ संयोग भी जुड़ा कि उनके पुत्र और भाई की राजनीति में रुचि ही नहीं रही और न ही कुटुंब के लोग इधर-उधर परिचय देकर लाभ लेने की कोशिश करते नजर आए। नीतीश ने संगठन के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भरोसेमंद राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया।

आइएएस रहे आरसीपी, कुर्मी वोटबैंक की राजनीति करने वाले नीतीश के 23 साल पुराने सहयोगी हैं, उनके गृह जिले नालंदा से हैं, इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर किया। अब आरसीपी सिंह केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। जदयू की एक व्यक्ति, एक पद की नीति के अनुसार आरसीपी चूंकि एक ही पद पर रह सकते हैं इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में बुलाई जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नए अध्यक्ष पर निर्णय हो सकता है।



जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। जागरण

जदयू का संकट यही रहा कि उसमें आरसीपी के अलावा जातिगत समीकरणों में फिट बैठने वाला कोई भी ऐसा नेता नहीं पनपा जो उनकी जगह ले सके। इसलिए फिलहाल हाल ही में पार्टी में शामिल हुए नीतीश के पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा सबसे आगे है। वह जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उपेंद्र का नीतीश से रिश्ता लोकदल के समय से है। इसे कैलेंडर के हिसाब से वर्ष 1985 से मान सकते हैं। यह रिश्ता इस बीच लगभग आठ वर्षों तक टूटा रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र की पार्टी रालोसपा (राष्ट्रीय लोक समता पार्टी) भी उतरी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं ला पाई। अलग दल बनाकर कोई राजनीतिक लाभ न उठा पाने वाले उपेंद्र चुनाव बाद नीतीश के साथ आ गए और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। लव-कुश (कुर्मी-कुशवाहा) समीकरण के तहत उपेंद्र, नीतीश के हर समीकरण में फिट बैठते हैं। इसलिए इन पर नीतीश दांव लगा सकते हैं।

कुशवाहा वोटों को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल होने से पहले उमेश कुशवाहा को जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लव-कुश समीकरण साधने की कोशिश की गई, लेकिन अब आरसीपी के स्थान पर उपेंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में भी फेरबदल हो सकता है और वहां किसी कुर्मी नेता को बैठाया जा सकता है, क्योंकि दोनों पदों पर कुशवाहा को नहीं रखा जा सकता।

इधर लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चा में आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह जातिगत समीकरणों से इतर लिया गया एक ऐसा फैसला होगा, जिसमें नफा-नुकसान दोनों समाहित होंगे।

हालांकि राजनीतिक विरासत परिवार में देना भी कम कठिन नहीं है। लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान ने इसे भांप लिया था। पुत्र चिराग पासवान 2014 में पहली बार सांसद बने। उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके पांच साल बाद वे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने गए। लेकिन रामविलास पासवान के आंख मूंदते ही उनके भाई-भतीजों की आंखें खुल गईं। नतीजा सबके सामने है। पार्टी दो हिस्से में बंट गई और चिराग अकेले पड़ गए। अभी माना जा रहा है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद बड़ी आसानी से अपने पुत्र तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंप देंगे। असर की बात बाद में होगी, लेकिन पुत्री डा. मीसा भारती की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सुस्त पड़ी रहेगी, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है।

परिवार की पार्टी- परिवार का नेतृत्व वाली प्रवृत्ति वाले सिर्फ रामविलास पासवान या लालू प्रसाद ही नहीं हैं। महज सात साल वाली पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) में भी उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र संतोष मांझी को तैयार किया जा रहा है और बमुश्किल तीन साल पुरानी वीआइपी (विकासशील इंसान पार्टी) के संस्थापक मुकेश सहनी भी अपने भाई को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं।

मंथन

जरूरी है समान नागरिक संहिता

भारत का संविधान समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लिहाजा प्रत्येक मामलों में नागरिकों और वर्गों के लिए समान नागरिक संहिता का होना आवश्यक है



सिद्धार्थ मिश्र
प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में तलाक के एक मामले पर टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में देश में समान नागरिक संहिता लागू करना आवश्यक बताया है। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार देश में न्यायालयों के समक्ष निजी कानूनों में संघर्ष के मामले आते रहते हैं। हालिया मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न था कि अनुसूचित जनजाति के युवक-युवती के उनकी जनजातीय प्रथाओं के अनुसार हुए विवाह पर उनके धर्म पर लागू होने वाला विवाह कानून लागू हो सकता है अथवा नहीं।

उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जहां एक तरफ यह मामला जातिगत प्रथाओं व विवाह कानून के बीच विरोधाभास को दर्शाता है, वहीं यह भी कि किस प्रकार कुछ लोग इस कमी का अपने फायदे के लिए प्रयोग कर लेते हैं।

वर्तमान में विभिन्न समुदायों, जातियों व पंथों के वैवाहिक बंधन में बंधे लोग विवादों में संघर्षरत हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन विवादों, संघर्षों से मुक्ति पाने, समाज में एकरूपता लाने की आशा से शाह बानो मामले (1985) में कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत शब्द बना हुआ है, जबकि इसके अंतर्गत देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करना राज्य का दायित्व है। कोर्ट ने इंगित किया था कि देश में समान नागरिक संहिता निर्माण हेतु उठाए गए किसी सरकारी कदम का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मुस्लिम समुदाय को निजी कानूनों में सुधार हेतु पहल करने की जरूरत पर उभरते मत की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समान नागरिक संहिता विरोधाभासी कानूनों को हटा कर राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य में मदद करेगी।

कोर्ट ने राजनीतिक मजबूरियों को रेखांकित करते हुए कहा था कि भिन्न मतों के लोगों को एक मंच पर लाना सरल नहीं है, परंतु यदि संविधान को अपने अर्थ पर खरा उतरना है तो शुरुआत कहीं से करनी ही होगी। कोर्ट ने इस विचार पर जोर दिया था कि व्यक्तिगत कानूनों के बीच की खाई को पाटने के लिए अदालतों द्वारा टुकड़ों में किए प्रयास समान नागरिक संहिता की जगह नहीं ले सकते तथा सभी को न्याय मिलना पृथक न्याय की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक है।

वर्ष 1985 में आए शाह बानो मामले में आए निर्णय जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह और तलाक की एक समान संहिता को लागू करने व इस क्षेत्र में 'पूर्ण सुधार' का आग्रह किया था। यही भावना सरला मुद्गल (1995) और लिली थामस (2000) मामलों में दोहराई गई थी।

जान वल्लमट्टम बनाम भारत संघ 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक सभ्य समाज में धार्मिक और व्यक्तिगत कानून के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण और मत के स्वतंत्र आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 44 धर्म को सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कानून से अलग करता है। विवाह, उत्तराधिकार और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के मामलों को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 की गारंटी के भीतर नहीं लाया जा सकता। यदि कोई कानून अनुच्छेद 25 और 26 के दायरे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और इसी तरह के मामलों को लाता है, तो वह एक संदिग्ध कानून है।

सुप्रीम कोर्ट ने जोस पाउलो काटिन्हो बनाम मारिया परेरा मामले (2019) में कहा है कि जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग चार में संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि राज्य यानी केंद्रीय सत्ता भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एकसमान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, पर आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यद्यपि हिंदू कानूनों को वर्ष 1956 में संहिताबद्ध किया गया था, फिर भी न्यायालय के आग्रह के बावजूद देश के सभी नागरिकों पर समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।



राष्ट्रीय एकता के लिए देश में सभी नागरिकों और वर्गों के लिए समान कानून होना चाहिए। प्रतीकात्मक

न्यायालयों के समक्ष आ रहे मामले बार-बार ऐसी संहिता की आवश्यकता को उजागर करते हैं। अनुच्छेद 44 सभी के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे पहलुओं के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम बनाता है, ताकि तय किए गए सिद्धांतों, सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं को लागू किया जा सके।

आधुनिक भारतीय समाज धीरे-धीरे एकरूप हो रहा है। धर्म, समुदाय और जाति के पारंपरिक अवरोध धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। भारत के विभिन्न समुदायों, जनजातियों, जातियों या मतों से संबंधित युवाओं को उनके द्वारा अपनाई जाने वाली वैवाहिक विधियों में उन्हें विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों, विशेष रूप से विवाह और तलाक के संबंध में उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

इसमें संदेह नहीं है कि जब अन्य मामलों में समस्त देश में एक जैसा कानून लागू है तब केवल विवाह व उत्तराधिकार के मामलों में भिन्न कानूनों का बने रहना कितना न्यायोचित है। भारत का संविधान समानता के सिद्धांत पर आधारित है और समाज के सभी व्यक्तियों-वर्गों के बीच समानता का लक्ष्य निर्धारित करता है। एक समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित अंतर्विरोधों को दूर करके जनता के बीच समानता और राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।

144 अतिक्रमण हटाए हैं उज्जैन स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जिला प्रशासन ने। मध्य प्रदेश सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 24 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

शिक्षा व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल

उत्तराखंड में तमाम कोशिशों के बाद भी उच्च शिक्षा का ढर्रा पटरी पर नहीं आ पा रहा है। बात गुणवत्तापरक शिक्षा की हो या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, दोनों ही मोर्चों पर राज्य सरकार को अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। निजी शिक्षण संस्थाओं की मनमानी बदस्तूर जारी है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं की हालिया दिनों में सामने आई करतूत यह बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर खराब हैं। इन संस्थानों ने निर्धारित सीटों से ज्यादा बच्चों को न केवल दाखिला दिला दिया, बल्कि उनकी परीक्षा भी ले डाली। उन्हें प्रश्नपत्र फोटो कापी कराकर बांटे गए। संज्ञान में आने पर विश्वविद्यालय प्रशासन से स्तर से कराई गई जांच में यह सच सामने आया। बड़ा सवाल यह कि निजी शिक्षण संस्थानों ने अपने स्तर पर यह सब कैसे कर दिया? विश्वविद्यालय ने निर्धारित सीटों से अधिक बच्चों को प्रवेश पत्र कैसे जारी किए? सवाल उठ रहा है क्या विश्वविद्यालय का निजी संस्थानों पर कोई नियंत्रण नहीं है या उन्हें मनमानी की आजादी दी हुई है। विश्वविद्यालय अब कह रहा है कार्यपरिषद की बैठक बुलाकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। हालांकि, उसका तर्क आसानी से गले नहीं उतर रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या मिलीभगत के बगैर यह संभव है? अगर अधिकारी अपने दायित्व के प्रति ईमानदार होते तो दाखिले के वक्त ही गड़बड़झाला पकड़ में आ जाता। दरअसल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं। कुछ साल पूर्व केंद्रीय विवि के एक कुलपति को ऐसे ही मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। उनके कार्यकाल में मानकों को ताक पर रखकर कुछ निजी संस्थानों में नियत सीटों से अधिक पर दाखिला और नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी गई थी। सीबीआइ जांच में विश्वविद्यालय प्रबंधन की मिलीभगत सामने आई थी।

निजी शिक्षण संस्थानों में घालमेल सामने आने के बाद राज्य सरकार के उन दावों की हवा निकलती दिख रही है, जिनमें गुणवत्ता सुधार पर फोकस किए जाने की बात कही जा रही है

उच्च शिक्षा में ऐसी प्रवृत्ति क्यों पनप रही है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। विडंबना यह कि विवि जांच की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। कभी भी तह में जाने की कोशिश नहीं की जाती। यही वजह है सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी इस तरह की खामियां दूर नहीं हो पा रही हैं। निजी शिक्षण संस्थान इसी का फायदा उठा रहे हैं। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। शिक्षा जैसे पेशे में इस तरह के 'खेल' एक प्रकार से भविष्य की नींव को कमजोर करने जैसा ही है। जिम्मेदारों को यह बात ठीक से समझनी होगी, अन्यथा निजी संस्थान केवल डिग्री हासिल करने के माध्यम बनकर रह जाएंगे।

बिहार

ताकि कम हों दुर्घटनाएं

परिवहन विभाग ने सड़क हादसों का थानावार डाटा तैयार करने का निर्देश देकर यह जाहिर कर दिया है कि सरकार दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। हालांकि यह जरूरी है कि ऐसे उपाय किए जाएं, जिससे सड़क हादसों पर रोक लग सके। सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन कराने का भी निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग की यह सोच जायज है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में थानावार आंकड़े तैयार किए जाएं, ताकि यह पता चल सके कि किस इलाके में दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। जिन इलाकों में अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां कारणों का अध्ययन कर रोकथाम के उपाय करने की योजना बनाई जा सकेगी।

इसके साथ ही बिहार परिवहन मोबाइल एप में सभी जिलों द्वारा सड़क दुर्घटना के आंकड़ों की इंट्री करने को कहा गया है। अभी जिलास्तर या प्रमुख सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के आधार पर डाटा तैयार करने का प्रविधान है। हादसों के डाटा संग्रह तथा परिवहन विभाग के मोबाइल एप में सही ढंग से इनकी इंट्री के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है। औरंगाबाद में बने चालक प्रशिक्षण संस्थान में इसके लिए अलग-अलग जिलों


सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के उपायों पर हो अमल। फाइल

के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है। सड़क हादसों में जख्मी लोगों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में एंबुलेंस सेवा को शामिल किया गया है। इससे हादसे के शिकार लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा, जिससे उनकी जान बच सकेगी। यह देखा गया है कि गोल्डन आवर यानी दुर्घटना होने के पहले एक घंटे के भीतर ही

सड़क दुर्घटनाएं रोकना जरूरी है। किसी खास स्थान पर बार-बार दुर्घटना होती है तो उसका अध्ययन करने से ही उपाय खोजने में मदद मिलेगी

चिकित्सकीय सहायता नहीं मिलने के कारण गंभीर रूप से घायल होने वाले अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। जरूरत यह है कि पुलिस और परिवहन विभाग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर इस दिशा में काम करें।

अगर दुर्घटनाओं की सटीक जानकारी मिलेगी और उसका शत-प्रतिशत डाटा संकलन किया जाएगा तो उस जोन का पता करने तथा वहां हादसों के रोकथाम के उपाय में सहायता मिल सकेगी। इसी तरह राज्य में शुरू की जाने वाली एंबुलेंस सेवा के संचालकों को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है, ताकि सूचना मिलते ही गोल्डन आवर की अवधि में घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया जाए जिससे उनकी जान बच सके।

झारखंड

कायम रहे सेवा भाव

चिकित्सकों को धरती पर भगवान का रूप बताया जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, जिससे यह विश्वास डगमगाने लगता है। रांची के रिम्स में ब्लैक फंगस की पीड़िता मरीज के साथ भी पिछले दिनों ऐसा ही हुआ। महिला एक माह से भर्ती थी, लेकिन उसके आपरेशन में देरी की गई। स्वजनों की गुहार और हाई कोर्ट की सख्ती के बाद जब महिला का आपरेशन हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि आपरेशन के दो दिन बाद ही महिला की मौत हो गई। ऐसे में उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कुछ हद तक जायज ही दिखती है कि कोरोना काल में चिकित्सक सेवा की बजाय पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं, उनमें संवेदना नहीं रही। अदालत की यह तल्ख टिप्पणी यूं ही नहीं है। कोरोना काल में ही हमने ऐसे तमाम मामले देखे हैं, जब कुछ लोग पीड़ितों की जान बचाने से ज्यादा उनसे रकम ऐंठने की चिंता कर रहे थे। निजी अस्पतालों का रवैया तो पूरी तरह से व्यावसायिक है। इलाज सिर्फ कमाई का जरिया बना हुआ है और सेवा भाव लुप्त


चिकित्सा सेवा में संवेदनाओं का अभाव होता जा रहा है। फाइल

होता जा रहा है। झारखंड जैसे राज्य में चिकित्सा सेवा के सुधार के लिए सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों की भी बड़े पैमाने पर जरूरत है। राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति में भी उन्हें प्रोत्साहित करने के कदम उठाए हैं। लेकिन निजी अस्पतालों का रवैया ऐसा ही रहा तो सरकार की इन प्रोत्साहन नीति का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। कोराना काल में भी निजी अस्पतालों ने साधन

हाई कोर्ट की टिप्पणी से सबक लेकर मरीजों के इलाज के प्रति डाक्टरों खास कर निजी अस्पतालों को अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है

संपन्न लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई। सरकार के निर्देश के बावजूद जरूरतमंदों को बेड नहीं मिलने की शिकायतें मिलती रहीं। कोरोना के इलाज के लिए शुल्क भी तय किया गया था, लेकिन लगातार ऐसी शिकायतें आती रहीं कि निजी अस्पताल ज्यादा शुल्क ले रहे हैं। सरकारी अंकुश भी इन पर लगाम नहीं लगा सका। ऐसे में सरकारी तंत्र को ही सख्ती बरत कर इन्हें जिम्मेदार बनाना होगा। चिकित्सा का तेजी से निजीकरण और व्यवसायीकरण हो रहा है। ऐसे में अदालत की यह टिप्पणी जायज है कि मेडिकल कालेज में नए डाक्टरों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाए जाने की जरूरत है।

बंगाल

दिल्ली में नए सियासी जंग की तैयारी

पिछले करीब एक साल से बंगाल की सियासी गतिविधियां पूरे देश में सर्वाधिक सुर्खियों में रही हैं। विधानसभा चुनाव हो या फिर चुनावी सियासी हिंसा या फिर भाजपा व तृणमूल नेताओं के बीच जुबानी जंग अक्सर देशभर में चर्चा का विषय रही हैं। क्या अब तक बंगाल की धरती पर लड़ी जा रही बंगाल की सियासी जंग दिल्ली की धरती से लड़ी जाएगी? यह एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी सियासत का मुंह दिल्ली की ओर मोड़ दिया है। इसका एक उदाहरण 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की वर्चुअल रैली में देखने को मिली। भले ही यह वार्षिक रैली को ममता कोलकाता स्थित अपने कालीघाट आवास से संबोधित कर रही थीं, लेकिन उनकी नजर दिल्ली में मौजूद अन्य दलों के नेताओं पर अधिक थी। भला भी क्यों नहीं। उनकी अपील पर भाजपा विरोधी दलों के प्रमुख नेता जो दिल्ली में एकत्रित हुए थे। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में तृणमूल के लोकसभा व राज्यसभा सदस्य अपने तेवर दिखा चुके हैं। अब आगामी सप्ताह खुद ममता बनर्जी पांच दिनों के दौरे पर दिल्ली जा रही हैं। परंतु भाजपा भी पीछे नहीं है और ममता के हर कदम का जवाब देने की पूरी रणनीति बना रखी है। माना जा रहा है कि कुछ इसी रणनीति के तहत ममता के पहुंचने से तीन दिन पहले ही शुक्रवार को भाजपा विधायकों के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचने के साथ ही अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बंगाल की स्थितियों के बारे में जानकारी दी। मुलाकात के बाद सुवेंदु ने कहा कि चुनाव बाद शुरू हुई हिंसा बंगाल में अब भी जारी है और स्थिति बहुत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को पूरी जानकारी दी है। वह इस मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा बंगाल के बारे में और भी चर्चा हुई है, लेकिन वे उस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं राज्य के भाजपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भी सुवेंदु के साथ दिल्ली में है। वे बंगाल की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के साथ-साथ चुनाव बाद जारी हिंसा को लेकर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से शिकायत करेंगे। संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए, बंगाल के सभी भाजपा सांसद दिल्ली में हैं और उसी क्रम में सुवेंदु भी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि बंगाल को लेकर दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में खूब सियासत होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी सप्ताह ममता के दिल्ली पहुंचने के बाद स्थिति क्या बनती है?

क्या अब तक बंगाल की धरती पर लड़ी जा रही राज्य की सियासी जंग दिल्ली की धरती से लड़ी जाएगी? यह एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है

बढ़ती आबादी के लिए सरकारों की नाकामी जिम्मेदार

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग और इस दिशा में विभिन्न राज्यों में उठाए जा रहे कदमों के बीच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की रिपोर्ट से एक अहम तस्वीर सामने आई है। 2019-20 के एनएफएचएस सर्वे में सामने आया है कि महिलाएं आमतौर पर कम बच्चा चाहती हैं, लेकिन परिवार नियोजन की सुविधाओं तक पहुंच नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता है।



बिहार और झारखंड को छोड़ दें, तो अन्य किसी बड़े राज्य में ऐच्छिक प्रजनन दर दो से ज्यादा नहीं है यानी औसतन कोई दो से ज्यादा बच्चे नहीं चाहता है। इसके बावजूद वास्तविक प्रजनन दर इससे ज्यादा है। कुल प्रजनन दर (टीएफआर) दो होने को रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अगली पीढ़ी की संख्या पिछली पीढ़ी के बराबर रहती है। जनसंख्या नियंत्रण के कानूनों का उद्देश्य भी मुख्यतः टीएफआर को इस स्तर पर या इससे नीचे रखना होता है। 1993 में देश की ऐच्छिक प्रजनन दर 2.6 थी, जो 2016 में 1.8 हो गई थी। हालांकि 2015-16 में देश की वास्तविक प्रजनन दर 2.2 थी। पिछले डेढ़-दो दशक में सरकारों के स्तर पर कदम उठाए गए होते तो इसे दो से नीचे लाया जा सकता था। शिक्षा का फर्क भी साफ दिखा है। 2015-16 के मुताबिक, स्कूल न जाने वाली महिलाओं में ऐच्छिक टीएफआर 2.3, पांच साल तक स्कूल जाने वाली महिलाओं में 1.9 और 12 साल तक स्कूल जाने वाली महिलाओं में यह 1.5 थी।

राज्यों में प्रजनन दर की स्थिति

राज्य	वास्तविक टीएफआर	ऐच्छिक टीएफआर	अंतर
बिहार	3	2.3	0.7
उत्तर प्रदेश*	2.7	2.1	0.6
राजस्थान*	2.4	1.8	0.6
हरियाणा*	2.1	1.6	0.5
झारखंड*	2.6	2.1	0.5
उत्तराखंड*	2.1	1.6	0.5
मध्य प्रदेश*	2.3	1.8	0.5
ओडिशा*	2.1	1.7	0.4
गुजरात	1.9	1.5	0.4
असम	1.9	1.6	0.3
छत्तीसगढ़*	2.2	1.9	0.3
कर्नाटक	1.7	1.4	0.3
हिमाचल प्रदेश	1.7	1.4	0.3
महाराष्ट्र	1.7	1.4	0.3
तेलंगाना	1.8	1.6	0.3
पंजाब*	1.6	1.4	0.2
तमिलनाडु*	1.7	1.5	0.2
बंगाल	1.6	1.4	0.2
आंध्र प्रदेश	1.7	1.6	0.2
जम्मू-कश्मीर	1.4	1.3	0.1
केरल	1.8	1.7	0.1
भारत*	2.2	1.8	0.4

स्रोत: एनएफएचएस-5 (2019-20) और *एनएफएचएस-4 (2015-16) का डाटा

पहाड़ी पर हवाओं के रुख से तय होता है मौसम का मिजाज

विदिशा में आठ दशक से वराह मिहिर की पद्धति पर जारी है परंपरा, किसान करते भरोसा

जागरण विशेष

राजेंद्र शर्मा • विदिशा

आधुनिक दौर में मौसम का मिजाज जानने के लिए उपग्रह से लेकर तमाम उपकरणों का सहारा लिया जाता है लेकिन, मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में किसान आज भी भारत की पुरातन संस्कृति पर भरोसा करते हैं। यहां हर गुरुपूर्णिमा पर हवाओं के रुख से आने वाले मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। जिले में पिछले 80 वर्षों से यह परंपरा चल रही है।

किसानों की उम्मीदें परंपरा पर टिकीं : इस बार रूठे मानसून और मौसम विभाग की सही न होती भविष्यवाणियों के बीच किसानों की उम्मीदें गुरुपूर्णिमा पर होने वाली भविष्यवाणी पर टिकी हैं। विदिशा शहर के मध्य में स्थित करीब 100 फिट ऊंची लुहांगी की पहाड़ी पर शहर के धर्माधिकारी रहे परिवार की तीसरी पीढ़ी आज भी हर साल गुरुपूर्णिमा पर शाम के समय वायु परीक्षण की परंपरा को निभा रही है। वराह मिहिर पद्धति से गणना कर अच्छी या सामान्य बारिश तथा उपज की पैदावार की भविष्यवाणी की जाती है। किसानों को भी बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। हालांकि,

करीब 80 साल पहले दादाजी पंडित उमाशंकर शास्त्री ने इसकी शुरुआत की थी। उनके निधन के बाद पिता स्व. गोविंदप्रसाद शास्त्री लगातार वायु परीक्षण कर भविष्यवाणी करते रहे। वर्तमान में पिछले 36 साल से मैं स्वयं वायु परीक्षण कर भविष्यवाणी करता हूं। वैदिक शास्त्रों के आधार पर यह पूर्णतः प्रामाणिक होती है।
– पंडित बृजराज चतुर्वेदी, विदिशा

विदिशा में होने वाले वायु परीक्षण का आधार सनातन ज्ञान है। इसका वैदिक ग्रंथो में तो उल्लेख मिलता है लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति में कहीं जिक्र नहीं होता, इससे इस पद्धति को खारिज नहीं किया जा सकता। भविष्यवाणी की सत्यता तो किसान ही बता सकते हैं।
-डा. एसएस तोमर, मौसम विज्ञानी, कृषि विज्ञान केंद्र, सीहोर

मौसम विज्ञानी इस भविष्यवाणी को विज्ञान सम्मत नहीं मानते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि यह भविष्यवाणी सटीक बैठती है, इसलिए वे इस पर भरोसा करते हैं।

तीन पीढ़ियों से एक ही परिवार कर रहा वायु परीक्षण: इस वायु परीक्षण की शुरुआत करीब 80 साल पहले संस्कृत के प्रकांड विद्वान और धर्माधिकारी की उपाधि प्राप्त पंडित उमाशंकर शास्त्री ने की थी। तब से यही परिवार वायु परीक्षण करता आ रहा है। तीसरी पीढ़ी के रूप में पंडित ब्रजराज चतुर्वेदी यह परंपरा निभा रहे हैं। इस पद्धति को कायम रखने के लिए वह संस्कृत पाठशाला के बटुकों को भी साथ रखते हैं ताकि प्राचीन संस्कृति कायम रह सके।

प्राचीन पद्धति पर भरोसा कायम: जिले के किसानों का इस प्राचीन पद्धति पर आज भी भरोसा कायम है। विदिशा तहसील के ग्राम जल्हरी के किसान शैलेंद्र सिंह राजपूत कहते हैं कि मौसम को लेकर यह भविष्यवाणी सटीक बैठती है। पिछले 30 वर्ष से इसी के आधार पर खेती की तैयारी करते हैं। उन्हें हर साल इस भविष्यवाणी का इंतजार रहता है। वहीं, ग्राम रावण के किसान बालमुकुंद तिवारी का कहना था कि इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। यह वैदिक ज्ञान पर आधारित भविष्यवाणी होती है। अब तक मौसम का मिजाज परखने में यह पद्धति गलत साबित नहीं हुई है। पिछले वर्ष खण्ड वर्षा की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई।


विदिशा शहर में 100 फिट ऊंची लुहांगी पहाड़ी पर वायु परीक्षण करते पंडित बृजराज चतुर्वेदी। (फाइल फोटो)

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

पर्यावरण संरक्षण : समझ में आया पेड़ों का महत्व तो बना दी नवजीवन फोर्स

अब्बास अहमद, भिंड

- पुलिस की कठिन नौकरी से समय निकालकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे जवान
- बेटी का जन्म होने पर रोपते हैं 21 पौधे, 2200 पौधे पेड़ बन दे रहे लोगों को राहत

मध्य प्रदेश के कई जिलों में तैनात पुलिस आरक्षक एक अलग मायने में सूत्र वाक्य देशभक्ति-जनसेवा को चरितार्थ कर रहे हैं। इन्होंने 200 साथियों के साथ मिलकर नवजीवन सहायतार्थ फोर्स का गठन किया। यह समूह (फोर्स) ड्यूटी के साथ-साथ पर्यावरण को बचाने के लिए भी काम कर रहा है। इसमें शामिल लोग अपने या दोस्त के यहां बेटी का जन्म होने पर 21 पौधे रोपते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ बेटियों को भी मान मिलता है। अन्य अवसरों पर भी पौधे रोपे जाते हैं। 2018 से अब तक 24 सौ से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं।

मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) की दूसरी बटालियन ग्वालियर में पदस्थ आरक्षक गिरीश शर्मा बताते हैं कि 2013 बैच के जवानों को 2018 में मुरैना जिले में कड़ी धूप में ड्यूटी करनी पड़ी थी। आसपास छांव के लिए कोई पेड़ नहीं था। इससे पेड़ों का महत्व समझ में आया। जब ये साथी ग्वालियर लौटे तो तय किया कि एक ऐसा समूह बनाया जाए जिसके माध्यम से पौधे रोपे जाएं। गिरीश कहते हैं, उन्हें और साथियों को मालूम था कि हाल-फिलहाल तो नहीं लेकिन कुछ वर्ष बाद ये पौधे पेड़ बनकर सुकून देंगे। इसी विचार के साथ नवजीवन सहायतार्थ फोर्स का गठन हुआ। इसमें 2013 बैच के प्रदेश भर के आरक्षक जुड़े।

नवजीवन सहायतार्थ फोर्स पुलिस के जवानों की अनूठी पहल है। प्रकृति को बचाना सभी का कर्तव्य है। ये लोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। भिंड के चंदूपुरा में ही इनके रोपे पौधे अब पेड़ बन चुके हैं।
-प्रो. इकबाल अली, प्रोफेसर, चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिंड


भिंड के सीतानगर में रोपे गए पौधे अब पेड़ हो चुके हैं। इनके नीचे खड़े आरक्षक गिरीश शर्मा (दाएं) और सुनील भदौरिया (बाएं)। नईदुनिया

अब एक दर्जन से ज्यादा सब इंस्पेक्टर, वन विभाग के कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी जुड़ चुके हैं। समूह के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों को सभी साथी इंटरनेट मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। भुवनेश्वर, जयपुर और दूसरे शहरों के जवान भी जुड़ गए। ये लोग प्रशिक्षण के दौरान संपर्क में आए थे। ये भी अपने राज्यों में पौधे रोपने का कार्य कर रहे हैं।

समूह उठाता है पौधे रोपने का खर्च : गिरीश शर्मा ने बताया कि पौधे रोपने का खर्च समूह की ओर से दिया जाता है। जगह का चयन स्थानीय साथी करते हैं। किसी सदस्य के घर बेटी के जन्म लेने पर 21 पौधे रोपे जाते हैं। बेटे का जन्म होने पर 11 पौधे रोपे जाते हैं। इसका दायरा जन्मतिथि और छोटे-मोटे अन्य खुशी के अवसरों तक बढ़ गया है। समूह आपस में धन संग्रह कर एक फंड इसके लिए तैयार रखता है।

इन जिलों में सदस्य : फोर्स में जुड़े 200 जवान, सब इंस्पेक्टर, वनकर्मी और समाजसेवी मध्य प्रदेश के इंदौर, रीवा, रतलाम, भोपाल, भिंड, मुरैना, बालाघाट, राजगढ़ और ग्वालियर में रहते हैं। इन्हीं स्थानों पर पौधारोपण करते हैं।

अबकी खास है सावन, रविवार से शुरू होकर इसी दिन होगी समाप्ति

सौरभ चंद्र पांडेय, वाराणसी : सनातन संस्कृति का सबसे पवित्र माह सावन 25 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इस विशेष माह में शिव की आराधना, उपासना और अभिषेक से मनोकामना पूर्ण होती है। मन में भक्ति, शक्ति, पवित्रता, उल्लास, साधना और अध्यात्म की भावना उमड़ पड़ती है। सनातनी मन अपने आपको शिवभक्ति में समाहित करने लगता है। ख्यात ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी के अनुसार श्रावण मास की शुरुआत रविवार से तो समाप्ति भी रविवार को ही हो रही है, जो बेहद खास है। प्रतिपदा को श्रवण नक्षत्र का संयोग चार चांद लगाने वाला होगा। सावन में नवग्रह पूजन विशेष फलदायी होता है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रो.विनय कुमार पांडेय के अनुसार सावन महीने में पवित्रता पूर्ण जीवनयापित करें। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। शिव का गंगाजल, गाय के दूध से अभिषेक करें। फल-फूल, बिल्वपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री से शिव का दरबार सजाएं और उनकी महाआरती करें।

पं.धनंजय पांडेय के अनुसार सावन में द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्व प्रधान ज्योतिर्लिंग आदिविश्वेश्वर को माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए सावन में रुद्राभिषेक, तैलाभिषेक, जलाभिषेक किया जाता है। अलग-अलग कामनाओं के लिए अभिषेक के विधान बनाए गए हैं।

बुलंद हौसले : लद्दाख के निगहबानों से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान

विवेक सिंह, जम्मू

कारगिल विजय दिवस

- खुद को सैनिक के तौर पर देखता है हर युवा, चरवाहे भी रखते हैं दुश्मन पर नजर
- कारगिल युद्ध में लद्दाख के 24 सैनिकों ने दिया था देश की खातिर बलिदान
- अपने बच्चों को सैनिक बनने की प्रेरणा देते हुए बड़ा करते हैं लद्दाख के लोग

यह जगजाहिर है कि लद्दाखी सैनिकों के साथ क्षेत्र के स्थानीय लोग भी देश की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं। कारगिल युद्ध में लोगों ने भी पूरा सहयोग दिया था। यही कारण है कि कारगिल विजय दिवस को लेकर स्थानीय निवासियों का भारी उत्साह होता है। इससे सेना का हौसला और मजबूत होता है।
– लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मुसावी, सैन्य प्रवक्ता, कश्मीर

दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के साथ कंधा मिलाकर लड़ते आए लद्दाख के लोगों के बुलंद हौसले से पाकिस्तान और चीन दोनों देश कांपते हैं। दुश्मनों को धूल चटाने का माद्दा रखने वाले लद्दाखियों का जज्बा ऐसा है कि होश संभालते ही यहां के बच्चे सैनिक बनने के लिए खुद को तैयार करने लगे हैं। यहां तक कि मवेशियों के सहारे जीवन बिताने वाले चरवाहे भी दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं। लद्दाख के लोगों का हौसला देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणास्रोत है।

लद्दाखी सैनिकों ही नहीं, यहां के स्थानीय लोगों से भी पाकिस्तान और चीन खौफ खाते हैं। लद्दाख के लोग शुरू से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते आए हैं, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद यहां के युवाओं में सैनिक बनने का जज्बा सिर चढ़कर बोलने लगा। यह कहना है लेह के चुशोत गोंगमा के रहने वाले बुजुर्ग पूर्व सैनिक गुलाम मुहम्मद का। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा ले चुके गुलाम मुहम्मद के दोनों बेटे लद्दाख स्काउट्स में हैं। उन्होंने बताया कि गांव के 63 घरों में से शायद ही ऐसा कोई होगा, जिसका कोई न कोई सदस्य सेना में न हो। उनका कहना है कि युवा सेना में हैं, बच्चे सैनिक बनने की तैयारी कर रहे हैं। घर संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं और हम जैसे बुजुर्गों की है। यही हमारी जिंदगी है।

कुदरती तौर पर दक्ष हैं लद्दाखी सैनिक

वर्ष 1971 के युद्ध के वीर चक्र विजेता कर्नल वीरेंद्र साही का कहना है कि लद्दाखी सैनिक हाई अल्टीट्यूड वारफेयर के लिए कुदरती रूप से मजबूत हैं। वे देश के आजाद होने के बाद से ही बहादुरी की मिसाल कायम करते आए हैं। लद्दाख स्काउट्स की पांच बटालियन अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ने के लिए दक्ष हैं।

कारगिल में घुसे दुश्मनों की चरवाहों ने ही दी थी खबर : लद्दाख में चरवाहे भी दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं। मई 1999 में कारगिल के चरवाहों ताशी नामग्याल और सेरिंग मोटुप ने कड़ी जद्दोजहद कर सेना को यह सूचना दी कि पाकिस्तानी सेना घुस आई है। इसके बाद सेना ने उनके साथ वहां जाकर खुद इसकी पुष्टि की थी। वर्तमान में लद्दाख के चरवाहे उसी जज्बे के साथ अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाकर चीनी सैनिकों के घुसपैठ करने की सूचना देकर चंद मिनटों में पूरे देश को सचेत कर देते हैं।

लद्दाखियों के लिए कारगिल विजय दिवस महज कार्यक्रम नहीं : कारगिल युद्ध में 24 लद्दाखी सैनिकों ने बलिदान दिया था। द्रास में 22वें कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे। लद्दाख के लोगों के लिए कारगिल विजय दिवस शहीदों की याद में होने वाला महज एक सैन्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह उनके लिए लद्दाख की सुरक्षा के लिए अपने परिवारों द्वारा दिए जा रहे योगदान को याद करने का बड़ा दिन है।

दैनिक जागरण

मनुष्य की नियति को आकार देने में गुरु की महती भूमिका होती है

खतरा बढ़ाता पाकिस्तान

जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश के एक माह के भीतर विस्फोटक से लैस एक ड्रोन को मार गिराने में मिली सफलता यह तो बताती है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हैं, लेकिन इस घटना से यह भी पता चलता है कि शत्रुओं के दुस्साहस में कोई कमी नहीं आई है। गत दिवस जम्मू के कानाचक्क इलाके में पुलिस ने जिस ड्रोन को मार गिराया, उससे पांच किलो की आईईडी भी बरामद हुई है। इसका अर्थ है कि सीमा के अंदर ऐसे तत्व सक्रिय हैं, जो सीमा पार की दुष्ट ताकतों के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर आतंकी हमले की फिराक में हैं। चूंकि उक्त ड्रोन पाकिस्तान सीमा के निकट ही मार गिराया गया इसलिए यह संदेह पुख्ता होता है कि उसे सीमा पार से ही भेजा गया। पुलिस को संदेह है कि यह काम आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद ने किया। यह वही आतंकी संगठन है, जिसे पाकिस्तान का सहयोग और संरक्षण प्राप्त है। भारत इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने जैश के साथ लश्कर के आतंकियों को भी तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान भेजा है। वह तालिबान के जरिये अफगानिस्तान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में भी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का मतलब होगा वहां पाकिस्तान का वर्चस्व कायम हो जाना और किस्म-किस्म के जिहादियों को खुली छूट मिल जाना।

पाकिस्तान अपने यहां के साथ-साथ जिस तरह अफगानिस्तान में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में जुटा है, उससे यही संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए भारत इससे संतुष्ट नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन को मार गिराया गया। भारत का उद्देश्य पाकिस्तान और वहां पल रहे भारत विरोधी आतंकी संगठनों के दुस्साहस का दमन करना होना चाहिए। जब तक इस दुस्साहस का दमन नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान से ड्रोन हमलों का खतरा टलने वाला नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जम्मू-कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में एक अर्से से ड्रोन देखे जा रहे हैं। यह इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि खुफिया एजेंसियां अंदेशा जता चुकी हैं कि आतंकी ड्रोन के जरिये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। तथ्य यह भी है कि बीते डेढ़ साल में ड्रोन के जरिये हथियार, विस्फोटक, मादक पदार्थ और पैसे भेजे जा चुके हैं। यह ठीक है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में पूरी तौर पर सफलता मिलेगी।

हाईकमान के लिए चुनौती

पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पद ग्रहण समारोह और उससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से विधायकों को दी गई चाय पार्टी में जो कुछ देखने को मिला, उससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। हाईकमान ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर अपनी इच्छा तो पूरी कर ली, लेकिन उसकी चुनौती कम नहीं हुई है। शुक्रवार को हुए दोनों आयोजनों में यह साफ झलका कि सिद्धू व कैप्टन के बीच दूरियां कम नहीं हुई हैं और सिद्धू के तेवरों से भी यही संकेत मिले हैं कि वह बेशक सभी को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हों, लेकिन कैप्टन को लेकर उनका रवैया बदला नहीं है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद से लेकर अध्यक्ष बनने तक वह विपक्ष के साथ अपनी ही पार्टी की सरकार पर भी हमलावर रहे हैं, लेकिन अब जब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है तो भी उनकी बोली व अंदाज वही है। पार्टी के पहले ही आयोजन में प्रदेश प्रभारी हरीश रावत को भी दोनों के बीच सामंजस्य दर्शाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी है। कैप्टन की चाय पार्टी से उठकर चले जाने के बाद उन्हें दोबारा बुलाना और फिर कैप्टन के साथ बिठवाना ही रावत के लिए कठिन कार्य बन गया। निश्चित तौर पर ताजपोशी समारोह के मंच से नेताओं, कार्यकर्ताओं में सही संदेश नहीं गया है। हालांकि कैप्टन ने आशंकाओं को गलत साबित करते हुए न सिर्फ समारोह का न्योता स्वीकार करके यह जताने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने कहे मुताबिक हाईकमान के फैसले को मान लिया है। मंच से भी उन्होंने सिद्धू को बधाई दी और साथ मिलकर काम करने को भी कहा। 'ठोको ताली' जुमले से मशहूर सिद्धू को भी यह ध्यान रखना होगा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। चाय पार्टी हो या ताजपोशी समारोह का मंच या फिर उनका भाषण, कैप्टन के प्रति कहीं भी उनमें नरमी, विनम्रता या कृतज्ञता नजर न आना यह संकेत देता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस के भीतर माहौल शांत होने वाला नहीं है। संगठन व सरकार में तालमेल न बैठा तो कांग्रेस को दो माह की कवायद के बाद हुए इस फैसले से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसे हाईकमान की असफलता ही माना जाएगा। पंजाब में हाईकमान ने जो यह दो ध्रुव बना दिए हैं, अब इनके बीच दूरियां कम करना ही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा।

तबाही के मुहाने पर अफगानिस्तान



ब्रह्मा चेलानी

तालिबान के समक्ष अमेरिकी समर्पण से अफगानिस्तान में शांति स्थापना की संभावना कमजोर होने के साथ ही दक्षिण एशिया में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ा है



अवधेश राजपूत

अफगानिस्तान से निकलने की लचर अमेरिकी योजना और जल्दबाजी ने अफगानिस्तान को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है। जब तालिबान काबुल के आसपास तेजी से अपना कब्जा जमा रहा है, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन वापसी के इस कदम को तर्कसंगत ठहरा रहे हैं। इसमें अफगानियों के लिए विध्वंस के संकेत ही छिपे हैं। इससे अमेरिका के प्रति वैश्विक भरोसा भी घटेगा। बाइडन ने अपने शीर्ष सैन्य कमांडर की राय को भी दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर मुहर लगाई। यह एक ऐसे फैसले का प्रतीक बना, जिसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना एक आतंकी मिलिशिया के हाथों परास्त हो गई। तालिबान अफगानिस्तान से अमेरिका को बेदखल करने के अपने स्वप्न को साकार करने के कगार पर है। इसका असर अफगानिस्तान से परे भी दिखेगा। अमेरिकी शक्ति के पराभव की ओर संकेत करने वाला यह घटनाक्रम वैश्विक जिहादी मुहिम का हौसला बढ़ाने का काम करेगा।

बाइडन ने दुरुस्त ही कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं गया था। वह तो असल में 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमला का प्रतिशोध लेने के लिए ही वहां घुसा था। इस देश में हाईवे, अस्पताल, बांध और संसद बनाने का जिम्मा भारत जैसे देशों का रह गया। भले ही अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से वापसी करें, लेकिन यह सिलसिला तो एक जुलाई को तबसे ही शुरू हो गया, जब अमेरिका ने वहां अपने आखिरी एयरबेस बगराम में बिजली आपूर्ति बंद कर रातोंरात अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। यह एयरबेस अमेरिकी युद्ध का केंद्रबिंदु जैसा रहा। इससे सुरक्षा आवरण भरभरा गया। अफगान सुरक्षा बल वहां पहुंचकर स्थिति अपने नियंत्रण में लेते, उससे पहले ही लुटेरे लूट-खसोट कर चले गए। अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी ने वियतनाम की याद दिला दी है। अमेरिका उस युद्ध को भी आधा-अधूरा छोड़कर भाग निकला था। जैसे अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में अपने साथियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था उसी तरह यह वापसी अफगानियों को बर्बर इस्लामिक ताकतों की मोहताज बनाकर छोड़ देगी।

बाइडन ने अफगानिस्तान से वापसी को वाजिब बताते हुए कहा कि आखिर अमेरिका की कितनी संतानों के जीवन को जोखिम में डालेंगे? उनकी यह भ्रामक टिप्पणी तथ्यों को नेपथ्य में डाल रही है। एक जनवरी, 2015 को जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सैन्य भूमिका समाप्त हुई तबसे उसकी तपिश अफगान सुरक्षा बलों की ही झेलनी पड़ी है। इन वर्षों के दौरान अमेरिका के 99 जवान मारे गए, जबकि अफगान सुरक्षा बलों के 28,000 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

अमेरिका का अपने सबसे लंबे युद्ध का समापन तो तार्किक है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि ऐसे आंतकी समूह के साथ सौदेबाजी करनी पड़े, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने पैदा किया और आज भी बदस्तूर उसकी परवरिश कर रही हैं। 1996 से 2001 के बीच तालिबान का शासन क्रूरता की पराकाष्ठा वाला रहा। उसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का विध्वंस भी शामिल था। इसने 1975-79 के दौरान कंबोडिया में चीन समर्थित कम्युनिस्ट शासन की भयावहता की ही याद दिलाई। गत वर्ष तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तालिबान से किया गया समझौता और अब बाइडन द्वारा उस पर अमल एक ऐतिहासिक गलती के रूप में गिना जाएगा। अमेरिका दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकियों से समझौता किए बगैर और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाले बिना भी अफगानिस्तान से विदाई ले सकता था। बाइडन ने ट्रंप के तमाम फैसलों को पलटने में जरा भी देरी नहीं की, पर अफगानिस्तान के मामले में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती का ही अनुसरण किया। इससे भी बदतर बात यह है कि बाइडन की जल्दबाजी ने जमीनी हालात तेजी से बदलकर आसन्न पराजय का द्वार खोल दिया है। अफगानिस्तान में बदलती स्थितियों के गहरे निहितार्थ हैं। इससे वहां भारत के खिलाफ नया आतंकी मोर्चा खड़ा हो सकता है, जिससे भारत का ध्यान चीन से भटक सकता है, जो उसे सीमा पर परेशान किए हुए है। यह आशंका भी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां अफगान धरती से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बढ़ा सकती हैं।

अमेरिकी फौज की एक छोटी टुकड़ी का अफगानिस्तान में तैनात रहना उचित होता। इससे न केवल अफगान सुरक्षा बलों के लिए मदद का ढांचा मौजूद रहता, बल्कि सुरक्षा आवरण के एकाएक ढहने का जोखिम भी कम हो जाता। साथ ही आतंकियों की ऐशगाहों के फिर से उभरने पर भी विराम लगता। बाइडन इसके बजाय उस समझौते पर अमल में आगे बढ़ गए, जिसका तालिबान पहले से ही उल्लंघन कर रहा है। 25 जून को अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी कह चुके हैं कि अफगानिस्तान का भविष्य अब खुद उसके हाथ में है। असल में तालिबान के समक्ष अमेरिकी समर्पण ने अफगानिस्तान में शांति स्थापना को कमजोर करने के साथ ही दक्षिण एशिया में अस्थिरता का खतरा बढ़ा दिया है। जैसा कि गनी ने कहा, 'अब अमेरिका की भूमिका न्यून हो गई है और शांति या अशांति का सवाल पाकिस्तान पर निर्भर करता है।'

बाइडन के कदम पीछे खींचने से चीन को अपने पिट्ठू पाकिस्तान के जरिये अफगानिस्तान में पैठ बढ़ाने का एक अनुकूल अवसर मिला है। अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और बेल्ट एंड रोड परियोजना में उसे ईरान एवं पाकिस्तान के बीच सेतु बनाने के लिए चीन तालिबान को वह दो पेशकश करेगा, जिसकी इस समूह को शिद्दत से दरकार है। पहली अंतरराष्ट्रीय मान्यता और दूसरी आर्थिक मदद। तालिबान को रूस से भी मान्यता मिलने की उम्मीद है। ऐसे में तालिबान स्वयं में सुधार करने के बजाय अपने मध्यकालीन तौर-तरीकों को ही और सख्ती से लागू करेगा। तालिबान व्यापक वैश्विक जिहादी मुहिम का ही एक हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ने के उसके पूरे होते सपने से दुनियाभर में जिहादी आतंकवाद को नई ताकत मिलेगी। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने 2014 में लिखा था कि गत चार दशकों के दौरान विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े मसलों पर बाइडन का रुख गलत रहा है। अब अफगानिस्तान में आकार लेती त्रासदी के रूप में बाइडन को लेकर की गई गेट्स की वह तल्ख टिप्पणी पुष्ट होती दिख रही है।

(लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

गुरु–शिष्य परंपरा की महत्ता

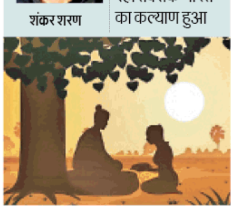


शंकर शरण

भारतीय परंपरा में शिक्षा दान का कार्य त्यागी लोगों ने ही किया। जब तक ऐसा रहा तब तक भारत का कल्याण हुआ

यह विडंबना ही है कि पराधीन भारत में हमारी भाषा, शिक्षा और संस्कृति उतनी बुरी अवस्था में नहीं थी, जितनी अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद स्वदेशी राज में हो गई। शिक्षा की धारणा भी मूलतः स्खलित हो गई। महान कवि-चिंतक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' के शब्दों में कहें तो शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करने का एकाधिकार उस राजनीतिक वर्ग का हो गया है, जिसका आज ज्ञानोपार्जन से कोई नाता नहीं, जो केवल सफलता के फौरी नुस्खे बांटते रहते हैं। ऐसी अवस्था में भारत के महान गुरुओं का स्मरण कर लेना भी एक आवश्यक कार्य है, ताकि लोगों में शिक्षा और शिक्षक की अर्थवत्ता की लौ जलती रहे। भारतीय ज्ञानियों के अनुसार, जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति-संचार हो, वह गुरु कहलाता है। इसके लिए देने वाले में शक्ति और लेने वाले में ग्रहण करने की योग्यता अपेक्षित है। शिष्य में भी पात्रता होनी आवश्यक है। सातवीं सदी में भारतीय शिक्षा को देखने वाले चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने लिखा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आने वाले छात्रों में दस में दो-तीन ही उत्तीर्ण हो पाते थे, किंतु यह भी सत्य है कि व्याकुल शिष्य को गुरु मिल ही जाते हैं। एकलव्य की कथा इसी का संकेत है। यहां तक कि भौतिक रूप से मौजूद न रहने पर भी महान गुरुओं के वचन, उनकी पुस्तकें हमारा वही मार्गदर्शन कर सकती हैं, जैसा वे स्वयं करते। केवल सच्ची अभीप्सा होनी चाहिए। केवल पांडित्य प्रदर्शनकारी गुरु नहीं हो सकते। सच्चे गुरु यश, धन आदि जैसी स्वार्थ-सिद्धि लिए शिक्षा नहीं देते। वे प्रेम और कर्तव्यवश अपना कार्य करते हैं। प्रसिद्ध दक्षिणामूर्तिस्तोत्र में उल्लेख मिलता है कि गुरु 16 वर्ष का लड़का था, जिसने 80 वर्ष के मनुष्य को सिखाया। गुरु वही हो सकता है जिसे शास्त्रों का मर्म ज्ञात हो। केवल शब्दाडंबर नहीं, अपितु जिसमें अंतदृष्टि विकसित हो चुकी हो। दूसरे वे निष्पाप हों। उनका चरित्र शुद्ध और उज्ज्वल हो। अशुद्ध चित्त व्यक्ति धर्म नहीं सिखा सकता।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत के महान पूर्वजों में सबसे पहला गुण उनकी वीरता बताया है। ब्राह्मण गुरुओं में भी उनकी निर्भीकता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यबोध वही तत्व है, जिन्होंने झूठ के सामने कभी सिर नहीं नवाया। वे धर्म को छोड़ किसी वस्तु का डर नहीं रखते थे। मृत्यु का भी नहीं। वे जानते थे कि उनसे छीन लेने को कुछ नहीं है। उनका सर्वस्व तो उनके मन के अंदर ही था। वे सबके कल्याण की चिंता करते थे। गुरुदेव टैगोर के अनुसार, उन पूर्वजों का सिखाया हुआ हम ग्रहण करें। उसका अनुसरण करें, उनके जैसा होने का प्रयत्न करना ही उनके प्रति सच्ची भक्ति करना है। अपने विद्यालय में बच्चों को विद्यारंभ की शिक्षा देते हुए टैगोर कहते थे, 'हमारे पूर्वज जिस व्रत का अवलंबन करके बड़े हुए, वीर बने, उसी शिक्षा को, उसी व्रत को ग्रहण करने के लिए तुम सबका मैंने आह्वान किया है। अगर हमारा प्रयत्न सफल हुआ तो तुममें से प्रत्येक बालक सच्चे अर्थ में वीर बनेगा। तुम भय से व्याकुल नहीं होगे, दुःख से विचलित नहीं होगे। अपनी सभी शक्तियों को लगाकर कर्तव्य करोगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे। तुम्हारे प्रयत्न से भारतवर्ष फिर से उज्ज्वल हो उठेगा, तुम जहां रहोगे वहीं मंगल होगा। तुम सबकी भलाई करोगे और तुमको देख कर सब अच्छे रहेंगे।'



भारत में समृद्ध रही है गुरु-शिष्य संस्कृति। फाइल

सच्चा शिक्षक केवल सहायता देता है। बीज और पौधे की तरह, हर विद्यार्थी में अपनी स्थिति संचित होती है। वह अपने-आप सीख लेता है। शिक्षक केवल उसके मार्ग के विघ्नों, कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। यहीं उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। शिक्षक को मात्र यह करना है कि बच्चा अपने हाथ-पैर, आंख-कान, बुद्धि का समुचित उपयोग करना सीख ले। अज्ञेय ने भी अपने जीवन की दो अनोखी अनुभूतियों का वर्णन करते अनायास इसी की पुष्टि की। एक अनुभव उन्हें उत्तराखंड के पहाड़ पर एक गिरिजातीय वृद्धा के साथ, दूसरा जापान में एक संवेदनशील सज्जन के साथ हुआ। दोनों में जो अनोखी ज्ञान-शक्ति थी, उसे अज्ञेय ने उन्हीं के भीतर की संपन्नता कहा था। वह शक्ति, संपन्नता, विवेक बाहर से किसी को नहीं दिए जा सकते। यदि वह किसी के अंदर हो, तभी उसे जगाया, विकसित किया जा सकता है। यही सच्चे गुरु का काम है। ये बातें काल्पनिक आदर्श नहीं हैं। भारतीय शास्त्रों में ही नहीं, आधुनिक युग के सभी मनीषियों ने भी उसे दोहराया है। स्वामी विवेकानंद, श्रीअरविंद और रवींद्रनाथ टैगोर के लेखन, विचार और कार्य में भी यह है। प्राचीन गुरुकुलों से लेकर टैगोर के शांति निकेतन तक, उन विचारों की अचूक व्यावहारिकता के प्रमाण मिलते हैं। टैगोर के शब्दों में, 'शिष्य के चित्त को गतिशील कर उठाना गुरु की अपनी साधना का अंग है। उनके साथ से शिष्य के जीवन को प्रेरणा मिलती है।' वे गुरु-शिष्य के बीच परस्पर सहज-सापेक्ष संबंध को ही विद्यादान का प्रधान माध्यम मानते थे। उस शिक्षा-दर्शन के व्यवहार का सुपरिणाम देखा जा सकता है कि शांति निकेतन ने भारत को कई क्षेत्रों में अनेक बड़ी-बड़ी प्रतिभाएं दीं। कहने का तात्पर्य है कि केवल कक्षा में पाठ सिखाने, सिद्धांतों, तथ्यों का वर्णन करने से शिक्षा नहीं होती। वह होती है गुरु द्वारा अपने को प्रेम और निष्ठा से उड़ेल देने में, परंतु सभी शिक्षाओं का मूल है-धर्म। गुरु का काम शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना है, न कि उसकी बुद्धि तेज करना।

निःसंदेह भारतीय परंपरा में शिक्षा दान का कार्य त्यागी लोगों ने ही किया। जब तक ऐसा रहा तब तक भारत का कल्याण हुआ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, जब तक इस देश में शिक्षा दान का भार पुनः त्यागी लोगों को नहीं दिया जाता, तब तक भारत को दूसरे देशों के तलवे चाटने होंगे।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

गुरु की महिमा

विद्या मुक्ति की साधना है और गुरु इसी विद्या की अनेक धाराओं का संगम। यदि किसी मनुष्य ने गुरु का मंत्र ग्रहण नहीं किया तो समझिए वह पृथ्वी पर भार स्वरूप है। ऐसा मानव कभी गुरु महिमा का विस्तार नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को गुरु का अनुशासन, प्रेम और आशीष समय पर प्राप्त कर लेना चाहिए। तभी वह गुरुभक्ति और गुरुशक्ति का वाहक बनने में सक्षम हो सकेगा। जिस प्रकार भगवान ने गुरु की ओर संकेत कर उन्हें स्वयं से श्रेष्ठ बताया, उसी तरह माता-पिता भी गुरु को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में माता-पिता तो जन्म देकर पालन-पोषण करते हैं, लेकिन किसी को आदर्श मनुष्य का आकार देने वाला तो गुरु ही है।

गुरु संसार की श्रेष्ठ पदवी है, जो अपने शिष्य को सर्वोत्तम बनाने के धर्म का निर्वहन करता है। केवल गुरु-शिष्य संबंध ही आध्यात्मिक संबंध है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का मार्ग दिखाता है। गुरु ही जीवन का रहस्य बताता है। गुरु ही मानव के जीवन से जुड़े लक्ष्य भेद को सिद्ध कराने में समर्थ हो सकता है। जिस भी साधक ने गुरु की महिमा को आत्मसात किया, वह भवसागर से पार हो गया। शरीर व आत्मा का तत्व दर्शन, जीव की मीमांसा, ईश्वर की खोज और संसार का आश्रय गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। आत्मोद्धार के पथिक गुरु महिमा से पूर्ण सफलता पाते हैं। इसीलिए गुरु को पारंपरिक एवं मूल पथप्रदर्शक बताया गया है, जिस पर चलकर आत्मबोध की यात्रा सरल हो जाती है।

महान गुरु ही जीवन का सच्चा निर्माता है। वह अपने बुद्धि कौशल से शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। यह गुरु की महिमा ही है कि वह अपने गुरु से भी आगे बढ़कर अपने शिष्य को महान बनाता है। भगवान श्रीराम के लिए गुरु वशिष्ठ, पांडवों के लिए गुरु द्रोण और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के लिए आचार्य चाणक्य जैसे गुरु ही उनकी समग्र सफलता के स्रोत थे। विद्या दान की गुरु कृपा ही अपने शिष्यों का महिमामंडन करने का माध्यम सिद्ध होती है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

नई पीढ़ी के भविष्य पर ग्रहण

सुधीर कुमार

पढ़ाई बीच में छूटने के कारण बच्चे मानव संसाधन के रूप में परिणत नहीं हो पाते, जो देश के लिए राष्ट्रीय क्षति की तरह है

देश में स्कूल ड्रापआउट यानी बच्चों का असमय विद्यालय छोड़ देना एक गंभीर समस्या रही है। हालांकि 2018-19 की तुलना में प्राथमिक स्कूलों में ड्रापआउट दर घटी है, किंतु माध्यमिक स्तर यह चिंता का सबब बना हुआ है। 2018-19 में प्राथमिक स्कूलों में ड्रापआउट दर 4.45 फीसद थी, जो 2019-20 में 1.5 फीसद पर आ गई, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह 17.87 फीसद से घटकर 16 फीसद हो गई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तीनों स्तरों पर लड़कियों के मुकाबले लड़कों में औसत ड्रापआउट दर अधिक है।

प्राथमिक स्कूलों में देश के जिन सात राज्यों में ड्रापआउट सर्वाधिक है, उनमें से छह राज्य पूर्वोत्तर के हैं। वहीं देश के सात राज्यों तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम, महाराष्ट्र, आंध्र, केरल, हरियाणा और सात केंद्रशासित प्रदेशों में ड्रापआउट दर शून्य है। बिहार और झारखंड में उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट समस्या सबसे अधिक है, जहां प्रत्येक सौ में से नौ बच्चे आठवीं कक्षा से पूर्व ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। माध्यमिक स्तर पर सबसे कम ड्रापआउट की दर पंजाब (1.6 फीसद) में है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह दर 34.3 फीसद, असम में 32.3 फीसद, त्रिपुरा में 26.7 फीसद और ओडिशा में 23.6 फीसद तक है।

उच्च ड्रापआउट दर देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस कारण बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। पढ़ाई के अभाव में बच्चे मानव संसाधन के रूप में परिणत नहीं हो पाते हैं, जो देश के लिए राष्ट्रीय क्षति की तरह है। गरीबी, पढ़ाई में अरुचि, शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव, महंगी शिक्षा, स्कूल का दूर होना, कम उम्र में विवाह और बाल-अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण स्कूलों में ड्रॉपआउट की समस्या खत्म नहीं हो रही है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बच्चे आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद घर से समर्थन न मिलने तथा महंगी शिक्षा के कारण बच्चे पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं।

वहीं कुछ अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने की पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं देते हैं। उनके ऊपर कम उम्र में रोजगार पाने का दबाव बनाया जाता है। दूसरी ओर भोजन योजना, मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और साइकिल आदि के वितरण के कारण एक समय तक बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित रहते हैं, लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़कर घरेलू व अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शिक्षकों की कमी और अध्यापन के प्रति शिक्षकों में दिलचस्पी कम होने के चलते भी अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। ड्रापआउट के बाद कई बच्चे बाल श्रम की गिरफ्त में आ जाते हैं, जिससे उनका बचपन तबाह तथा भविष्य अधर में डूब जाता है। ड्रापआउट कम करके ही बच्चों को स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

(लेखक बीएचयू में शोध अध्येता हैं)

खेलों पर और देना होगा ध्यान

'विजयगाथा लिखने को बेताब बेटियां' शीर्षक से लिखे आलेख में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों की दुनिया में आधी आबादी के लगातार बढ़ते दम पर प्रकाश डाला। उनका कहना उचित ही है कि स्वतंत्र भारत में महिला खिलाड़ियों ने ओलिंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने में अपनी ओर से कोई कोताही नहीं की। इस सूची में कर्णम मल्लेश्वरी से लेकर मेरी कोम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिखाया कि यदि अवसर मिले तो महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं। इसके बावजूद अगर समग्र तस्वीर पर गौर करें तो वह बहुत उत्साहजनक नहीं लगेगी। इतने बड़े देश का ओलिंपिक पदक तालिका में किसी उल्लेखनीय स्थान पर न होना दिल को बहुत टीस देने वाला है। इसमें संदेह नहीं कि बीते कुछ वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की कुछ संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं, लेकिन वे भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। साथ ही भारतीय खेल परिदृश्य पर क्षेत्रीय असंतुलन की खाई भी सालने वाली है। मिसाल के तौर पर देश की आबादी में हरियाणा और पंजाब की आबादी जहां मात्र चार प्रतिशत है, लेकिन देश के ओलिंपिक दल में इन दोनों राज्यों का सम्मिलित प्रतिनिधित्व 40 प्रतिशत यानी एक तिहाई से भी अधिक है। अपनी इस सफलता के लिए ये दोनों राज्य और वहां स्थापित ढांचा बधाई का पात्र है, लेकिन इससे संबंधित प्राधिकारी संस्थाओं के समक्ष कुछ प्रश्न भी खड़े होते हैं कि संभवतः उनके प्रयासों में कहीं न कहीं कोई कमी रह जा रही है।

मेलबाक्स

अन्यथा कोई कारण नहीं कि देश के अन्य इलाकों से भी प्रतिभाएं सामने न आ सकें। इसलिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो जाता है कि देश के सभी क्षेत्रों में खेलों की प्रतिभाओं को सही समय पर चिन्हित कर समुचित पर्यवेक्षण में प्रशिक्षित कर आगे बढ़ाया जाए। यदि यह संभव हो सका तो इसका परिणाम देश को प्राप्त पदक तालिका में भी परिलक्षित होगा।

साकेत शर्मा, नई दिल्ली

अपरिपक्व राजनीति का परिचायक

विपक्षी दलों द्वारा मानसून सत्र के पहले ही दिन संसदीय कार्यवाही के दौरान जबरदस्त व्यवधान उत्पन्न करके प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल नए सदस्यों से संसदीय परंपराओं के तहत परिचय न करवाने देना, वह भी पेगासस स्पाइवेयर प्रकरण को आधार बनाकर जिसका केंद्र सरकार के विरुद्ध विपक्ष के पास कोई तथ्यात्मक आधार भी नही है, निःसंदेह संसदीय इतिहास की गरिमा को चोटिल करती अति शर्मनाक व घोर निंदनीय घटना है। इतना ही नहीं राज्यसभा में पेगासस स्पाइवेयर प्रकरण पर स्पष्टीकरण देते समय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री के हाथों से टीएमसी सांसद द्वारा पेपर छीनना, बोलने नहीं देना और पेपर को फाड़कर राज्यसभा के अध्यक्ष की ओर उछाल देना, ऐसी आक्रोशित और अशोभनीय हरकतों से संसदीय मर्यादाओं को ठेस पहुंचती है। यह लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। राज्यसभा को हाउस आफ लार्ड्स की तरह माना जाता है। देश के प्रधानमंत्री जब विपक्ष से कठिन से कठिन सवाल पूछने के लिए कहते हैं तब प्रश्न पूछने के बजाय विपक्षी दल दोनों सदनों की संसदीय कार्यवाही में बेवजह व्यवधान पैदा कर उन्हें बाधित कर देते हैं। क्या विपक्ष के पास अब केवल हंगामा करना, संसदीय कार्यवाही रोकना जैसे नकारात्मक मुद्दे ही शेष बचे हैं। निश्चित ही सांसदों को भी पता है कि संसदीय सत्र के दौरान प्रति मिनट का खर्चा लगभग एक लाख साठ हजार रुपये आता है। तब देश की प्रगति के लिए प्राप्त टैक्सपेयर्स का पैसा बेवजह हो-हल्ला करके बर्बाद क्यों किया जा रहा है। संसदीय कार्यवाही रोकने से कई जरूरी बिल कैसे पारित हो पाएंगे और कैसे बेहतर राष्ट्र, का निर्माण हो पाएगा। बाद में यही विपक्ष अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, उच्च स्वास्थ्य सेवाएं, जल, सड़क, परिवहन, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि विषयों पर केंद्र सरकार को घेरकर अपनी सुविधानुसार दलीय राजनीति करेगा। ऐसे में बेहतर राष्ट्र निर्माण कैसे संभव है। इसे नकारात्मक व अपरिपक्व राजनीति की कुत्सित लहर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

7 फीसद की दर से बढ़ रहा है दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी का बाजार। कोरोना पाबंदियों के चलते 2020 में इसकी ग्रोथ माइनस 1.9 फीसद रही। 2024 में इस कारोबार के सात फीसद की वृद्धि दर पर लौटने का अनुमान है।

स्पिन बोल्डक में तालिबान ने की 100 लोगों की निर्मम हत्या

अफगान संकट ▶ पाक सीमा से लगे शहर में बर्बरता, सरकार ने कहा– सामूहिक नरसंहार पाकिस्तान के इशारे पर

तालिबानी आतंकियों के ठिकानों पर अमेरिका ने शुरू किए हवाई हमले

वाशिंगटन, एएनआइ: तालिबान ने अफगानिस्तान में हावी होने के बाद बकरीद पर पाकिस्तान सीमा से लगे व्यावसायिक शहर स्पिन बोल्डक में सौ नागरिकों का कत्लेआम करके खूनी खेल शुरू कर दिया है। नरसंहार के दौरान निर्दोष नागरिकों के साथ लूटपाट और घृणित कार्य किए गए। अफगान सरकार ने कहा है कि तालिबान ने अपने आका पाकिस्तान के इशारे पर यह जघन्य कांड किया है। इधर तालिबानी आतंकियों पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।

टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि आतंकियों ने यहां पूरे शहर में कोहराम मचा दिया है। शहर के आसपास अभी भी शव पड़े दिखाई दे रहे हैं। कम से कम सौ लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने बच्चों का भी बेरहमी से कत्ल किया।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस नरंसहार की पुष्टि की है। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता मीरवाइज स्टेनकजई ने कहा है कि आतंकियों ने अपने पंजाबी आकाओं (पाकिस्तान) के इशारे पर इस क्रूर घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि यह दुश्मन के असली चेहरे को उजागर करता है।

स्पिन बोल्डक वही स्थान है, जहां पर भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। इस शहर पर पिछले सप्ताह तालिबान ने कब्जा कर लिया था। फ्रांस 24 ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तालिबानी आतंकी तोड़फोड़ और लूटपाट कर रहे हैं। तालिबान ने नागरिकों की हत्या में शामिल होने से इन्कार किया है।

प्रेट्र के अनुसार, अफगान सेना पर हावी होते जा रहे तालिबान को थामने के लिए वापसी कर रही अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।

अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता जान किर्बी ने बताया कि मैं इस संबंध में पूरा विवरण नहीं दे सकता, लेकिन हमने अफगान सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए हवाई हमले किए हैं। उन्होंने कहा, सेना की वापसी के बीच भी हम हवाई हमले करने में सक्षम हैं। अफगानिस्तान में तैनात सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी हवाई हमले करने के लिए पूरी तरह अधिकृत और सक्षम हैं।

सीएनएन के अनुसार, एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिका सेना ने पिछले दिनों में तालिबान के ठिकानों पर छह या सात हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई अमेरिकी ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क विले के बयान के बाद हुई है। मार्क ने कहा था कि तालिबान ने 419 जिलों में से 212 जिलों पर कब्जा कर लिया है। वह तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है।


पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के शहर स्पिन बोल्डक में रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते तालिबानी और उनके समर्थक। यह तस्वीर 14 जुलाई की है। एपी

चार माह में 36 हजार परिवारों का पलायन: अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि बढ़ती हिंसा से नागरिक दहशत में पलायन कर रहे हैं। पिछले चार माह में 36 हजार से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं।

तालिबान ने अफगान कामेडियन को मारा: कंधार प्रांत में तालिबान ने खाशा ज्वान के नाम से प्रसिद्ध मशहूर कामेडियन नजर मोहम्मद की हत्या कर दी। अफगान सेना ने हवाई हमलों में बीस तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना ने कुंदूज शहर पर कब्जा करने आए तालिबानी आतंकियों को खदेड़ दिया है।

आठ हजार अफगान सहयोगियों को दिए जाएंगे वीजा : समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार अमेरिकी सीनेट ने आठ हजार अफगान सहयोगियों को वीजा देने की स्वीकृति दे दी है। ये वीजा उन नागरिकों को दिए जाएंगे, जो बीस साल में अमेरिकी सेना के सहयोगी बनकर रहे हैं। इनमें दुभाषिए, ड्राइवर, इंजीनियर या ऐसे ही सहयोगी रहे हैं।

अमेरिकी सेना के सहयोगी दुभाषिए का तालिबान ने किया सिर कलम

एएनआइ के अनुसार, तालिबान ने अमेरिकी सेना का सहयोग करने वाले अफगान नागरिकों की हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया है। सेना के साथ दुभाषिए के रूप में काम करने वाला सोहेल पारदिस काबुल में रहता है। वह बकरीद पर खोस्त प्रांत जा रहा था। उसके वाहन को रास्ते में आंतकियों ने रोक लिया। पहले उसे गोली मारी और बाद में उसका सिर कलम कर दिया। सीएनएन के अनुसार, पारदिस के दोस्त ने बताया कि उसे तालिबानी आतंकी कुछ समय से धमकी दे रहे थे। वे कह रहे थे कि तुम अमेरिकी जासूस और उनकी आंख-कान हो। तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ज्ञात हो कि अमेरिका को भी इस बात की आशंका है, इसीलिये उसने वीजा प्रक्रिया तेज कर दी है। कुछ ही दिनों में ढाई हजार अफगान सहयोगी और उनके परिवार को अफगानिस्तान से ले जाने की योजना है। इन्हें वीजा प्रक्रिया पूरी होने तक वर्जीनिया के सैन्य अड्डे पर रखा जाएगा।

तालिबान ने कहा, शांति के लिए अशरफ गनी को हटाना होगा

इस्लामाबाद, एपी : तालिबान ने कहा है कि वे सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहते हैं, लेकिन देश में शांति नहीं होगी, जब तक अशरफ गनी को हटाकर नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। समाचार एजेंसी एपी को दिए एक साक्षात्कार में तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा, तालिबान हथियार डाल देगा, जब काबुल में सभी पक्षों को स्वीकार्य सरकार का गठन हो जाएगा। इस नई सरकार में महिलाओं को काम करने, स्कूल जाने व राजनीति करने की छूट होगी, लेकिन उनका हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। जिन जिलों पर कब्जे हुए हैं, वहां इसी तरह से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कमांडरों ने इसका पालन नहीं किया है, उन्हें सैन्य न्यायाधिकरण के समक्ष पेशी के लिए कहा है। सुहैल ने कहा, अभी तालिबान को प्रांतीय राजधानी पर कब्जे के लिए रोक दिया गया है।


समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार के दौरान तालिबान का प्रवक्ता सुहैल शाहीन। एपी

नूर के हत्यारोपित की विदेश यात्रा पर रोक की अर्जी देगी पुलिस

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार युवक की विदेश यात्रा पर रोक लगाने को अदालत में अर्जी देने का फैसला किया है। नूर मकदम (27) की जघन्य हत्या से पूरा पाकिस्तान सकते में है। जानने वाले नेकदिल युवती के कामों को याद कर रहे हैं। पीएम इमरान ने पुलिस से बिना दबाव में आए जांच करने व पुख्ता सुबूतों के साथ अदालत में जाने के लिए कहा है। नूर की हत्या इस्लामाबाद में अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण व पिटाई की घटना के कुछ ही दिन बाद हुई है।

नूर की सिरकटी लाश इस्लामाबाद की एक पॉश कालोनी के घर से मंगलवार को मिली। पोस्टमार्टम में पता चला कि युवती को पहले गोली मारी गई और उसके बाद उसकी गर्दन काटी गई। पुलिस ने मामले में जाहिर जाफर नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। वह इस्लामाबाद के एक प्रभावशाली कारोबारी का बेटा है और उसके नूर के परिवार से अच्छे संबंध थे। नूर के पिता शौकत मकदम दक्षिण कोरिया और कजाखस्तान में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं। जाफर ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन में रहता है। ऐसे में पुलिस उसके वापस वहां भागने का खतरा उठाने को तैयार नहीं है और वह उसका पासपोर्ट जब्त कर यात्रा पर प्रतिबंध लगवाने की अर्जी अदालत में देगी। इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक काजी जमील उर रहमान ने जांच दल से कहा है कि जाफर का नाम देश बाहर जाने से रोक की सूची में दर्ज कराने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए।

चिनफिंग अचानक अरुणाचल से सटे तिब्बती शहर निंगची पहुंचे

- चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी चिनफिंग का पहला तिब्बती दौरा
- पूरी तरह गोपनीय रहा निरीक्षण, मीडिया को भी दो दिन बाद लगा पता
- ब्रह्मपुत्र नदी के बांध स्थल, ल्हासा के पोटाला पैलेस भी पहुंचे



चीन के राष्ट्रपति शुक्रवार को अचानक अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत के शहर निंगची के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न जातीय समूह ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। साभार : शिन्हुआ

बीजिंग, प्रेट्र : लद्दाख में भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत के शहर निंगची का अचानक दौरा किया। इस दौरे को गोपनीय रखा गया था। 20 जुलाई को चिनफिंग के दौरे की जानकारी मीडिया को दो दिन के बाद हुई।

किसी भी चीनी राष्ट्रपति की इस शहर में पहली यात्रा है। बुधवार को यात्रा के दौरान चिनफिंग ने निंगची नदी के पुल और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन का भी निरीक्षण किया। चीन ने यहां 14 वीं पंचवर्षीय योजना में एक बड़े बांध की परियोजना को स्वीकृति दी है। यह बांध भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत-चीन सीमा विवाद के बीच चिनफिंग की इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लद्दाख सीमा पर पिछले साल मई से विवाद चल रहा है।

वैसे तो इस क्षेत्र में चीनी अधिकारियों के दौरे होते रहते हैं। चीनी मीडिया में जारी एक वीडियो में तिब्बत के स्विटजरलैंड कहे जाने वाले निंगची में चिनफिंग लोगों अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं।

चिनफिंग ने यहां बुलेट ट्रेन में बैठकर क्षेत्र का जायजा लिया। वह तिब्बत की राजधानी ल्हासा भी पहुंचे। ल्हासा में उन्होंने पोटाला पैलेस, डेपुंग मठ और बरखोर स्ट्रीट का दौरा किया। पोटाला पैलेस दलाई लामा का परंपरागत स्थान है। पोटाला पैलेस के सामने चिनफिंग ने एक सभा कर लोगों को तिब्बती सरकार व सेना को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। चीनी राष्ट्रपति के तौर पर चिनफिंग का तिब्बत में यह पहला दौरा है। इससे पहले 2011 में उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने तिब्बत का दौरा किया था। भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगा निंगची शहर उस समय सुर्खियों में आया था, जब चीन ने यहां बुलेट ट्रेन शुरू की थी।

नीदरलैंड के अर्नहेम शहर ने चीनी शहर वुहान से रिश्ता तोड़ा

अर्नहेम, एएनआइ : नीदरलैंड की अर्नहेम सिटी का सिस्टर सिटी वुहान से सहयोग का रिश्ता टूट गया है। एनएल टाइम्स के अनुसार अर्नहेम की नगर परिषद ने बहुमत से मेयर की उस योजना के खिलाफ मतदान किया जिसमें वुहान के साथ संबंधों को जारी रखा जाना था। नीदरलैंड के कई प्रमुख दलों ने तत्काल प्रभाव से इन संबंधों को तोड़ने के लिए वोट किया। चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों ने कहा, चीन में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। उइगर मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इन हालात में चीन के शहरों से संबंध रखना अनैतिक होगा। डच संसद के निचले सदन ने भी उइगरों के अत्याचार को नरसंहार करार दिया है। नीदरलैंड के पचास से अधिक सांसदों ने डेमोक्रैट प्रस्तावों को आत्मसात किया है।

सीआइए में अब हो सकती है चीनी विशेषज्ञ की तैनाती

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआइए के निदेशक विलियम बर्न्स ने भू-राजनीतिक क्षेत्र में अमेरिका की बादशाहत को लेकर बड़ा बयान दिया है। बर्न्स ने कहा, 'अमेरिका को समझना होगा कि अब वो भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र में अकेला नहीं है। उसे चीन की ताकत समझनी होगी।'

एनपीआर को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में सीआइए के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि अमेरिकी खुफिया सेवा को अब बीजिंग के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीनी विशेषज्ञों को तैनात करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 'मैं चीन के विशेषज्ञों को आगे-तैनात करने के लिए अभी संभावनाएं तलाश कर रहा हूं। चाहे वह आपरेशनल अफसर, एक्सपर्ट, एनालिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट ही क्यों न हों। हमें प्रतिद्वंद्विता को और प्रभावी बनाने के लिए ऐसा करना होगा।' बर्न्स ने कहा कि 21वीं सदी में चीन, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी भू-राजनीतिक चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा क्षेत्र है।

अफगानिस्तान में सेना की तैनाती के मुद्दे पर सीआइए के निदेशक ने कहा कि अमेरिका अभी भी अफगानिस्तान और उसके आसपास आतंकवादी संगठनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की महत्वपूर्ण क्षमता रखता है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जाहिर करते हुए बर्न्स ने कहा कि तालिबान शायद 2001 के बाद अभी सबसे मजबूत सैन्य स्थिति में है।

भू-राजनीतिक ताकतों की बात करते हुए बर्न्स ने रूस के व्यापक प्रभाव पर भी टिप्पणी की।

▶ सीआइए के निदेशक बर्न्स ने कहा-चीन की ताकत समझनी होगी


विलियम बर्न्स फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

चीन में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 51 पहुंची

बीजिंग, प्रेट्र : चीन के हेनान प्रांत में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 51 पहुंच गई है। लापता हुए आठ लोगों का तीसरे दिन भी कोई पता नहीं चला है। राज्य मीडिया के अनुसार जबर्दस्त बारिश से काफी नुकसान हुआ है। झेंगझोऊ शहर में आठ हजार से ज्यादा सैन्यकर्मी राहत कार्य में लगे हुए हैं। बाढ़ से पांच प्रांतों के शहर प्रभावित हैं। अब राहत कार्य तेज किया जा रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त है। बारिश और बाढ़ से तीस लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नावों की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है।

सिंगापुर में हाल में मिले संक्रमितों में 75 फीसद वैक्सीन लेने वाले

▶ कारगर साबित हुई वैक्सीन, मरीजों में कम रहा संक्रमण का स्तर

सिंगापुर, रायटर : सिंगापुर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले चार हफ्ते के दौरान सामने आए नए मामलों में से 75 फीसद ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। हालांकि, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टीका लगवाने वाले किसी संक्रमित की हालत गंभीर नहीं हुई है। वहीं, ब्रिटेन और अमेरिका में फिर संक्रमण बढ़ने लगा है। खासकर ब्रिटेन में स्थिति ज्यादा गंभीर हो रही है।

सिंगापुर सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 28 दिनों के दौरान 1096 लोग स्थानीय स्तर पर ही संक्रमित हुए हैं। इनमें से 484 यानी 44 फीसद लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी, जबकि 30 फीसद ने एक डोज ली थी और 25 फीसद ने एक भी डोज नहीं ली थी।

इन आंकड़ों से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि वैक्सीन संक्रमण के गंभीर होने से रोकती है, लेकिन यह भी साफ है कि सिर्फ टीका लेने के बाद भी संक्रमण होता है। मतलब साफ है कि सिर्फ टीका ही पर्याप्त नहीं है, कोरोना से बचाव के अन्य उपायों को भी अपनाना होगा।

इस बीच, समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक ब्रिटेन में नए मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। यहां पिछले 24 घंटे में 39 हजार से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। ब्रिटेन में हाल ही में लाकडाउन में छूट दी गई है। इसके साथ ही डेल्टा वैरिएंट को लेकर सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। खाद्य सामग्री के स्टोर में ग्राहकों की संख्या बढ़ने के बाद सामान की कमी आने लगी है। इसको देखते हुए तमाम स्टोर में लगे दस हजार कर्मचारियों के लिए क्वारंटाइन के नियमों में ढील दी गई है, जिससे सप्लाई चेन को सामान्य रखने में मदद मिल सके।

अमेरिका में एक हफ्ते में 53 फीसद बढ़े केस : रायटर के अनुसार अमेरिका में पिछले कुछ सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह मरीजों की संख्या में 53 फीसद का इजाफा हुआ है। इनमें से अधिकांश मरीज डेल्टा वैरिएंट के हैं।

चीन के इन्कार के बाद डब्ल्यूएचओ का वायरस की जांच पर तालमेल का आग्रह

जिनेवा, रायटर : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चीन के उसकी प्रयोगशालाओं (लैब) में और सतर्कता बरतने व उसके बाजारों की निगरानी करने से इन्कार करने के बाद सभी देशों से कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने की अपील की है। ज्ञात हो, दिसंबर 2019 में वुहान शहर में पहली बार इंसानों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन चीन अपने यहां की लैब से वायरस लीक होने के सिद्धांत को नकारता आ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने इस माह चीन में कोरोना संक्रमण के उद्गम की जांच का मुद्दा उठाया था। चीन के उप मंत्री झेंग वाइजिंग ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता तारिक जासारेविक ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र को बताया कि यह राजनीति या दोषारोपण का विषय नहीं है। हमें मानव आबादी को बचाने के लिए इस महामारी को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है।


कैलिफोर्निया में सूखा, बंद हो सकते हैं बिजली संयंत्र
अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य बहुत गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। राज्य के कई जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से भी नीचे चला गया है। यहां पानी की कमी की वजह से 4.1 मिलियन एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है। ओरोविल झील में पानी एकदम तलहटी में पहुंच गया है। इस वजह से क्षेत्र में स्थित एडवर्ड हयात पावर प्लांट को अगले महीने और जलविद्युत संयंत्र को सितंबर में बंद किया जा सकता है। एएफपी

अमेरिका ने मोदी के स्वच्छ ऊर्जा अभियान का स्वागत किया

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के बावजूद भारत में स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को युद्धस्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और उनके प्रयासों का स्वागत किया है।

एक कांग्रेस कमेटी के समक्ष बयान जारी करने से पहले पर्यावरण परिवर्तन पर विशेष दूत के वरिष्ठ सलाहकार जोनाथन परशिंग ने अमेरिका और भारत मौसम के मामले में प्रतिबद्ध साझीदार हैं। परशिंग ने सांसदों से कहा कि हम भारत को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ ऊर्जा अभियान को आगे बढ़ाने के अथक प्रयासों का स्वागत करते हैं।

उन्होंने बताया कि विगत अप्रैल में दोनों सरकारों ने 'अमेरिका-भारत पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी' पर दस्तखत किए थे। इसी साझेदारी में दोनों पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और पर्यावरण कार्रवाई को लेकर 2030 के एजेंडे की पहचान की थी।

उन्होंने कहा कि मुख्य फोकस नियामक और बाजार की स्थितियों में सहयोग बढ़ाना है। ताकि भारत के 450 जीडब्ल्यू परिवर्तनीय ऊर्जा को हासिल करने का भारत का लक्ष्य होगा। अगर यह लक्ष्य हासिल होता है तो भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के साथ ही जीएचजी उत्सर्जन भी उपलब्ध होगा।

अमेरिका चीनी शोधकर्ता के वीजा फ्राड के आरोपों को वापस लेगा

स्कारमेंटो, एपी : अमेरिका ने एक चीनी शोधकर्ता के खिलाफ दायर अपना मुकदमा वापस ले लिया है। चीनी शोधकर्ता को चीनी सेना के साथ संबंधों की जानकारी वीजा आवेदन में नहीं देने के आरोप में उत्तरी कैलिफोर्निया की जेल में बंद किया गया था। उसे सोमवार को संघीय अदालत में पेश किया जाना था।

स्कारमेंटो की संघीय अदालत में दर्ज दस्तावेजों के अनुसार, जुआन तांग (37) पर लगे फर्जी वीजा आरोपों को खारिज करने के लिए उसके वकीलों ने जज से अपील की। लेकिन ऐसा करने की वजह नहीं बताई। सुनवाई सोमवार से शुरू होनी थी। स्कारमेंटो स्थित अमेरिकी अटर्नी आफिस की टिप्पणी भेजी गई, लेकिन जवाब नहीं मिला। तब उनके वकीलों मैलकम सीगल और टाम जानसन ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि डा. तांग को अपनी बेटी और पति के पास लौटने दिया जाएगा।

सैक्रामेंटो काउंटी जेल के रिकार्ड के अनुसार जुआन तांग (37) को अमेरिकी मार्शल सेवा ने गिरफ्तार किया है। न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को तांग और अमेरिका में रह रहे तीन अन्य वैज्ञानिकों के खिलाफ आरोपों की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के सदस्य के अपने दर्जे को छिपाया। सभी पर वीजा धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। तांग की गिरफ्तारी चारों में सबसे बाद में हुई है। इससे पहले न्याय मंत्रालय ने सैन फ्रांसिस्को में चीन के वाणिज्य दूतावास पर एक भगोड़े को शरण देने का आरोप लगाया था।

इस संबंध में जानकारी पाने के लिए महावाणिज्य दूतावास को किए गए ईमेल अथवा फेसबुक संदेश का कोई जवाब नहीं मिला।

न्याय मंत्रालय ने कहा कि तांग ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में काम करने की योजना के लिए पिछले साल अक्टूबर में जो वीजा आवेदन दिया था उसमें सेना के साथ अपने संबंधों के बारे में झूठ बोला था और इसके कई महीनों बाद एफबीआइ साक्षात्कार में भी इस बारे में झूठ बोला। एजेंट को तांग की तस्वीरें मिली हैं जिसमें वह सेना की वर्दी में है और चीन में लेखों की समीक्षा में सेना के साथ उसके संबंधों का पता चला है।


जुआन तांग फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

चीनी विद्रोहियों पर वार में शामिल नौ लोग वापस भेजेंगे

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार चीन के खुफिया अभियान 'फाक्स हंट' में शामिल उन लोगों जो चीनी सरकार के लिए जासूसी कर रहे थे उन लोगों को जबरन वापस भेजा जाएगा। इन नौ लोगों में चीनी नागरिकों और अमेरिकी जांच कर्ता भी शामिल हैं। वाशिंगटन टाइम्स के अनुसार इन पर चीन के अवैध एजेंट के तौर पर काम करने, अवैध तरीके से विद्रोहियों का पीछा करने और बीजिंग शासन की आलोचना करने जैसे आरोप हैं।

भारतीय अमेरिकी व्यवसायी कैलिफोर्निया से लड़ेंगी संसदीय चुनाव

वाशिंगटन, प्रेट्र : एक भारतीय-अमेरिकी इंजीनियर और उद्यमी ने घोषणा की है कि वह कैलिफोर्निया के एक कांग्रेस सीट वाले जिले से अमेरिकी प्रतिनिधिसभा के लिए चुनाव लड़ेगी।

रिवरसाइड में भारतीय अप्रवासी माता-पिता के घर पैदा हुई श्रिना कुरानी नवंबर 2022 में मध्यावधि चुनाव के लिए 15-अवधि के रिपब्लिकन अवलंबी केन कैल्वर्ट को चुनौती देंगी। कुरानी ने गुरुवार को कहा, 'मैं सीए-42 में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने वाली हूं! यह तथ्य आधारित समाधान और साहसिक कार्रवाई का समय है।' एक पहली पीढ़ी के अमेरिकी के रूप में, मेरे परिवार ने यहीं रिवरसाइड में एक सफल पूल आपूर्ति व्यवसाय बनाने के लिए एक साथ काम किया। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता ने वर्षों से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, लेकिन इन दिनों अक्सर इतनी हलचल भी पर्याप्त नहीं होती है। अवसर अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर हैं, जबकि कैरियर वाशिंगटन के केन कैल्वर्ट जैसे राजनेता खुद को, अपने राजनीतिक दलों और अपने कारपोरेट दाताओं की मदद करने पर केंद्रित हैं। कुरानी ने खुद को एक राजनेता ना बताकर एक इंजीनियर, उद्यमी और एक तथ्य-आधारित समस्या समाधानकर्ता के रूप में वर्णित किया है।

केन कैल्वर्ट 30 वर्षों से वाशिंगटन में हैं और उन्होंने बार-बार हमारे हित के खिलाफ मतदान किया है। कुरानी ने 16 साल की उम्र में ला सिएरा हाई स्कूल से स्नातक किया और यूसी रिवरसाइड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वर्तमान में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चार भारतीय अमेरिकी हैं - डॉ अमी बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल।

साइबर सिकनेस का शिकार बना रही टेक्नोलाजी



आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखने में उलझन हो रही है? या फोन देखने से चक्कर आ रहा है? हो सकता है कि आप इसे आंखों की थकान समझ रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लक्षण साइबर सिकनेस के हैं। वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और आग्मेंटेड रियलिटी (एआर) जैसी तकनीक और स्मार्टफोन व कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग ने इस नई बीमारी को जन्म दिया है। अमेरिका की आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की शोध छात्र एंजेलिका जेस्पर ने साइबर सिकनेस को लेकर कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं।

यह है वजह



व्यक्ति साइबर सिकनेस का शिकार तब होता है, जब आंखों को हो रहे अनुभव और वास्तविकता में अंतर होता है। वीआर और एआर डिवाइस के इस्तेमाल से इसका खतरा ज्यादा रहता है। वीआर डिवाइस का इस्तेमाल करते समय यूजर को आसपास कुछ नहीं दिखता है। ऐसे में आंखों को लगता है कि सब कुछ गतिमान है, जबकि शरीर एक जगह स्थिर होता है। यही असंतुलन साइबर सिकनेस का कारण बनता है। डिवाइस का इस्तेमाल करने के बाद ऐसे लोगों को सामान्य होने में बहुत समय लगता है।

न करें उभर रहे लक्षणों की अनदेखी

शुरुआत में साइबर सिकनेस के लक्षण सामान्य होते हैं और डिवाइस इस्तेमाल के बाद करीब 24 घंटे बीतते-बीतते ठीक हो जाते हैं। अगर अनदेखी की जाए तो समय के साथ लक्षण गंभीर होते जाते हैं। तेज सिरदर्द, आंखों में तनाव और चक्कर आने जैसे लक्षणों के कारण सामान्य दिनचर्या मुश्किल हो जाती है। कोई वाहन चलाते समय इन लक्षणों के प्रभाव में हो, तो दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। लक्षण की गंभीरता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है।

जरा सी सतर्कता में छिपी है बचने की राह

अगर कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर ज्यादा समय बिताना आपके काम का हिस्सा है और इस कारण से आप साइबर सिकनेस का शिकार हो रहे हैं, तो कुछ उपाय इससे राहत दे सकते हैं। स्क्रीन पर काम करते समय ब्लू कट लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करें। यह स्क्रीन से निकलने वाली कुछ किरणों को आंखों तक नहीं पहुंचने देता, जिससे आंखों का तनाव कम होता है। स्क्रीन पर फांट साइज बड़ा रखकर काम करना भी आंखों के लिए राहत की बात है। थोड़ी-थोड़ी देर पर आंखें बंद कर लेना और स्क्रीन से नजरें हटाकर आसपास देखना भी फायदेमंद है। (इनपुट : प्रेट्र)

पति अतानु की जगह जाधव के साथ बनी दीपिका की जोड़ी

क्वालीफिकेशन दौर के प्रदर्शन के आधार पर मिक्स्ड डबल्स जोड़ी का फैसला

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो ओलिंपिक तीरंदाजी मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में पति और अनुभवी तीरंदाज अतानु दास की जगह प्रवीण जाधव के साथ जोड़ी बनाएंगी और शनिवार को इस स्पर्धा में उतरेंगी। शुक्रवार को रैंकिंग राउंड के प्रदर्शन के आधार पर यह फैसला लिया गया। मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा ओलिंपिक में पहली बार खेली जा रही है और इसमें भारत को पदक मिलने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है।



रैंकिंग मुकाबले के दौरान निशाना साधती दीपिका कुमारी • रायटर

जाधव और दीपिका के संयुक्त स्कोर के आधार पर मिक्स्ड डबल्स में भारत को नौवीं रैंकिंग मिली है। भारत के पास दास और दीपिका का नाम भेजने का विकल्प था, जिन्होंने पेरिस विश्व कप में साथ में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय तीरंदाजी महासंघ (एएआइ) ने दास की जगह जाधव को चुना। एएआइ के वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 'मौजूदा फार्म के आधार पर जाधव का चयन किया गया। इसमें कोई राकेट साइंस नहीं है। जाधव नई प्रतिभा हैं और उम्मीद है कि दोनों साथ में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।'

इससे पहले दीपिका यहां ओलिंपिक रैंकिंग राउंड में अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाईं तो वहीं पुरुष तीरंदाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिससे भारत को मिक्स्ड जोड़ी में फेरबदल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। दीपिका 663 अंक के साथ नौंवे स्थान पर रहीं, जो उनके सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग स्कोर 686 से काफी कम है।

उम्मीद है कि भारतीय मिक्स्ड डबल्स जोड़ी आठवीं रैंकिंग की चीनी ताइपे की जोड़ी की चुनौती से निपटने के बाद क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीय कोरिया से भिड़ेगी। 2019 के बाद से ओलिंपिक की तैयारियों के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से दूर रहे कोरियाई तीरंदाज ने रैंकिंग राउंड में दबदबा बनाया।

अतानु, जाधव और तरुणदीप राय की भारतीय पुरुष टीम अच्छा स्कोर नहीं बना सकी और टीम रैंकिंग में बस किसी तरह से शीर्ष-10 में पहुंचने में सफल रही। भारत ने पुरुष और मिक्स्ड टीम रैंकिंग में एक समान नौंवा स्थान हासिल किया। पदार्पण कर रहे प्रवीण जाधव अनुभवी तीरंदाज दास (35वें स्थान) और राय (37वें स्थान) से आगे रहे। जाधव और दास का स्कोर समान 329 था, पर महाराष्ट्र का तीरंदाज अंतिम छह सेट में उनसे आगे निकल गया और उसने 720 में से 656 अंक जुटाए। एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता राय 37वें स्थान पर रहे। एलिमिनेशन दौर के मुकाबले 27 जुलाई को खेले जाएंगे। रैंकिंग दौर से एलिमिनेशन दौर की वरीयता का निर्धारण होता है और विरोधी भी तय होता है। तीरंदाजों को 70 मीटर की दूरी से निशाना लगाने के लिए 72 तीर दिए जाते हैं। उन्हें छह-छह तीरों की 12 सीरीज में निशाना लगाना होता है।

भारत के ओलिंपिक दल का प्रायोजक बना अदाणी ग्रुप

नई दिल्ली, (वि.) : अदाणी ग्रुप शुक्रवार को टोक्यो ओलिंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर भारतीय दल का प्रायोजक बन गया। अदाणी ग्रुप ने एक बयान जारी करके इसकी पुष्टि की। इसके अलावा अदाणी ग्रुप 'गर्व है' अभियान के तहत विश्व के नंबर एक मुक्केबाज अमित पंघाल, स्टार पहलवान दीपक पूनिया और महिला हाकी कप्तान रानी रामपाल सहित सात शीर्ष खिलाड़ियों की भी मदद कर रहा है। अदाणी ग्रुप का 'गर्व है' अभियान भारत के अगले बनने वाले चैंपियन खिलाड़ियों की पहचान करना है और उनकी मदद करना है।



हाथ में ओलिंपिक मशाल लिए जापान की नाओमी ओसाका • रायटर

रियो की कसक टोक्यो में दूर करना चाहेंगे निशानेबाज

टोक्यो, प्रेट्र : रियो ओलिंपिक में नाकामी के बाद से लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे भारतीय निशानेबाज टोक्यो में पदकों के साथ उस मलाल को मिटाने की कोशिश करेंगे और इस बार भारतीय दल से एक या दो नहीं बल्कि चार पदकों की उम्मीद है। यूं तो भारत के 15 निशानेबाजों में से सभी पदक जीतने में सक्षम हैं लेकिन, कुछ को सबसे प्रबल पदक उम्मीद माना जा रहा है। इनमें से एक सौरभ चौधरी हैं जिनका सामना ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से होना है। पहले दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में चौधरी और अभिषेक वर्मा भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में शनिवार को अपूर्वी चंदेला और इलावेनिल वलारिवन की तकदीर का भी फैसला होगा।

टेनिस में करना होगा चमत्कारिक प्रदर्शन

टोक्यो : भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को में पदक दौर के करीब जाने के लिए चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा क्योंकि सानिया मिर्जा और ओलिंपिक में पदार्पण कर रहीं अंकिता रैना को यूक्रेन के रूप में कड़ी चुनौती मिली है जबकि सिंगल्स वर्ग में सुमित नागल की राह भी आसान नहीं है। रिकार्ड चौथा ओलिंपिक खेल रही सानिया और पहली बार उतरी रैना ने इस साल एक भी प्रतिस्पर्धी मैच साथ नहीं खेला है।

अपने पदार्पण को यादगार बनाना चाहेंगे प्रणीत

टोक्यो : भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ओलिंपिक में स्वप्निल पदार्पण करना चाहेंगे जो अपना अभियान शनिवार को इजरायल के मिशा जिल्बरमैन के खिलाफ शुरू करेंगे। प्रणीत और चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज की पुरुष जोड़ी भी अपने अभियान का आगाज करेगी। ग्रुप-डी में शीर्ष पर रहने के लिए 13वें वरीय प्रणीत को नीदरलैंड्स के मार्क कालजोऊ को हराना होगा और फिर वह ग्रुप-सी के विजेता से भिड़ेंगे। पुरुष डबल्स में चिराग और सात्विक को मुश्किल ड्रा मिला है जिन्हें शनिवार को चीनी ताइपे के लीग यांग और वांग चि लिन की तीसरी रैंकिंग की जोड़ी से भिड़ना है। उन्हें ग्रुप चरण में इंडोनेशिया की शीर्ष वरीय जोड़ी से भिड़ना है।

नया अध्याय लिखना चाहेंगी भारोत्तोलक मीराबाई चानू

टोक्यो : पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू से पदक की उम्मीद है और यह भारतीय भी रियो ओलिंपिक के निराशाजनक प्रदर्शन को भुलाकर देश के भारोत्तोलन इतिहास में नया अध्याय लिखना चाहेंगी। चानू भारत के लिए 49 किग्रा में पदक की निश्चित दावेदार मानी जा रही हैं क्योंकि आठ महिलाओं भारोत्तोलकों में उनका 205 किग्रा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केवल चीन की होऊ जिहुई के 213 किग्रा के बाद दूसरे नंबर पर है। मणिपुर की यह भारोत्तोलक इस बार निश्चित रूप से नया अध्याय लिखना चाहेंगी जिसमें पदक शामिल हो। राष्ट्रीय कोच विजय शर्मा ने कहा, 'हमारे प्रतिद्वंद्वी चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया से हैं। हमने स्नैच पर काम किया है। लेकिन अन्य कैसा कर रहे हैं, वजन का फैसला इससे ही होगा।'

मुक्केबाजी अभियान की शुरुआत करेंगे विकास कृष्णन

टोक्यो, प्रेट्र : अनुभवी विकास कृष्णन (69 किग्रा) शनिवार को यहां स्थानीय प्रबल दावेदार सेवोनरेट्स विंकी मेनसाह ओकाजावा के खिलाफ भारत के मुक्केबाजी ओलिंपिक अभियान की शुरुआत करेंगे। विकास मुक्केबाजी स्पर्धाओं के शुरुआती दिन रिंग में उतरने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज होंगे और इसी वजह से उन्होंने उद्घाटन समारोह में नहीं जाने का फैसला किया। भारतीय मुक्केबाजों को पदक दौर तक पहुंचने के लिए कई चुनौतीपूर्ण बाधाओं को पार करना होगा।



खास बातें

- कोविड-19 का हवाला देते हुए ओलिंपिक से नाम वापस लेने वाले गिनी ने आइओसी के साथ व्यापक चर्चा के बाद अब अपने पांच सदस्यों के दल को भाग लेने की इजाजत दे दी
- टोक्यो ओलिंपिक और पैरालिंपिक की मशाल में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया।
- 1972 के म्यूनिख ओलिंपिक में फिलिस्तीनी बंदूकधारियों द्वारा मारे गए इजरायली ओलिंपिक टीम के सदस्यों को उद्घाटन समारोह के दौरान याद किया गया।

ओलिंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान टोक्यो नेशनल स्टेडियम का दृश्य • एएफपी

भारत के आज के मैच

पदक के मुकाबले

निशानेबाजी : महिला 10 मीटर एयर राइफल, क्वालीफिकेशन- सुबह पांच बजे से, फाइनल- सुबह 7:15 बजे से

- खिलाड़ी- इलावेनिल वलारिवन, अपूर्वी चंदेला
- पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल, क्वालीफिकेशन- सुबह 9:30 बजे से, फाइनल- दोपहर 12 बजे से
- खिलाड़ी : अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी

तीरंदाजी : मिक्स्ड टीम अंतिम-16, सुबह छह बजे से

- खिलाड़ी : दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव

भारोत्तोलन : महिला 49 किग्रा फाइनल- सुबह 10:20 बजे से

- खिलाड़ी : मीराबाई चानू

अन्य मुकाबले

हाकी : पुरुष टीम : पूल-ए, सुबह 6:30 बजे से, बनाम न्यूजीलैंड,

- महिला टीम : पूल-ए, शाम 5:15 बजे से, बनाम नीदरलैंड्स

टेनिस : पुरुष सिंगल्स, पहला दौर, सुबह 7:30 बजे से

- खिलाड़ी : सुमित नागल बनाम डेनिस इस्तोमिन

जूडो : महिला सिंगल्स, 48 किग्रा, अंतिम-32, सुबह 7:30 बजे से

- खिलाड़ी : सुशीला देवी बनाम इवा सेर्स्नोविजकी

रोइंग : लाइटवेट पुरुष डबल्स स्कल्स हीट-2 : सुबह : 7:30 बजे से,

- खिलाड़ी : अर्जुन लाल और अरविंद सिंह

टेबल टेनिस : मिक्स्ड डबल्स, अंतिम-16, सुबह 8:30 बजे से

- खिलाड़ी : मनिका बत्रा और अचंता शरत कमल।
- महिला सिंगल्स, दोपहर 12:15 बजे से
- खिलाड़ी : मनिका बत्रा बनाम हो तिन-तिन, सुतीर्था मुखर्जी बनाम लिंडा बर्गस्ट्राम।

बैडमिंटन : पुरुष डबल्स ग्रुप-ए, सुबह 8:50 बजे से,

- खिलाड़ी : सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी बनाम ली यांग और वांग ची-लिन
- पुरुष सिंगल्स ग्रुप-डी, सुबह 9:30 बजे से
- खिलाड़ी : बी साई प्रणीत बनाम मिशा जिल्बरमैन

मुक्केबाजी : पुरुष वेल्टरवेट अंतिम-32, स 3:54 बजे से,

- खिलाड़ी : विकास कृष्णन बनाम सिवोनरेट्स बनाम ओकाजावा

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

भारतीय टीम में ओलिंपिक पदक जीतने का दम

हाकी दिग्गजों ने माना, मनप्रीत की अगुआई वाली टीम खत्म कर सकती है 41 साल का सूखा

उमेश राजपूत • नई दिल्ली

ओलिंपिक में आठ स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य सहित कुल 11 पदक, खेलों के इस महाकुंभ में भारतीय हाकी के दबदबे और गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं। लेकिन, ये भी सच है कि 1980 के मास्को ओलिंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद से भारतीय हाकी टीम कभी कोई ओलिंपिक पदक नहीं जीत सकी। हालांकि, हाकी दिग्गजों का मानना है कि मनप्रीत सिंह की अगुआई में भारतीय टीम चार दशक से चले आ रहे हाकी में भारत के ओलिंपिक पदक के सूखे को खत्म करने की काबिलियत रखती है। भारतीय पुरुष हाकी टीम का पहला मुकाबला शनिवार को न्यूजीलैंड से होना है और इस मुकाबले का परिणाम काफी हद तक भारतीय हाकी टीम के आगे के सफर की राह तैयार कर देगा।

टोक्यो दूसरी बार ओलिंपिक की मेजबानी कर रहा है और जब पिछली बार 1964 में वहां ओलिंपिक हुए थे तो उस टीम में खेलने वाले हरबिंदर सिंह अब 78 साल के हो चुके हैं। फिलहाल वह हाकी इंडिया की चयन समिति के सदस्य भी हैं। जब उसने टोक्यो में भारत की संभावना के बारे में पूछा तो वह पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने कहा, 'हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ओलिंपियन बने और फिर पदक जीते। मेरे लिए ये दोनों सपने पहले ओलिंपिक में ही पूरे हो गए। टोक्यो में 1964 के ओलिंपिक में मैं टीम का सबसे जूनियर सदस्य था और हमने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था।' दुनिया के बेहतरीन सेंटर फारवर्ड में शुमार रहे हरबिंदर ने इस बार भारत की संभावना को लेकर कहा, 'हमने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी है। हमारे पास यह मौका है कि हम 1964 का इतिहास दोहराएं। हमारी टीम में इतनी क्षमता है कि उसे खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हम किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते, लेकिन हमें अपनी टीम पर भरोसा है।'

1975 विश्व कप में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हाकी टीम के कप्तान और दो बार ओलिंपिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य अजित पाल सिंह ने कहा, 'हमारी टीम पिछले कुछ सालों से बेहतर हुई है। ओलिंपिक में हमें मैच दर मैच अच्छा खेलना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमारी टीम में पदक जीतने की काबिलियत है, लेकिन हमारा पहला लक्ष्य सेमीफाइनल में पहुंचना होना चाहिए, क्योंकि एक भी खराब मैच हमें सेमीफाइनल में पहुंचने से रोक सकता है और बिना सेमीफाइनल में पहुंचे पदक नहीं जीता जा सकता। उसके बाद हमें पदक की कोशिश करनी चाहिए।' 1975 विश्व कप विजेता और 1972 के म्यूनिख ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे अशोक ध्यानचंद ने कहा, 'हमारी टीम पदक जीतने की क्षमता रखती है। पिछले दो साल से हमारी टीम अच्छा खेल रही है और उसने अंतिम समय में हारने की अपनी कमजोरी को भी दूर किया है। हमारी टीम में एक स्थायित्व आया है, रक्षापंक्ति मजबूत हुई है और मारक क्षमता बढ़ी है। हमें अपने खिलाफ गोल होने से रोकना होगा और गोल करने के मौके भुनाने होंगे, क्योंकि बिना गोल किए जीता नहीं जा सकता।'



भारतीय हाकी दिग्गज हरबिंदर सिंह, अजित पाल सिंह, अशोक ध्यानचंद • फाइल फोटो, प्रेट्र

टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय पुरुष हाकी टीम का कार्यक्रम

तारीख	बनाम
24 जुलाई	न्यूजीलैंड
25 जुलाई	आस्ट्रेलिया
27 जुलाई	स्पेन
29 जुलाई	अर्जेंटीना
30 जुलाई	जापान

> महामारी के दौर में मानसिक दृढता खेल में सफलता की कुंजी साबित होगी और इसमें भारतीय खिलाड़ियों का कोई सानी नहीं। पिछले 15-16 महीने काफी कठिन रहे और मुझे भारतीय खिलाड़ियों को करीब से समझने का मौका मिला। मुझे यकीन है कि इसी दृढता के दम पर वे कामयाबी की नई कहानी लिखेंगे।
>
> **ग्राहम रीड, कोच,** भारतीय पुरुष हाकी टीम

छाप छोड़ना चाहेगी महिला हाकी टीम

नई दिल्ली : भारतीय महिला हाकी टीम का ओलिंपिक में कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है व 36 वर्ष बाद रियो ओलिंपिक में उतरने के बाद एक भी मैच नहीं जीत पाने की टीस वह टोक्यो में यादगार प्रदर्शन के जरिये दूर करना चाहेगी। हालांकि पहले ही कदम पर उसे विश्व नंबर एक टीम नीदरलैंड्स से भिड़ना है। लगातार दूसरी बार ओलिंपिक में जगह बनाने वाली भारतीय महिला टीम ने पिछले कुछ समय में अपने अच्छे प्रदर्शन से उम्मीद जगाई है। रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज रानी रामपाल की टीम का पहला लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में प्रवेश होगा।

भारतीय हाकी टीम की राह आसान नहीं

धनराज पिल्लै कलम से



आखिरकार टोक्यो ओलिंपिक शुरू हो गए। मुझे चार बार ओलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, इसलिए मैं इसमें हिस्सा ले रहे एथलीटों का उत्साह, उनका नर्वस होना और उनके समर्पण को अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं भारतीय हाकी टीमों को लेकर बेहद उत्साहित और आशावान हूं, जिसकी अगुआई मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल कर रहे हैं। टीमों ने पांच साल से कड़ी मेहनत की है और अब अपनी चमक बिखेरने का मौका है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये टीमें देश को गर्व करने का मौका जरूर देंगी। भारतीय पुरुष हाकी टीम अपने अभियान का आगाज शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी जो आसान मुकाबला नहीं होगा। पूल-ए में भारतीय टीम गत चैंपियन अर्जेंटीना, पूर्व चैंपियन आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेजबान जापान और स्पेन के साथ है। भारत के सभी विरोधी काफी मजबूत हैं और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि टीम बहुत अधिक दूर की सोचने की बजाय एक बारे में एक ही मैच के बारे में सोचे। जहां अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया की गिनती बेहद मजबूत टीमों में होती है, वहीं घरेलू जमीन पर जापान को कम करके नहीं आंका जा सकता। घरेलू समर्थन किसी भी मैच में लाभ ही देता है। न्यूजीलैंड और स्पेन की टीमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से सजी हैं।

इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय टीम आसान चुनौती पेश करेगी। युवा व अनुभवी खिलाड़ियों से सजी ये टीम बेहद जोशीली है व पिछले कुछ साल में इसने कौशल व फिटनेस में काफी सुधार भी किया है। वक्त आ गया है जब सभी टीमों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने लाना होगा व बीते पांच साल की कड़ी मेहनत का एक-एक पल साबित करना होगा। शुभकामनाएं। (टीसीएम)

दैनिक जागरण
सप्तरंग
जोश नई राहों का
शनिवार, 24 जुलाई, 2021



हमेशा सीखते रहें, यदि आप नहीं सीखते हैं तो आप उपयोगी चीजें करना बंद कर देते हैं। -सत्य नडेला

बैंकिंग सेवा में अधिकारी बनने का मौका



नाबार्ड भर्ती-2021

अनुज जिंदल
सीईओ, अनुज जिंदलडॉटइन

महत्वपूर्ण तिथियां

- कुल पदों की संख्या: 162
- आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अगस्त, 2021
- आनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (चरण 1): यह परीक्षा अगस्त, 2021 के आखिरी सप्ताह से सितंबर, 2021 के पहले सप्ताह के मध्य आयोजित होगी।
- वेबसाइट: www.nabard.org

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर ऐंड रूरल डेवलपमेंट/नाबार्ड) की ओर से ग्रेड ए और बी अधिकारी पदों के लिए कुल 162 रिक्तियां निकाली गई हैं। इनमें 155 रिक्तियां ग्रेड ए अधिकारी पदों के लिए हैं, जिनमें 148 पद ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा (आरडीबीएस) स्ट्रीम के लिए, पांच पद राजभाषा सेवा स्ट्रीम के लिए तथा दो पद प्रोटोकाल और सुरक्षा सेवा स्ट्रीम के लिए है।

ग्रेड बी पदों के लिए सात रिक्तियां हैं, जो आरडीबीएस स्ट्रीम के लिए हैं। नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी, दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट 7 अगस्त, 2021 तक इसके लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए इस भर्ती प्रक्रिया की तारीखों और पदों की जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जानते हैं:

नाबार्ड ग्रेड ए: नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रेड ए पद पर सहायक प्रबंधक के रूप में कैंडिडेट की नियुक्ति की जाएगी। नाबार्ड के सहायक प्रबंधक के जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यान्वयन और निगरानी जैसी चीजें शामिल हैं। इस पद का शुरुआती सकल मासिक वेतन 66,864 रुपये है। इस राशि में ग्रेड ए अधिकारी को मिलने वाले सभी भत्ते भी शामिल हैं। इस पद का मूल शुरुआती मासिक वेतन 28,150 रुपये के लगभग है। इस मूल वेतन के अलावा ग्रेड ए के अधिकारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, छुट्टी जैसे विभिन्न भत्ते भी मिलते हैं।

नाबार्ड ग्रेड बी: ग्रेड बी प्रबंधक का पद है। इस पद के अंतर्गत लेखांकन प्रक्रियाओं की निगरानी, ग्राहक संबंध बनाए रखने जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं। ग्रेड बी अधिकारियों को मिलने वाला शुरुआती सकल मासिक वेतन 73,600 रुपये है। वहीं, इस पद का मूल मासिक वेतन 35,150 रुपये के लगभग है। इस पद पर ग्रेड ए पद के समान ही अन्य भत्ते देय हैं।

आयु सीमा: एक जनवरी, 2021 को आपकी आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए यानी परीक्षा देने में सक्षम होने के लिए आपकी जन्मतिथि दो जनवरी, 1990 से एक जनवरी, 2000 के बीच होनी चाहिए।

शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम योग्यता स्नातक है। पद के अनुसार योग्यता संबंधी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें।

प्रदर्शन से ही पाएंगे कामयाबी

कोरोना की चुनौतियों के बीच टोक्यो ओलिंपिक की शुरुआत हो गई है। भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ियों को खेलों के इस महाकुंभ की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। जुनूनी खिलाड़ियों को मेडल से ज्यादा अपने बेहतर प्रदर्शन की परवाह होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि वे अपना सौ फीसद देंगे तो पदक आएंगे ही। जीवन में कामयाबी पाने का भी यही फार्मूला है। सपने देखने और परिणाम पर फोकस करने के बजाय हम अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दें, तो कामयाबी मिलेगी ही, बता रहे हैं अरुण श्रीवास्तव...



फोटो: इमेजेज बाजार

एक्स्ट्रा शाट

उम्र 38 वर्ष। तीन बच्चों की मां। छह बार की विश्व चैंपियन। वर्तमान विश्व रैंकिंग तीन। 2012 के लंदन ओलिंपिक की कांस्य पदक विजेता। संभवतः आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, यह सब मणिपुर की महिला मुक्केबाज एमसी मेरी कोम के बारे में है। लेकिन खास बात यह है कि इतना कुछ हासिल कर लेने के बावजूद उनका सपना इस ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर अपना और अपने देश का नाम रौशन करने का है। यही कारण है कि इस उम्र में भी मुक्केबाजी के रिंग में उतरने के उनके जज्बे में जरा भी कमी नहीं आई है। उन्हें अपनी क्षमता और प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है। उधर, हरियाणा की 26 साल की महिला पहलवान विनेश फोगाट हैं, जो 2016 के रियो ओलिंपिक में घुटने की चोट के चलते पदक नहीं जीत सकी थीं। तब से उनके दिल में यह कसक बनी हुई है। यह उनके प्रदर्शन की जिद ही है कि चोट से ठीक होने के बाद हर प्रतियोगिता में प्रतिद्वंद्वी को धूल चटाते हुए आज उनकी विश्व रैंकिंग नंबर वन है। टोक्यो ओलिंपिक में गये भारतीय दल में ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं, जिनमें अपने प्रदर्शन को लेकर भरपूर जिद और जुनून है। इनमें महिला निशानेबाज मनु भाकर (19 साल, विश्व रैंकिंग 2) व इलावेनिल वलारिवान (21 साल, विश्व रैंकिंग 1), पुरुष निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार (18 साल, विश्व रैंकिंग 2) व अमित पंघाल (25 साल, विश्व रैंकिंग 1), पहलवान बजरंग पूनिया (27 साल, विश्व रैंकिंग 1) जैसे नाम प्रमुख हैं। कोरोना की वजह से ओलिंपिक में एक साल का विलंब होने के बावजूद इन खिलाड़ियों के हौसले में कोई कमी नहीं आई है, उलटे अपने प्रदर्शन को लेकर उनका निश्चय और दृढ़ हो गया है। जाहिर है जब वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, तो देश के लिए पदक जीतेंगे ही।

सपने हों व्यावहारिक: जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जरूरी होता है। चाहे पढ़ाई हो या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी या फिर नौकरी हासिल करने और उसमें तरक्की की बात ही क्यों न हो, यदि आप अपनी पसंद से जुड़े लक्ष्य को अच्छी तरह समझ कर उसे हासिल करने की दिशा में सही तरीके से कड़ी मेहनत करेंगे, तो कामयाबी भी मिलेगी और तरक्की भी। अक्सर युवा सपने तो बड़े देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए जिस मेहनत की दरकार होती है, उसे अनदेखा कर देते हैं। प्रयासों में गंभीरता की कमी होने के कारण ही उन्हें कामयाबी से वंचित रह जाना पड़ता है। करियर को लेकर सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर ऐसे सपनों को बुनने से पहले अपनी रुचि और सक्षमता को भी जरूर देख लें। यदि किसी दूसरे को देखकर, उससे प्रभावित होकर आपने भी कोई सपना देख लिया, तो जरूरी नहीं कि उसमें आपको कामयाबी मिल ही जाए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको वह सपना प्रभावशाली लगा हो, लेकिन जब आप उसे हासिल करने की दिशा में प्रयास शुरू करते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद मन का न होने के कारण उसके प्रति आप गंभीर नहीं रह पाते। इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि आप जो भी सपने देखें या लक्ष्य तय करें, वह आपकी पसंद का होना चाहिए। तभी आप उसमें जुनून की हद तक डूब सकेंगे और मंजिल हासिल कर सकेंगे।

प्रयासों में न हो कमी: एक बार किसी सपने को लक्ष्य बना लेने के बाद उसे पाने की दिशा में कदम बढ़ाना होता है। ये कदम कई चरणों में हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी लक्ष्य झटके में या कम प्रयासों में हासिल करना लगभग असंभव होता है। इसके लिए धैर्यपूर्वक लगातार प्रयास करना होता है। आवश्यक संसाधन भी जुटाने पड़ सकते हैं। अच्छी तरह से सारी तैयारियां कर लेने के बाद जब आप मैदान में आत्मविश्वास और मनोबल के साथ उतरते हैं, तो जीत की संभावना अधिकतम होती है। हां, हो सकता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भी आपको कामयाबी से वंचित रह जाना पड़े। इससे हताश होने के बजाय आप यह देखें कि कहीं आपके प्रयास में कोई चूक तो नहीं हो गई। यह भी हो सकता है कि आपकी तुलना में दूसरे की तैयारी कहीं ज्यादा अच्छी रही हो, जिससे वह आपसे आगे निकलने में कामयाब हो गया। दोनों ही स्थितियों में आपको अपने प्रदर्शन और चूकों-गलतियों पर विचार करने के साथ दूसरे की सफलता में छिपे कारणों को भी तलाशने की जरूरत है। इसके बाद खुद को दुरुस्त करके अगर आप दोगुने उत्साह से फिर मैदान में उतरते हैं, तब आपका प्रदर्शन बेदाग और विजेता बनाने वाला हो सकता है।

समय रहते लें यू-टर्न: अगर आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने और पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में ठहरकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हो सकता है कि आपकी तुलना में दूसरे कहीं ज्यादा सक्षम हैं, जिसकी वजह से आप भरपूर प्रयास के बावजूद अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। यह स्थिति पढ़ाई की स्ट्रीम को लेकर भी हो सकती है और किसी प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में भी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समय जाया करने और निराश-हताश होने के बजाय अपनी रुचि के किसी दूसरे क्षेत्र की तलाश करें और उसमें खुद को निखारने-संवारने का जतन करें। हो सकता है कि उसमें आपको अपेक्षित कामयाबी मिल जाए। यदि आपने अपने पहले वाले लक्ष्य को पाने के लिए साल-दर-साल लगा दिए और नतीजा शून्य ही रहता है, तो जीवन का यह कीमती समय यूं ही जाया हो जाएगा और आपको हासिल भी कुछ नहीं होगा। इससे बेहतर यही है कि यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में दो-तीन साल पूरे दम-खम से प्रयास करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाती, तो दूसरे विकल्प को अपनाने में देर न करें।



परिणाम नहीं, कर्म पर करें फोकस

जो छात्र पूरे साल पढ़ाई करते हैं, परीक्षा आने पर उन्हें तनाव का कतई सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। चूंकि उन्होंने समूचे पाठ्यक्रम की तैयारी की होती है, इसलिए वे सहज बने रहते हैं। अपने प्रदर्शन को लेकर उनमें भरपूर आत्मविश्वास होता है। प्रश्न चाहे जहां से पूछे जाएं, उन्हें परवाह नहीं होती। हालांकि ज्यादातर परीक्षार्थियों के साथ होता यह है कि परीक्षा आते ही उनके हाथ-पांव फूलने लगते हैं। इसका मतलब यही है कि उन्होंने पूरी तन्मयता, ईमानदारी और निरंतरता बनाए रखते हुए तैयारी नहीं की। आइएएस जैसी परीक्षाओं के साथ भी यही है। अधिकतर अभ्यर्थी आवेदन तो कर देते हैं, परीक्षा की चिंता भी हमेशा करते रहते हैं, लेकिन सही दिशा में तैयारी को लेकर कभी गंभीर नहीं हो पाते। परिणाम यह होता है कि साल-दर-साल परीक्षा देने के बाद भी उन्हें कामयाबी से वंचित रहना पड़ता है। कामयाबी और पहचान के लिए कर्म सबसे ज्यादा आवश्यक होता है।

प्रभावी संवाद कला की जरूरत



लाइफ स्किल

डॉ. अनिल सेठी
(मोटिवेटर एवं लाइफ कोच)

जीवन में कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व है। रोजाना सुबह उठने से लेकर सोने तक हम किसी न किसी से बात करते हैं। इसी कम्युनिकेशन से हमारे करियर की राह तय होती है। यही हमारी सफलता या असफलता का कारण भी बनता है। यह बात मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाना चाहता हूं। मेरे एक मित्र अपने विवाह के कुछ महीनों बाद मुझसे मिले और कुछ परेशान से लग रहे थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगे कि आपकी भाभी (उनकी पत्नी) कुछ ऊंचा सुनती हैं, इसी बात से वह परेशान हैं। मैं उनको लेकर अपने पारिवारिक डाक्टर के पास गया। उनकी समस्या को सुनने के बाद डाक्टर ने पूछा कि कितनी दूर से उनको सुनाई नहीं देता है? मनीष ने कहा ऐसा तो कभी ध्यान नहीं दिया। डाक्टर ने कहा यह पूरी तरह से ठीक होने वाली समस्या है, लेकिन आप पहले मुझे बताएं कि कितनी दूर से उन्हें सुनाई देता है और कितनी दूर से नहीं। मनीष ने कहा कि वह इसका अंदाजा लगाकर जल्दी वापस आएंगे और घर चले गये। मनीष घर जाते ही जोर से पत्नी को आवाज देकर बोले, जो उस समय किचन में खाना बना रही थीं, कि भागवान खाने में क्या बनाया है। जब थोड़ी देर तक जवाब सुनाई नहीं दिया, तो दो कदम आगे बढ़कर फिर से प्रश्न दोहराया, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर मनीष ने किचन के दरवाजे पर पहुंचकर जोर से प्रश्न दोहराया, तब गुस्से से भरी आवाज में पत्नी बोली-अरहर की दाल और आलू की सब्जी, सुनाई नहीं देता क्या चार बार बता चुकी हूं? इसका मतलब पत्नी तो हर बार जवाब दे रही थीं लेकिन मनीष को ही सुनाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब डाक्टर की जरूरत पत्नी को नहीं, बल्कि स्वयं मनीष को ही थी। इससे एक सीख मिलती है कि जब भी हमें किसी से कोई शिकायत हो, तो उसकी समीक्षा ठंडे दिमाग से करनी चाहिए और इसलिए कम्युनिकेशन में लिसनिंग (सुनना) एक बहुत जरूरी पहला कदम है। आप सोचिये, अगर भगवान चाहते कि हम लोग बोलें ज्यादा और सुनें कम, तो शायद दो मुंह और एक कान देते लेकिन ऐसा नहीं है। जब कम्युनिकेशन गैप होता है, तो हम पूरी सचाई जाने बिना अपने मन से कुछ भी सोच लेते हैं। एक रिसर्च बताती है कि कारपोरेट वर्ल्ड में 60 फीसद प्राब्लम कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है। इसलिए अगर हम अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें तो घर परिवार और कार्य क्षेत्र, हर जगह सफलता पा सकते हैं। इसी पर एक बहुत पुरानी कहावत है-ऐसी बानी बोलिये मन का आप खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय।



सीखें बोलने का सही ढंग

अक्सर हम आवेश में आकर कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन शब्द जब तक हमारे मन के अंदर है, तब तक वह हमारे अधीन है और एक बार हमने बोल दिए तो हम अपने शब्दों के गुलाम हो जाते हैं। यह एक कटु सच्चाई है कि हम लोग जीवन में दो साल की उम्र तक बोलना सीख लेते हैं, लेकिन कई बार पूरे जीवन में यह नहीं सीख पाते कि बोलना क्या और कैसे है।

बाधाओं से जूझ कर बढ़ते हैं आगे



सक्सेस मंत्रा

अंकिता जैन
सह-संस्थापक गो पैसा डाट काम

देश की लोकप्रिय कैशबैक एवं कूपन साइट है गो पैसा डाट काम, जो आनलाइन खरीदारी (ई-कामर्स, ट्रैवल संबंधी एवं अन्य) पर अतिरिक्त कैशबैक आफर करती है यानी कंपनी आनलाइन ब्रांड्स से मिलने वाले कमीशन का 80 से 90 फीसद कैशबैक के रूप में सीधे ग्राहकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इस प्लेटफार्म से एक हजार से अधिक ब्रांड्स जुड़े हैं, जिनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, अजियो, वनएमजी, मेकमाईट्रिप, मामाअर्थ, मैन कंपनी शामिल हैं। अब तक इस एप के पांच लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। कंपनी की सह-संस्थापक एवं मार्केटिंग हेड अंकिता जैन कहती हैं कि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन्हें सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वही एक दिन सफलता की सीढ़ी बनती है। इन दिनों महामारी के दौरान भी हमें नये सिरे से अपनी रणनीति पर काम करना पड़ा। इसलिए युवाओं से कहना चाहूंगी कि जोखिम से डरें नहीं।

अंकिता सूरत (गुजरात) में जन्मीं और पली-बढ़ी हैं। संयुक्त परिवार था इनका। दादी चाहती थीं कि शादी हो जाए और वह अपने घर की जिम्मेदारी संभालें। इस दौरान इन्होंने वीएनएसजी यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में एमबीए किया। हालांकि, वह रेडियो जाकी बनना चाहती थीं। पढ़ाई के साथ-साथ कई रेडियो स्टेशंस पर अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी की। पहले इंटर्न के रूप में काम किया और फिर एक एफएम रेडियो में रेडियो जाकी भी बनीं। अंकिता बताती हैं, 'मुझे अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिला। लेकिन कुछ अपना करने, नया बनाने का आकर्षण भी हमेशा से रहा है। इसी ने उद्यमिता की ओर जाने के लिए प्रेरित किया, जो शादी के बाद संभव हो सका। मैंने अपने पति अमन (जिनकी फाइनेंस पृष्ठभूमि है) के साथ कुछ आइडियाज पर विचार-विमर्श किया। हमने देखा था कि भारतीय कैसे बचत को लेकर गंभीर होते हैं। लेकिन तब देश में कैशबैक का कांसेप्ट नहीं आया था। अमन ने ब्रिटेन में इस पर काम किया था और फिर 2012 में 'गोपैसा' की शुरुआत हुई।'

कठिन रहे शुरुआती दौर: शुरुआती दो साल अंकिता एवं इनकी टीम के लिए बेहद कठिन रहे। वह कहती हैं, 'मैं सिर्फ 23 वर्ष की थी। लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते थे। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि समय के साथ अब यह मार्केट ग्रो कर रहा है। रोजाना दो से तीन हजार यूजर्स हमारे प्लेटफार्म से जुड़ते हैं। विगत वर्षों में 50 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक दिया है। कई शीर्ष आनलाइन रिटेलर्स का दावा है कि इससे उनके बिजनेस को 12 से 20 फीसदी तक का फायदा हुआ है।' अंकिता इंटरनेट मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कई सफल मार्केटिंग अभियान चला चुकी हैं, जिसका फायदा कंपनी को हुआ है और वह अपनी एक पैठ बना सका है।

छोटे शहरों में भरा है टैलेंट: अंकिता की मानें, तो अब तक के सफर में इन्होंने यही सीखा है कि बड़े संस्थानों की डिग्री वालों की नियुक्ति के पीछे न भागें। टियर 2 एवं 3 शहरों में अच्छी योग्यता रखने वाले बहुतेरे काबिल युवा हैं, जिनमें न सिर्फ जुनून है, बल्कि आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को हासिल करने की भूख भी है। हमारे सबसे वरिष्ठ टेक सहयोगी किसी शीर्ष संस्थान से नहीं हैं, लेकिन वे अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में किसी के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, उन्हें परास्त कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मेरी टीम, मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो निरंतर मुझे सहयोग देती है। मुझे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम साथ में विकास करें और नई ऊंचाइयों को छू सकें।

बातचीत: अंशु सिंह



फोटो: इमेजेज बाजार

जुनून से मिलती है सफलता

कारोबार में नाकामियां, उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। अंकिता के पास भी ऐसे अनुभवों की कमी नहीं रही। वह कहती हैं, 'पहले ब्रांड्स को कनविंस करने में मुश्किल आती थी। यहां तक कि कर्मचारियों को भी कंपनी के विजन में विश्वास दिलाने में समय लगा। लेकिन मैंने कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि खुद से ही एक अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने का निर्णय लिया था। अभी भी मुश्किल वक्त में कई बार पीछे हटने का खयाल आ जाता है, लेकिन कुछ करने का जुनून थामे रखता है और मैं आगे बढ़ती रहती हूं।' अंकिता का मानना है कि एक उद्यमी को अपनी कमियों एवं गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ना होता है।

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 24 जुलाई, 2021 शनिवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का राशिफल।
आज का राहुकाल: प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: पूर्व।
आज का पर्व एवं त्योहार: व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा।

कल 25 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: पश्चिम।
पंचक: रात्रि के 10:48 बजे से प्रारंभ 30 जुलाई को दोपहर 02:02 बजे पर समाप्त।
विशेष: बुध कर्क में।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तत्पश्चात् द्वितीया श्रवण नक्षत्र तत्पश्चात् धनिष्ठा नक्षत्र आयुष्मान योग तत्पश्चात् सौभाग्य योग मकर में चंद्रमा तत्पश्चात् कुंभ में।

मेष: महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रही परेशानी दूर होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

वृष: पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नए संबंध बनेंगे।

मिथुन: किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कर्क: धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। सावधानी जरूर बरतें। जीवनसाथी का सहयोग एवं सान्निध्य मिलेगा।

सिंह: भावुकता में नियंत्रण रखें। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं।

कन्या: व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

तुला: आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी।

वृश्चिक: संतान या शिक्षा की दिशा में सफलता मिलेगी। सृजनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। उदर विकार या त्वचा का रोग कष्ट दे सकता है।

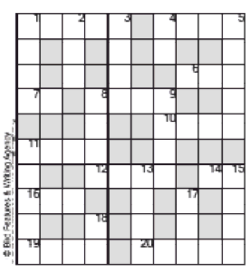
धनु: किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें। रचनात्मक कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। आर्थिक प्रगति होगी।

मकर: व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टदायी होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। नए संबंध बनेंगे।

कुंभ: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीवनसाथी का सहयोग रहेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

मीन: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यक्ति विशेष के कारण तनाव मिलेगा। संयम से काम लेना हितकर होगा।

वर्ग पहेली-1646



© Bitz Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
1 तालिका [6]।
4 [illegible], ताजा [2,2]।
6 [illegible] [3]।
7 दृढ़, [illegible] [2]।
8 जिस औरत का पति जीवित हो [4]।
10 बड़ा तकिया [4]।
11 [illegible] [2,2]।
12 बड़े [illegible] [4]।
14 [illegible] [2]।
16 [illegible] [3]।
19 [illegible] [4]।
20 रथ हांकने वाला, सारथी [5]।

ऊपर से नीचे
1 कई आकार का [4]।
2 लगातार, निरंतर [3]।
3 [illegible] [4]।
4 [illegible] [2]।
5 पेटी, बेल्ट [5]।
8 सुंदर, [illegible] [4]।
9 [illegible] [4]।
11 किसी वस्तु को तुरा लेना [2,3]।
13 [illegible] [4]।
15 [illegible] [4]।
17 [illegible] [3]।
18 आभास, प्रतीति, दीप्ति [2]।

कल का हल

अ	क	र्म	क		आ	त्म	नु	त्तां	त
का							त्ता		रा
ल	ह	क	नां		सं		का		श
मु			सा	हि	त्य	का	र		ना
त्यु		रं	नि			न			
			न			भी	य		सं
दं		तं	र	क	दा	र			म
र		र		र्ज		नीं	स	म	झ
क		की							दा
नीं	क	ब	चा	ना		नि	शा	च	र

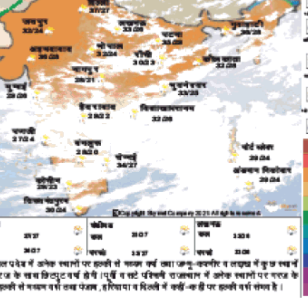
जागरण सुडोकू-1646

1			4					3
8		6		3		1	2	
	3			1				9
3			7				1	
	6			5	1	3		4
		1	3				8	
6			5		9	4		1
	7						6	
4		3		6			5	

कल का हल

9	2	6	4	3	1	8	5	7
1	3	4	8	5	7	9	2	6
7	5	8	6	2	9	1	3	4
5	8	9	2	6	4	7	1	3
3	4	7	5	1	8	6	9	2
2	6	1	9	7	3	4	8	5
6	9	5	7	8	2	3	4	1
4	1	2	3	9	6	5	7	8
8	7	3	1	4	5	2	6	9

मौसम



हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छिटपुट वर्षा होगी। पूर्वी व सटे पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा संभव है।

बोफोर्स घोटाले के विरोध में आधे विपक्ष ने लोकसभा से दिया इस्तीफा

1989 में आज ही लोकसभा में 70 से ज्यादा विपक्षी सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। बोफोर्स तोप खरीद के मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर घोटाले के आरोप लगे थे। इस पर विरोध जताने के लिए विपक्ष ने सामूहिक इस्तीफे का यह कदम उठाया था।





भारत की पहली महिला ग्रैंडमास्टर बनीं एस विजयलक्ष्मी

शतरंज की खिलाड़ी एस विजयलक्ष्मी वर्ष 2000 में आज ही 21 साल की उम्र में देश की पहली महिला ग्रैंडमास्टर बनी थीं। 1979 में जन्मीं विजयलक्ष्मी ने सात साल की उम्र में अपना पहला शतरंज टूर्नामेंट खेला था। उन्होंने लगभग हर नेशनल एज ग्रुप टाइटल जीता है।

भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय रहे हैं मनोज कुमार



पूरब और पश्चिम, क्रांति, उपकार और शहीद जैसी देशभक्ति फिल्मों में अभिनय कर भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय हुए अभिनेता मनोज कुमार का जन्म 1937 में आज ही एबटाबाद में (अब पाकिस्तान में) हुआ था। इनका नाम हरिकिशन गिरि गोस्वामी था। दिलीप कुमार की फिल्म शबनम में उनके किरदार के नाम से प्रेरित होकर इन्होंने अपना नाम मनोज कुमार कर लिया था। 1992 में इन्हें पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

इधर-उधर की

नकली पैरों पर चलना सीख रहा जर्मन शेफर्ड



जन्म से ही नहीं हैं दोनों पिछले पंजे। इंटरनेट मीडिया

फ्लोरिडा, एजेंसी : टेक्नोलाजी ने मनुष्यों ही नहीं, अन्य जीवों के लिए भी बेहतर जीवन के रास्ते खोले हैं। फ्लोरिडा का एक मामला इसी की बानगी है। यहां जन्म से ही अविकसित पिछले पंजों के साथ पैदा हुए जर्मन शेफर्ड प्रजाति के एक कुत्ते को एनिमल हेल्थ एंड रिहैब सेंटर वाले नकली पैरों पर चलना सिखा रहे हैं। यह जर्मन शेफर्ड अप्रैल में इस सेंटर में लाया गया था। इसके लिए विशेषतौर पर कृत्रिम पैर तैयार किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जन्म से ही उछल-उछलकर चलने की आदत के कारण उसे नकली पैरों के साथ चलने में मुश्किल हो रही है। इसलिए उसे इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है।

समुद्र में फैला तेल सोख लेगा सुपर काटन

तलाशी राह ▸ भाभा रिसर्च सेंटर के नवाचार से दुनिया लड़ेगी पर्यावरण व जैव विविधता बचाने की जंग

मुंबई, प्रेट्र : समुद्र में फैले तेल से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से पूरी दुनिया जूझ रही है। दुनियाभर में समुद्री मार्गों से ढुलाई के दौरान किन्हीं वजहों से कच्चा तेल समुद्र में कई किलोमीटर तक फैल जाता है। इससे आर्थिक नुकसान के साथ स्थानीय समुद्री जीवों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडराने लगते हैं। इस संकट से निपटने के लिए भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर (बार्क) ने काटन आधारित एक ऐसा सुपर एब्जार्बेंट (अवशोषक) बनाया है, जो पानी में फैले तेल को पूरी तरह सोख लेगा। इसमें रेडिएशन टेक्नोलाजी प्रयोग हुई है। संस्थान के आइसोटोप और रेडिएशन एप्लीकेशन डिवीजन में काम करने वाले विज्ञानी सुधेंदु रे चौधरी ने इसे बनाया है। इस तरह का सुपर एब्जार्बेंट बड़ी मात्रा में बनाने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की गई है। इसमें केवल मौसम के अनुसार परिवर्तन और आवश्यकता के अनुसार भंडारण किया जा सकेगा। यह प्रौद्योगिकी एक निजी कंपनी को हस्तांतरित की जा चुकी है।

बता दें कि विश्व भर में तेल की अधिकांश मात्रा का परिवहन समुद्री मार्ग से होता है। भारत में कच्चे तेल की मांग का 70 फीसद समुद्री मार्ग से आयात होता है।

▸ रेडियो टेक्नोलाजी का प्रयोग कर बनाया गया सुपर एब्जार्बेंट

▸ बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए निजी कंपनी को हस्तांतरित की प्रौद्योगिकी



समुद्र में जहाजों से होने वाला तेल रिसाव पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे नुकसानदेह माना जाता है। (फाइल)। एएफपी

तेल रिसाव की बड़ी घटनाएं

2010 में मैक्सिको की खाड़ी में करीब चार लाख टन तेल का रिसाव हुआ था। इससे प्लवक से लेकर डाल्फिन तक हजारों प्रजातियों की मौत हो गई थी।

2020 जुलाई में जापान के एक जहाज से तेल रिसाव होने से मारीशस का नीला समुद्र काला पड़ गया था।

1978 में फ्रांस के ब्रिटनी में कच्चे तेल का एक बड़ा जहाज फंस गया था। इससे करीब 70 मिलियन गैलन तेल समुद्र में चला गया था।

1 ग्राम काटन पानी में फैले 1.5 किलो तेल को अवशोषित कर सकता है

कपास बायोडिग्रेडेबल है और इसे 50 से 100 बार इस्तेमाल किया जा सकता है

2019 में इस नवाचार को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय से राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है

2020 दिसंबर में मिल चुका है पेटेंट

अन्य जगहों पर भी कर सकते हैं प्रयोग

इस अवशोषक का प्रयोग औद्योगिक या नगरपालिका अपशिष्ट जल से जहरीले कार्बनिक पदार्थों को हटाने में भी किया जा सकता है। इसका उपयोग ऐसे किसी भी उद्योग में हो सकता है जहां की सतह किन्हीं वजहों से तैलीय हो जाती है। सड़क मार्ग से पेट्रोल-डीजल की ढुलाई के दौरान किसी हादसे में तेल फैल जाने की सूरत में इसका इस्तेमाल सड़कों पर भी किया जा सकता है।

वर्तमान में ऐसा कोई अवशोषक नहीं है जो पानी की सतह पर तैरते तेल और पानी के नीचे बैठे सेडीमेंट आयल को एक साथ सोख सके।
-एके मोहंती, निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र



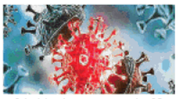
तांबे की ऐतिहासिक खदान...

पश्चिमी रोमानिया के रोसिया मोंटाना में स्थित इस ऐतिहासिक तांबे की खदान को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के लिए स्थानीय लोगों के समूह ने बीड़ा उठाया है। कम्युनिस्ट शासन काल के दौरान यहां अंधाधुंध खनन किए जाने से प्रकृति का यह दुर्लभ खजाना बर्बाद हो गया था। रोसिया मोंटाना खदान यूरोप में कहीं भी पाए जाने वाले तांबे का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। कहा जाता है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में एक अरब टन से अधिक अयस्क है। एएफपी

कुपोषण से कोरोना के गंभीर होने का खतरा

अनुसंधान

कुपोषण का शिकार लोगों के लिए कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कुपोषित बच्चों और वयस्क दोनों में ही कोरोना संक्रमण के बाद वेंटिलेटर पर जाने या मृत्यु की आशंका अन्य स्वस्थ लोगों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। यह सर्वविदित है कि कुपोषित लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बीमारियों के होने का खतरा ज्यादा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति में उसके असर पर इससे पहले कोई अध्ययन नहीं किया गया था।



जारी है कोरोना से जंग। फाइल/इंटरनेट मीडिया

साइंटिफिक रिपोर्ट्स में यह अध्ययन प्रकाशित किया गया है। कैलिफोर्निया के ओरेंज काउंटी स्थित बच्चों के अस्पताल में पांच साल से ऊपर के बच्चों और 18 से 78 साल के वयस्कों पर यह अध्ययन किया गया है। इसमें कुपोषित बच्चों और कुपोषण की पृष्ठभूमि वाले वयस्क दोनों ही शामिल किए गए। इनकी तुलना सामान्य लोगों पर कोरोना वायरस के प्रभाव से की गई। दोनों का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि कुपोषण की पृष्ठभूमि वाले लोगों पर सामान्य लोगों की अपेक्षा कोरोना ने घातक असर किया। कुपोषित बच्चों और वयस्कों के संक्रमण का शिकार होने के बाद मैकेनिकल वेंटिलेटर पर जाने या मरने वालों की संख्या सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा रही। कुपोषित और सामान्य दोनों लोगों पर ये अध्ययन साथ-साथ किए गए थे। शोध में शामिल अस्पताल के शोधकर्ता डा. लुईस ने बताया कि इस अध्ययन में 8,604 बच्चों और 94,495 वयस्कों को शामिल किया गया था। -आइएएनएस

फिल्म रिव्यू

★★☆ (ढाई स्टार)

14 फेरे

प्रमुख कलाकार : कृति खरबंदा, विक्रांत मेस्सी, गौहर खान, जमील खान, विनीत कुमार, यामिनी दास
निर्देशक : देवांशु सिंह
अवधि : एक घंटा 51 मिनट
डिजिटल प्लेटफार्म : जी5

हल्के-फुल्के अंदाज में जातिवाद का मुद्दा



भारतीय हिंदू परंपरा में सात फेरे लेकर शादी होती है। अगर शादी को दो बार किया जाए तो 14 फेरे हुए। यह फिल्म जातिवाद के मुद्दे पर है, जिसमें विजातीय जोड़े दो बार रीति-रिवाज के मुताबिक फेरे लेते हैं। हालांकि इस शादी को लेकर गढ़े गए प्रसंग बीच-बीच में हालात के चलते गुदगुदाते भी हैं। बिना भाषणबाजी के रुढ़िवादी सोच पर प्रहार भी करते हैं।

दिल्ली में एक ही कंपनी में कार्यरत संजय लाल सिंह (विक्रांत मेस्सी) और अदिति (कृति खरबंदा) कालेज के समय से एक-दूसरे से मुहब्बत करते हैं। दोनों का परिवार अंतरजातीय विवाह के सख्त खिलाफ है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले संजय की बहन अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। वहीं, जयपुर से ताल्लुक रखने वाली अदिति परिजनों के डर से शादी करके अमेरिका में बसने के लिए संजय पर दबाव बनाती है, लेकिन बहन के भागने से संजय अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। नौकरी के साथ स्टेज पर नाटक करने वाला संजय शादी के लिए जुगाड़ निकालता है। वह नकली माता-पिता की मदद से अपनी शादी का फुलप्रूफ कार्यक्रम बनाता है। इसमें उसका साथ थियेटर के साथी और ऑफिस के सहकर्मी देते हैं।

जातिवाद का विषय हिंदी सिनेमा के लिए नया नहीं है। मनोज कलवानी द्वारा लिखित '14 फेरे' में सोशल कॉमेडी के माध्यम से जातिवाद, आनर किलिंग और दहेज जैसे मार्मिक विषयों को उठाया गया है। इसमें बिना खून-खराबे के जातिवाद की बेड़ियों को रेखांकित करने का प्रयास हुआ है। फिल्म का आगाज समुचित तरीके से होता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसका पूर्वानुमान आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि जिंदगी की असल जटिलताओं को कहानी में प्रदर्शित नहीं किया गया है। पर्दे पर संजय और अदिति को देखकर लगता है कि सब कुछ सहजता से परीकथा की तरह आसानी से हो रहा है। परिवार का कट्टरवादी रवैया कचोटता नहीं है। अच्छी बात यह है कि जातिवाद पर केंद्रित प्रेम कहानी का अंत दुखद नहीं है।

कलाकारों की बात करें तो फिल्म का खास आकर्षण विक्रांत मेस्सी हैं। 'हसीन दिलरुबा' में सिरफिरे पति के किरदार में नजर आए विक्रांत यहां पर सीधे-सादे प्रेमी के किरदार में जंचे हैं। कृति खरबंदा शादी के परिधानों में बेहद खूबसूरत दिखी हैं। सफल करियर और आत्मनिर्भर लड़की का उनका किरदार पर्दे पर उतना सहज नहीं लगता। लेखन स्तर पर भी दिक्कत है। यही वजह है कि उनका किरदार विश्वसनीय नहीं बन पाया है। फिल्म में खुद को दिल्ली की मैरिल स्ट्रीप बताने वाली जुबीना (गौहर खान) नकली मां के किरदार में जमती हैं। शादी की तैयारियों और फैमिली ड्रामा के बीच बनी '14 फेरे' साफ-सुथरी हल्की-फुल्की मनोरंजक फिल्म है। गीत-संगीत कहानी के साथ सुसंगत है, लेकिन वह यादगार नहीं बन पाया है। -स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

'डर तो नहीं, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास होता है'



रोहित की आगामी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज का इंतजार कर रही है। इंस्टाग्राम

फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन फिल्मों की जब बात होती है तो रोहित शेट्टी का जिक्र होता है। सिंघम, सिंबा जैसी एक्शन फिल्में बना चुके रोहित का मानना है कि एक्शन फिल्में बनाना आसान काम नहीं है। इन फिल्मों को बनाते हुए डर से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। दैनिक जागरण से बातचीत में रोहित ने कहा कि चाहे फिल्म हो या खतरों के खिलाड़ी शो हो, मुझे डर किसी चीज से नहीं लगता है, लेकिन हां जब मैं किसी फिल्म या शो के लिए स्टंट शूट कर रहा होता हूं और कोई एक्टर या प्रतियोगी मेरे सामने होता है तो यकीनन मुझे खुद पर एक जिम्मेदारी का एहसास जरूर रहता है कि हर कोई सुरक्षित रहे। शो पर जितने भी स्टंट होते हैं, सब एडवांस में प्लान किए हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं होस्ट हूं तो शो पर क्या हो रहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं होगी। मुझे पता होता है कि कैसे वह स्टंट होने वाला है। प्रतियोगियों के आने से पहले वह स्टंट हम खुद ट्राई करते हैं। देखते हैं कि सुरक्षा के नजरिये से वह स्टंट कितना सही है। फिर उसमें जो कमियां होती हैं, उन्हें ठीक किया जाता है। रोहित की आगामी फिल्म सूर्यवंशी होगी, जो फिलहाल थिएटर के बंद होने की वजह से रिलीज के इंतजार में है। इसके अलावा रोहित अपनी एक और फिल्म सर्कस पर काम कर रहे हैं।

जब सोनाक्षी ने भाइयों के साथ लाइव चैट में कहा, शादी के सवाल न पूछें

दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। ऐसी ही बेबाकी उन्होंने दिखाई जब वह इंस्टाग्राम लाइव पर जुड़ीं अपने भाइयों लव और कुश के साथ। दरअसल, सोनाक्षी और उनके दोनों भाइयों ने मिलकर हाउस आफ क्रिएटिविटी नाम से एक प्लेटफार्म शुरू किया है, जहां हर तरह के आर्टिस्ट अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इस लाइव के दौरान तीनों ने यूजर्स से इस प्लेटफार्म से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहा, लेकिन इसी के साथ लव और सोनाक्षी ने यूजर्स को एक चेतावनी दे दी कि कोई भी सवाल पूछें, लेकिन शादी से जुड़े सवाल न पूछें, क्योंकि यहां हम शादी के बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। हालांकि, इस चेतावनी के बाद भी यूजर्स सोनाक्षी से शादी को लेकर सवाल पूछते रहे। इस लाइव चैट के बीच रणवीर सिंह भी आ गए। उन्होंने सोनाक्षी से पूछा कि क्या मैं एक स्टिक (छड़ी) की तस्वीर बनाकर भेज सकता हूं। इस पर सोनाक्षी ने हंसते हुए कहा कि हां जरूर, आप भेज सकते हैं। हम सोचेंगे उस तस्वीर के बारे में। सोनाक्षी ने आगे बताया कि उनकी बनाई हुई एक पेंटिंग बिक गई है। वह अक्सर अपनी बनाई पेंटिंग की झलक इंटरनेट मीडिया पर दिखाती रहती हैं। सोनाक्षी ने कहा कि मैं एक रचनात्मक परिवार से हूं। मैं पेंटिंग्स बनाती हूं, लव और कुश फोटोग्राफी करते हैं। दरअसल, मैंने उन दोनों की खींची हुई तस्वीरें देखने के बाद ही स्केच बनाना शुरू किया था। हालांकि, इस लाकडाउन के दौरान मैंने इस शौक को एक स्तर ऊपर ले जाने के बारे में सोचा। वक्त लगा समझने में की मेरा अपना स्टाइल क्या है।



सोनाक्षी एक्टिंग के साथ पेंटिंग में भी हैं माहिर। इंस्टाग्राम

पेशेवर मुक्केबाजों ने हमें ऐसे पीटा जैसे कि हम कोई पंचिंग बैग हों : दर्शन कुमार

अपने किरदारों की तैयारियों के लिए कभी-कभी कलाकारों को दर्द से होकर भी गुजरना पड़ता है। हालांकि, बाद में वह किरदार लोगों के सामने आने और उसके लिए सरहना पाने के बाद दर्द एक सुखद अनुभव में बदल जाता है। कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं हालिया रिलीज फिल्म तूफान में मुक्केबाज धर्मेश पाटिल के किरदार में नजर आए अभिनेता दर्शन कुमार। एक लाइव चैट के दौरान दर्शन ने अपनी तैयारियों को लेकर बताया, 'जब मुझे इस फिल्म का प्रस्ताव मिला तो मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उस समय मुझे इस फिल्म की तैयारी के लिए सिर्फ डेढ़ महीने का वक्त मिला था। इस फिल्म के लिए मेरी तैयारी बाक्सिंग (मुक्केबाजी) की ट्रेनिंग से शुरू हुई। 15-20 दिनों तक बाक्सिंग की ट्रेनिंग के बाद अमेरिकी मुक्केबाज डोरेल फास्टर आए। उन्होंने पंच मारने की एक्टिंग करने की जगह वास्तव में पंच मारना सिखाया। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग ज्यादातर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों के साथ हुई। उन्होंने हमें ऐसे पीटा जैसे कि हम कोई पंचिंग बैग हों। हालांकि, पंच मारने के बाद वे सारी बोल देते थे, लेकिन पड़ती बहुत अच्छे से थी। कभी मुंह सूजा हुआ होता था तो कभी पूरे शरीर पर मुक्कों के काले-नीले निशान होते थे, लेकिन फिर भी कुछ नया सीखने में हमें मजा आ रहा था। इस फिल्म के इंटरवल के बाद दिखाया गया है कि मेरी एक आंख काम नहीं करती है। इस सीन को करने के लिए मैंने वास्तव में कई दिनों तक अपनी एक आंख पर पट्टी बांधकर रखी थी। यहां तक कि जो लेंस मैंने लगाया था, उससे भी नजर नहीं आता था।'



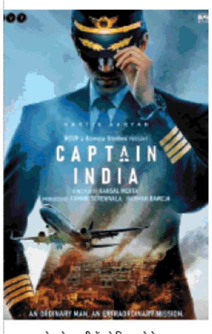
तूफान में धर्मेश पाटिल के किरदार में नजर आए दर्शन। इंस्टाग्राम

मुझे कोई गंभीरता से लेता ही नहीं : सुमित राघवन



धारावाहिक वागले की दुनिया : नई पीढ़ी नए किस्से में राजेश वागले का किरदार निभाते हैं सुमित। सौ. टीम सोनी सब

कई बार दर्शकों के दिमाग में कुछ कलाकारों की ऐसी छवि बन जाती है कि दर्शक उन्हें उस छवि से अलग देखना ही नहीं पसंद करते हैं। पिछले करीब ढाई दशक से टीवी और फिल्मों में सक्रिय अभिनेता सुमित राघवन की भी उनके कामेडी किरदारों की लोकप्रियता की वजह से कुछ ऐसी ही छवि है। हाल ही में उनके धारावाहिक वागले की दुनिया : नई पीढ़ी नए किस्से ने 100 एपिसोड पूरे किए। इस मौके पर आयोजित वर्चुअल कान्फ्रेंस में सुमित ने कामेडी किरदारों के प्रति अपनी दिलचस्पी को लेकर कहा, 'मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। अगर कभी मैं गंभीर भी हो जाता हूं तो लोग हंसने लगते हैं। मैं थोड़ी अलग तरह की कामेडी पसंद करता हूं। मुझे कामेडी सीन के दौरान एक्शन करने की जगह रिएक्शन (प्रतिक्रिया देने) में ज्यादा मजा आता है। रिएक्शन देने में स्वाभाविक अभिनय होता है।' वहीं, अपने धारावाहिक के बारे में सुमित का कहना है, 'किसी भी धारावाहिक या शो के सीक्वल में काम करने पर कलाकारों पर बहुत दबाव होता है। सीक्वल से मूल शो के दर्शकों की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जिस पर कलाकारों के साथ निर्माताओं और निर्देशकों को भी खरा उतरना पड़ता है। हम इस शो में किसी भी प्रकार का दोहराव नहीं करना चाहते थे। इसीलिए हमारी कोशिश उन्हीं किरदारों के साथ अलग-अलग कहानियां दिखाने की होती हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 100 एपिसोड में करीब 90 अलग-अलग कहानियां दिखाई जा चुकी हैं।'



युद्धरत क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के अभियान पर केंद्रित होगी फिल्म • इंस्टाग्राम

धर्मा प्रोडक्शंस और रेड चिलीज की फिल्मों से हटने के बाद कार्तिक ने हाल में दो फिल्मों का एलान किया है।

अगली फिल्म में कैप्टन बनेंगे कार्तिक

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म दोस्ताना 2 और शाह रुख खान के बैनर रेड चिलीज की फिल्म से बाहर होने के बाद अभिनेता कार्तिक आर्यन ने कुछ सप्ताह के अंतराल में ही दो नई फिल्मों की घोषणा की है। फिल्मकार हंसल मेहता के साथ कार्तिक के काम करने की खबरें पिछले काफी दिनों से चर्चा में थीं। शुक्रवार को कार्तिक ने हंसल के निर्देशन में बन रही अपनी अगली फिल्म कैप्टन इंडिया का आधिकारिक एलान किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया, जिसमें कार्तिक एक पायलट की वर्दी में नजर आ रहे हैं। इसके साथ लिखा है, 'एक साधारण आदमी, असाधारण मिशन पर।' इस फिल्म की कहानी किसी युद्धरत देश में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की वास्तविक घटना से प्रेरित है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म का निर्माण रॉनी स्क्रूवाला और हरमन बावेजा साथ काम कर रहे हैं। कार्तिक ने कहा, 'कैप्टन इंडिया एक प्रेरणादायक और रोमांचक फिल्म है। हमारे देश की ऐसी ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। हंसल सर के काम का मैं बहुत सम्मान करता हूं और यह फिल्म उनके साथ जुड़ने का सबसे उपयुक्त मौका था।' बता दें कि इससे पहले कार्तिक ने समीर विद्वांस के निर्देशन में बन रही फिल्म सत्यनारायण की कथा की घोषणा की थी। विवादों में आने के बाद निर्माताओं ने फिल्म का नाम बदलने का एलान किया था। इसके अलावा कार्तिक आगामी दिनों में धमाका और भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।

बिग बास ओटीटी शो को होस्ट करेंगे करण जौहर

टेलीविजन पर सलमान खान कई वर्षों से रियलिटी शो बिग बास को होस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफार्म पर आने वाले शो बिग बास ओटीटी को होस्ट करेंगे फिल्ममेकर करण जौहर। यह शो वूट प्लेटफार्म पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा। करण की बात करें, तो शो की होस्टिंग उनके लिए नई बात नहीं है। निर्माता-निर्देशक होने के साथ ही करण अपने शो काफी विद करण की होस्टिंग भी कर चुके हैं, जहां वह कई सितारों के इंटरव्यू ले चुके हैं। बिग बास ओटीटी शो टीवी पर आने से छह हफ्ते पहले तक वूट प्लेटफार्म पर चलेगा, इन छह हफ्तों की होस्टिंग की कमान करण संभालेंगे। आठ अगस्त से शो की स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। एक घंटे के इस एपिसोड में दर्शकों को शो के एक्सक्लूसिव फुटेज और 24 घंटे घर के भीतर की लाइव एक्टिविटीज देखने का मौका भी मिलेगा। छह हफ्ते के बाद यह शो कलर्स चैनल पर आ जाएगा, जिसे बिग बास सीजन 15 के तौर पर लांच किया जाएगा। खबरों के मुताबिक बिग बास ओटीटी शो में शामिल होने वाले सितारों में कई सनसनीखेज नाम और जाने-माने चेहरे होंगे। फिल्म की बात करें, तो करण लंबे वक्त बाद निर्देशन में भी वापसी कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्म राकी और रानी की प्रेम कहानी का एलान किया है।



टीवी से छह हफ्ते पहले डिजिटल प्लेटफार्म पर आएगा शो • इंस्टाग्राम

दो फिल्मों के लिए साथ काम कर रहीं दीपिका

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद निर्माताओं में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट जल्द पूरे कर लेने की होड़ मची है। ऐसे में कलाकारों को सभी निर्माताओं को वक्त देने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से बाजीराव मस्तानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी गुजर रही हैं। दीपिका कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मुंबई में लाकडाउन से पहले शाह रुख खान अभिनीत फिल्म पठान और शकुन बत्रा के निर्देशन में बन रही अनाम फिल्म के एक-एक शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर चुकी थीं। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक, अब शूटिंग का काम फिर से पटरी पर लौटने के साथ एक ओर उन्होंने पठान की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ रितिक रोशन अभिनीत फाइटर के लिए लगातार हो रही बैठकों और स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में भी हिस्सा ले रही हैं। साथ-साथ वह अपनी अन्य फिल्मों के निर्माताओं से भी बराबर संपर्क में हैं। फाइटर की शूटिंग अगले साल के शुरुआती महीनों से शुरू करने की योजना है। पठान और फाइटर के अलावा दीपिका आगामी दिनों में हालीवुड फिल्म द इंटर्न की हिंदी रीमेक, प्रभास के साथ एक फिल्म और शकुन बत्रा की एक फिल्म में नजर आएंगी। द इंटर्न की हिंदी रीमेक की अभिनेत्री होने के साथ-साथ दीपिका इसको प्रोड्यूस भी कर रही हैं।



सात साल बाद पठान में फिर शाह रुख के साथ काम कर रही हैं दीपिका • इंस्टाग्राम

निर्देशन की क्षमता मुझमें नहीं है : विद्या बालन



कई कलाकार हैं जो अभिनय के साथ-साथ निर्देशन करने में भी माहिर हैं। कोंकणा सेन शर्मा से लेकर कंगना रनोट, सनी देओल, सीमा पहावा तक कई कलाकर निर्देशक की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। वहीं शार्ट फिल्म नटखट से निर्माता बनी विद्या बालन फिलहाल निर्देशक बनने के बारे में नहीं सोच रही हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में विद्या ने बताया कि न मुझे निर्देशन करने की इच्छा है, न वह क्षमता है कि मैं एक पूरी फिल्म का भार खुद के कंधों पर उठाऊं। मैं अभिनय से इतना प्यार करती हूं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगी, जिसमें मेरा ध्यान अभिनय से हटकर दुसरी तरफ जाए। मैं दरअसल, सेट पर इन चीजों में नहीं पड़ना चाहती हूं कि कैमरा कहां लगाना है, सेटअप कैसे करना है, फ्रेम कैसा होना चाहिए। जहां तक निर्माता बनने की बात है, तो वह भी बाय चांस ही हुआ है, क्योंकि मुझे निर्माता बनने की जरूरत नहीं है। घर पर पहले से ही सिद्धार्थ (विद्या के पति सिद्धार्थ राय कपूर) निर्माता के तौर पर मौजूद हैं। एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मुझे खुद पर नहीं चाहिए।

« शार्ट फिल्म नटखट से प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं विद्या • इंस्टाग्राम